11.04 hrs.

CONSTITUTION (FORTY-FOURTH AMENDMENT) BILL—*contd.*

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as amended, be passed".

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as amended, be passed".

Now, before I call upon the non. Members, I have to suggest that since today's debate is on the third reading, the scope being limited, the speeches should not be too long. I have received a very large number of requests from hon. Members to participate in the debate. So, in order to accommodate all of them, I would suggest to the hon. Members to confine their speeches to, say five minutes. The scope is very limited and you cannot go into the details.

PROF. S. L. SAKSENA (Maharajganj): The Opposition Members should get proportionate time.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj): Sir, I would suggest that those who have not at all taken part in the debate should be given more time.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अभी तो हमने अपनी लिस्ट भेजी नहीं है ।

MR. SPEAKER: Therefore I say that the speeches should be short. They have to be relevant and short.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta—North-East): Not wishing particularly to speak myself, may I submit that this is an important constitutional Amendment and we have the whole day for the third reading? There are certain fundamental, even philosophical, aspects of the matter which may have to be brought up at this stage before the House. If the hon. Members wish to do so, I hope, the Chair would not withhold the opportunities in this regard.

श्री रामचन्द्र विकल (बागपत) : संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल आश्वासन दिया था कि संशोधन वापिस ले लो, बहस मत करो, कल आपको टाइम मिलेगा । तो उन लोगों को टाइम मिलना ही चाहिए ।

MR. SPEAKER: First of all, I propose to call those Members who have not so far spoken on the Bill. That will be the first category. The second category will comprise of those hon. Members whom I had requested not to speak on Clauses 57 and 59. I will give them more time on the third-reading. That was my promise. If they want to participate in the debate, I will call them. Then I will call those Members who have not spoken on the first-reading and after that I will call other Members, if there is time.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): Mr. Speaker, Sir, may I respectfully submit, while I appreciate all what you have said, the fact nonetheless remains that a very few of us on the non-Governmental benches are actually present in the House and, therefore, those of us who have chosen to remain present and participate should not be debarred from third-reading speeches altogether. My point is that the dissenting voices are fewer and the supporting voices are many more. Therefore, it would be in fairness to the debate and in the fitness of parliamentary traditions that those who are to say something against the Bill are given proportionately more time. I am not asking for a big chunk of time. I

hope this axe of time-limit will not fall on those who will stand up and speak against this Bill and explain its philosophical, political, moral, legal and Constitutional aspects, to say why they are opposed to the Bill.

MR. SPEAKER: Even philosophical, moral or other intellectual approach should not call for a very long speech. And the whole burden of my suggestion is that nobody should be debarred and if Members cooperate and if they confine themselves, of course, to relevant matters, I think I will be able to accommodate all the Members.

श्री डी० एन० तिवारी : (गोपालगंज) : अध्यक्ष जी, आज से 27-28 वर्ष पहले कांस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ था । समय इतनी तेजी से बदल रहा है कि कल की बात आज पुरानी हो जाती है । 27-28 वर्ष पहले की बात आज पुरानी हो जाये, इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है । डेवलप्ड-नेशन्ज का मैक-अप करने के लिये डेवलपिंग कन्ट्रीज को बहुत तेजी से आगे बढ़ना है और बढ़ने का प्रयास भी किया जा रहा है । जो सोश्यो-एकानोमिक चेन्जेज हुए हैं, तो उस पैटर्न के अनुसार हम ने विधान में संशोधन नहीं किये तो हम पीछे रह जायेंगे और जनता हम को उठा कर पीछे फेंक देगी ।

अभी आपने देखा कि इन संशोधनों पर बहुत से संशोधन सदस्यों की तरफ़ से आये । सरकार भी इस बात को मानती है कि संविधान में बहुत सारे परिवर्तनों की जरूरत है, इसलिये मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सरकार को इस मौके पर कोई कान्प्रीहैन्सिव बिल लाना चाहिये था, पूरी गम्भीरता के साथ संविधान का अध्ययन करना चाहिए था, किन-किन सेक्शन्ज को बदलना है, किन-किन को नहीं बदलना है, सब बातों को सामने रख कर काम करना चाहिये था, लेकिन मुझे इफ़सोस है कि सरकार ने ऐसा नहीं किया । आज जो संशोधन किये गये हैं, मेरा ऐसा ख्याल है कि उन से कहीं अधिक दूसरी धाराओं में संशोधन करने जरूरी थे । सरकार ने पहली गलती जो यह की कि पिछली लोक सभा में इस विधेयक को यहां पेश कर दिया, दो महीने बाद इस अधिवेशन में इस को पास कर दिया । उचित यह था कि उसी वक्त एक सीलैक्ट कमेटी बना दी जाती और इन सारे मजमूनों को उस सिलैक्ट कमेटी को सौंप दिया जाता, वह कमेटी इस पर विचार करती, और जिन अन्य धाराओं में संशोधन करना था, उन को भी इस कमेटी में लिया जाता और वह सिलेक्ट कमेटी दो महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती थी । इस तरह से इस बिल पर बाहर भी बहस हो जाती और सदन में भी बहस हो जाती। जल्दी की इस में कोई बात नहीं थी, क्योंकि लोक सभा का जीवन बढ़ने वाला था । ऐसी बात तो थी नहीं, कि आप ने लोक सभा का जीवन बढ़ाने के लिये कोई स्पर-आफ दि-मोमेन्ट पर फैसला लिया हो, गवर्नमेंट के दिमाग में यह बात पहले से होगी, इसलिये इस बिल के बारे में बहुत ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं थी । इस को ज्यादा समय दिया जाना चाहिये था, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट 15 नवम्बर के बाद आती, जिस में तमाम संशोधनों पर विचार किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, पता नहीं वे क्यों इतनी जल्दी इस को पास करना चाहते थे ।

इस बिल पर हाउस में जितना डिस्कशन हुआ है, मैं यह तो नहीं कहता कि उचित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी-जल्दी में हुआ है । 600-700 अमेंडमेंट्स को चार-पांच दिनों के अन्दर समाप्त कर देना कोई आसान बात नहीं है । हमारे स्पीकर साहब और पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर

[श्री डी० ए० तिवारी]

बार बार कहा करते थे कि जल्दी समाप्त करो, निश्चित समय के अन्दर ही इस को पूरा करना है, इसलिये जितना ध्यान इस पर दिया जाना चाहिये था, उतना नहीं दिया जा सका । अब यह बिल आज पास हो जायेगा, राज्य सभा में भी इस में कोई संशोधन नहीं होगा, क्योंकि अगर वहां कोई संशोधन मन्जूर करते हैं तो उसे फिर यहां लाना पड़ेगा, इसलिये यह इसी रूप में पास हो जायेगा । इसलिये मेरा अनुरोध है कि अब चूंकि इस हाउस की लाइफ एक वर्ष बढ़ रही है, इस बीच में हमें उन तमाम संशोधनों को ले आना चाहिये, जिन का लाया जाना बहुत जरूरी है, जिन के बिना हमारा काम अधूरा रह जायगा । अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जिस गति से हम चलना चाहते हैं, उस गति से नहीं चल सकेंगे । जितनी अमेंडमेंटस हुई हैं, उन में कुछ ऐसी धारायें हैं जिन में कुछ में कुछ और जोड़ा जाना चाहिये था । जैसे एक अमेंडमेंट था कि राष्ट्रध्वज के साथ यदि कोई मनमानी की बात करे तो उस को सजा मिले, इसी तरह की अमेंडमन्ट राष्ट्र भाषा के लिये भी होनी चाहिये थी, लेकिन उस अमेंडमेंट को नहीं लाया गया । राष्ट्र ध्वज हमारे देश का सिम्बल है, उसी तरह से राष्ट्र भाषा देश की दूसरी सिम्बल है, जो हिन्दुस्तान में लिंक-भाषा का काम करती है—इस संशोधन को न लाने से एक कमी रह गई है जिस को जरूर पूरा किया जाना चाहिये ।

इसी तरह से जो ड्यूटीज निर्धारित की गई हैं उन में भी कुछ बातें जोड़े जाने से रह गई हैं तथा कुछ ऐसी बातें जोड़ दी गई हैं जो रिडन्डेन्ट मालूम होती है । इस लिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे और इसी वर्ष के अन्दर उन संशोधनों को यहां पेश करे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप का इशारा समझ रहा हूं कि आप और अधिक समय नहीं देना चाहते हैं और मैं अधिक नहीं कहूंगा लेकिन मैं दो बातें ही कहना चाहता हूं कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है और राष्ट्र आगे बढ़ रहा है । इसलिए उस की एस्पीरेशन्स के अनुसार सब धाराओं को देख कर जिन जिन में बदलने की जरूरत है आज की स्थिति में, उन को बदलना चाहिए और अब जो आप बिल लावें, उस को सेलेक्ट कमेटी में भेजें ताकि वहां पर पूरी तरह से छानबीन हो सके । आप यह देखें कि 32वां एमेंडमेंट बिल संविधान के संशोधन का जो है, उस में एजोनमेंट के बाद एजोनमेंट दिये जा रहे हैं और उस में सिर्फ एक दो धाराओं को ही एमेंड करना है और यह जो संविधान (संशोधन) विधेयक है, इस में तो 59 धाराएं हैं । इन सब धाराओं को ठीक से समझने के लिए और विचार करने के लिए कितना समय चाहिए, यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं लेकिन ये धाराएं पास हो हो गई हैं और मैं तो कहूंगा कि इन में आप ने जल्दी की है । इसलिए पूरे संविधान पर पुनर्विचार कर के आप एक संविधान (संशोधन) विधेयक लाएं और उस के लिए लोगों को पूरा समय दीजिए ।

बस मुझे यही कहना था ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कानून मंत्री जी को बधाई देती हूं कि वे यह कान्टीट्यूशनल (एमेंडमेंट) बिल यहां पर पास करवा रहे हैं और जो कई किस्म की दिक्कतें आ गई थीं और लोगों ने कान्स्टीट्यूएंट एसेम्बली के नाम पर दिक्कतें पैदा करदी थीं, उन दिक्कतों पर काबू पा कर उस सवाल को कम से कम एक दफा बन्द कर दिया ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यहां पर और भी कई सदस्य कह चुके हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहती हूं पर यह कहना चाहती हूं कि पहले जो कांस्टीट्येन्ट एसेम्बली बनी थी, यह लोक सभा उससे कहीं ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और उससे कहीं ज्यादा इस लोकसभा की ताकत है। इसलिये यह सभी कानूनों में और संविधान में परिवर्तन कर सकती है। जो लोग कांस्टीट्येन्ट एसेम्बली की या दूसरी बातें करते हैं, उनसे मैं बहस में नहीं पड़ना चाहती लेकिन यह कहना चाहती हूं कि अगर इस चीज के चक्कर में फंस गये, तो बहुत भारी दिक्कतें उसमें पैदा हो जातीं और देर भी बहुत लग जाती। अभी कानून मंत्री जी लोक सभा का पीरियड बढ़ाने के लिये कानून लाने वाले हैं वह तो अलग बात है पर अगर कांस्टीट्येन्ट एसेम्बली और इस तरह का नाम लेकर चुनाव में बहुत देर कर दी जाए, तो मैं इस बात को नामुनासिब समझती हूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय, आज जो जरूरत है, वह इस देश के लिये बहुत आवश्यक है। मैं तो यह समझती हूं कि आज चुनावों में जितनी देर होती जा रही है, उतना ही नौकरशाही उसका फायदा उठा रही है। आज हमने अपने और सदस्यों ने अखबारों में पढा होगा कि डी० डी० ए० के बारे में पार्लियामेंटरी कमेटी का एक बयान निकला है कि वह किस तरह से पालिसी बदलती जा रही है और दिल्ली के रहने वाले गरीब आदमियों के लिये कोई जगह रहने वाली नही है। अगर इस तरह की बातों की रोकथाम नही की गई तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि एडल्ट फ्रेन्चाइज के जरिये चुने हुये लोग अगर इस कान्स्टीट्यूशन में परिवर्तन नहीं कर सकते है, तो कौन कर सकता है। यह समय का तकाजा है और मैं कानून मंत्री जी को मुबारकबाद देती हूं कि वे इस बिल में सेक्यूलरिज्म और सोशलिज्म जैसी बातें लायें। ये सब बड़ी इम्पार्टेन्ट चीजें हैं और यह समय का तकाजा है कि समाजवाद लाए बिना कोई चल नहीं सकता। न कोई जमायत चलने वाली है और न देश ही चल सकता है क्योंकि आज हिन्दुस्तान में अगर कोई यह कहे कि गरीब-गरीब है, यह किस्मत की बात है इसको कोई मान नहीं सकता। अगर कोई यह कहे कि गरीब भगवान ने बनाये हैं, और गरीबी भगवान की देन है, इसको कोई नहीं मानता। आज जो गरीब यह कहता है कि मेरी मेहनत का पैसा दूसरे की जेब मे चला जाता है। अब वह बात नहीं चल सकती कि खेती कोई करे और खाए कोई कपड़ा कोई बनाए और पहने कोई और मकान कोई बनाए और रहे कोई। आज उन लोगों को भी इसकी आवश्यकता है और अगर हमने फौरन परिवर्तन नहीं किया और जो बाधाएँ हैं उनको दूर नही किया, तो मैं सफाई से कहना चाहती हूं कि जनता का डेमोक्रेसी में विश्वास नही रहेगा और जिस तरह से एक आदमी को एक दफा पावर दे दी जाए और वह उसको नहीं छोड़ता, उसी तरह से हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमी जिन के हाथ में 25—30 साल से ताकत दे रखी है उस ताकत को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। और अगर हमने वक्त के मुताबिक परिवर्तन नहीं किया तो देश में जनता खुद परिवर्तन लाएगी और खुद समाजवाद लाएगी।

अध्यक्ष महोदय मैं कानून मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देती हूं कि उन्होंने ड्यूटीज के बारे में हम सब का और देश का ध्यान खींचा है और संविधान में इसकी व्यवस्था की है। मगर इसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब तक इसे नहीं देखा जाएगा तब तक इसको अमल में लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी उन्होंने ध्यान दिलाया कि कांस्टीट्यूशन झंडे इन सब का आदर करना चाहिए यह बहुत अच्छा कदम है।

[श्रीमती सुमन्ना जोशी]

हमने देखा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने जिन्होंने संविधान को कभी नहीं माना उन्होंने कहा कि देश में सब धर्मों के लोग यहां के नागरिक नहीं हो सकते। उन्होंने यहां तक कहा कि सबको बराबर के अधिकार दे दिये गये है यह वैसा ही है जैसे कोई बेवकूफ बाप अपने घर में चोर और बेटे को बराबर के अधिकार दे दे। उनके इस किस्म की जो लिखित चीजे थी उनको होम मिनिस्ट्री के ध्यान में लाया गया तो वहां से उत्तर मिला कि वे चीजे कानून के खिलाफ नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ के लोगों ने यह सिर्फ कहा ही नहीं उसके बाद उन्होंने छुरे, लाठियां, बन्दूके चलाना सिखाया जिनको हमने देखा कि लड़ाई में तो वे चीजे काम में आयी नहीं, सिर्फ पड़ोसी के काम आती रही।

इसी तरह से आनन्दमार्गियों ने खोपड़ियों को काट-काट कर रखी। इस पर भी सरकार ने पाबन्दी लगाई है। मंत्री जी ने कहा कि एमरजेंसी पावर में यह पाबन्दी का कानून लगाया गया। मैं उम्मीद करती हूं कि संविधान में परिवर्तन लाने के बाद उनको कानूनी मदद मिलेगी और इन संस्थाओं को वे परमानेंटली बैन करेंगे।

इस संशोधन विधेयक की क्लाजिज पर बहस के दौरान हमने देखा कि माइनोरिटीज कम्यूनिटीज के लोग यह समझ रहे हैं कि उन्हें खतरा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सफाई के साथ कहना चाहती हूं और सरकार को भी मुबारकबाद देना चाहती हूं कि आर० एस० एस० और आनन्दमार्ग पर जो उसने पाबंदी लगाई, उसके बाद हिन्दुस्तान की माइनोरिटीज को पहली दफा यह महसूस हुआ कि हम हिन्दुस्तान के नागरिक हैं और हिन्दुस्तान में हमें भी हमारे हासिल हैं। इसके बाद फिर उन्हें बन्दूकें और लाठियां चलाने की इजाजत दी जाए, तो इसका बुरा असर पड़ेगा।

एक बात मैं और कहूंगी कि कानून मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि इन डायरेक्शंस के मुताबिक कानून बनें कि इतने साल जो इन जमायतों को प्रचार करने की इजाजत दी गई, इतने साल जो काम करने की इजाजत दी गई, उसकी वजह से जो ऐसे हालात बने कि हम जैसे लोग जो फिरका परस्ती को नहीं मानते है उन पर इसका असर पड़ा और बावजूद सरकार के और संविधान के बराबरी का अधिकार देने की यह नतीजा निकला कि हमारी सारी कोशिशों के और सरकार की कोशिशों के इन माइनोरिटी कम्यूनिटी के लोगों को नौकरियों में बिजनेस में बहुत कम स्थान मिला, न के बराबर मिला। कहा जाता है कि माइनोरिटी के किसी आदमी के लिये राष्ट्रपति बनना आसान है पर सरकारी दफ्तर में या दूसरे दफ्तरों में अपरासी की नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। यह जो आज तक इनका पिछड़ापन रहा है उसके लिये जो डायरेक्शन दी गई है, उस पर सरकारी कर्मचारियों के लिये और मंत्रियों के लिये भी ऐसा कानून बनाये जिससे इनका पिछड़ापन दूर हो सके और इन्हें आगे बढ़ाया जा सके।

आपने कम्युनल, रीजनल और कास्ट अलग अलग भाषाओं के और प्रदेशों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जो कदम उठाने के लिये कहा है, उनका भी मैं स्वागत करती हूं।

इस प्रकार का कानून बनाना बहुत आवश्यक है कि किसको आप समझते हैं कि कम्यूनल हार्मनी के लिये काम करता है और किस चीज को आप समझते हैं कि वह कम्यूनल हार्मनी के लिये ठीक नहीं है।

देश के कोने-कोने में लोग जानते हैं कि हम लोग एक अर्से से काम कर रहे हैं और फिरकापरस्ती के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई

छेड़ रखी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस दिन साम्प्रदायिकता विरोधी कमेटी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग मेरे घरमें होती है तो सी० आई० डी० मेरे घर के बाहर आ कर पहरा देती है लेकिन जब आर० एस० एस० की शाखायें लगा करती थीं तो उनके यहां पर पहरा नहीं दिया जाता था। मैं चाहती हूं कि डयूटीज के बारे में जब आप डाइरेक्शंस दे रहे हैं तो आगे इसको भी डिफ़ाइन किया जाए, यह भी बताया जाए कि काम को कैसे करना है और जो नहीं करेगा उसका भी कोई डेफीनिशन हो कि उनके केस में आप क्या करने वाले है।

साइंटिफ़िक चीजों को बढ़ाने के लिये जो आपने इसमें प्रावधान किया है उसके लिये मैं आपको खास तौर पर बधाई देना चाहती हूं। मुझे याद है कि गांधी जी जब डांडी मार्च के सिलसिले मे एक गांव में गए तो वहां गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि गांधी जी के आने से वहा कुएं मे पानी आ गया है। गांधी जी ने उसका खंडन किया और कहा कि ऐसी अनसाइंटिफ़िक बात नहीं की जानी चाहिये मेरे आने से कुएं में पानी आने का कोई सम्बन्ध नहीं है। जवाहर लाल जी ने भी हमेशा हमारा और हिन्दुस्तान का इस तरफ़ ध्यान दिलाया था। आपको मालूम ही है कि अष्ट ग्रह की एक बात को खड़ा कर दिया गया था। उसके खिलाफ़ किस तरह से उन्होंने आवाज उठाई यह हम सबको मालूम है। आज हमारे देश के कोने कोने में कहीं आनन्द मार्गी उठ कर खड़े हो गए हैं, कहीं बौन महाराज उठ कर खड़े हो गए हैं, कहीं बाल योगेश्वर खड़े हो गये हैं, कहीं सांई बाबा हो गये हैं और कहीं कोई और बाबा खड़े हो गये हैं। कितनी ही किस्म के लोग हो गए हैं। अफ़सोस की बात तो तब होती है जब हम उन लोगों को देखते हैं जो इनके सदस्य होते हैं। मुझे याद है आनन्द मार्ग के लोगों ने इसको मुझे बताया है कि जब पहला केस हुआ और किसी लड़के का सिर काट दिया गया तो लड़के के मां बाप भारत की राजधानी हिन्दुस्तान में आए इंसाफ़ पाने के लिये और उनको नीचे से ऊपर तक मालूम हुआ कि जिन को इंसाफ़ दिलाना है वे नीचे से ऊपर तक आनन्दमार्ग के मेम्बर हैं इसलिये उनको कोई मदद सरकार से नहीं मिल सकेगी। सरकारी लोग ऊपर से नीचे तक, राजनीतिक सब इन चीजों में पड़ जाते हैं। मैं समझती हूं कि अगर किसी का विश्वास इन चीजों में हो, इन स्वामी बाबाओं में हो भूतप्रेतों हो तो वह अपने घर में इनकी पूजा पाठ कर लिया करे, अपने घर में उनको बुला करके जो करना हो कर लिया करे लेकिन पब्लिक प्रदर्शन इन चीजों का न करे, इसको एक आफेंस माना जाना चाहिये और इसके मुताबिक कानून बनाया जाना चाहिये।

इस मौके का फायदा उठा कर मैं कानून मंत्री का ध्यान इस ओर भी खींचना चाहती हूं कि बंगलोर युनिवर्सिटी के वॉइस चांसलर ने एक कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा है कि हम साइंटिफ़िक ढंग से इन सब चीजों की खोज करेंगे, पता लगायेंगे कि इन चीजों का कोई साइंटिफिक बेसिस है या नहीं है। मैं चाहती हूं कि आपको इस तरह की बातों पर विचार करना चाहिये। जो भी लोग इन तरह की चीजों मे हिस्सा लें और इनका पब्लिक प्रदर्शन करें तो अगर वे सरकारी अफसर हों तो सरकारी अफसर उनको नहीं होना चाहिये, और अगर पब्लिक के लोग हों तो लोक सभा और लेजिस्लेचर के मेम्बर उनको नहीं होना चाहिये। साइंटिफिक चीजों को बढ़ाने के लिए उचित कदम कानून मंत्री को उठाने चाहिये। मैं चाहती हूं कि स्पेसिफ़िक डायरेक्शंस इशू होनी चाहियें, ठीक से कानून इसके सम्बन्ध में बनाया जाना चाहिये और उस पर अमल हो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिये। इस तरह की चीजों पर पाबन्दी लगाई जाये। ऐसा किया गया तो हम अच्छी तरह से शान्ति की सांस ले सकें। जल्दी से जल्दी जो कानून आपको

[श्रीमती सुमित्रा जोशी]

बनाये हैं उनको आप पास करायें, जो डायरेक्शंस देनी हों दे ताकि उनके मुताबिक काम हो और लोग सचमुच समझें कि अब हम शान्ति से आगे बढ़ सकते है, समाजवाद की तरफ़ बढ सकते हैं, सैक्युलरिज्म को जो मान लिया गया है उसको इम्प्लैमेंट करने के लिये सख्ती से कदम सरकार उठा रही है।

SHRI SYED AHMED AGA (Baramulla): Because of the dynamic leadership of Shrimati Indira Gandhi, this Parliament got the opportunity of passing this Bill, and I am happy that I happen to be a Member of this Parliament and get an occasion to participate in the passing of this Bill. It is true that this is not the last word on *garibi hatao*, or on socio-economic revolution, but it does show the trend, it does give a direction to our future thinking and to the future plans of development that we are to undertake.

This is the third reading of the Bill We are adding the words "socialist and secular" in the Preamble. We are strengthening the unity and integrity of the nation. We are ensuring Directive Principles to become operative. We are safeguarding against anti-national activities. We are providing that steps will be taken by suitable legislation to secure participation of the workers in the management. At the same time, we have also included fundamental duties in this Bill.

Besides attending seminars and symposia on this Bill—it was introduced in September—during the inter-session period, I also, on my own, had conversations and meetings with workmen, labourers, tillers, those who pull out lotus roots from under water and the craftsmen. There, an elderly man told me too things. One was that it was because of the freedom struggle that India was united. The other was that "even though the leaders led us in the freedom struggle, they went to jails. But we received flogging bullets and all type of torture, because we could not be put into the jails. This was due to the fact that the alien rulers could not afford to feed us in the jails."

After this, the elderly man asked me two questions. He asked, "Will you, Mr. Aga, give us the right to work?" He further asked, "Will you, Mr. Aga, give us adequate living wages?"

These are the two questions, which I am transmitting to the Law Minister. I hope he will answer these two questions to enable me to convey his reply to those who asked the questions.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रस्तुत सविधान संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हू और स्वागत करता हू क्योंकि इससे हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता मे, विशेषकर गरीबों में एक बडा उत्साह आया है। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि देश की आजादी के 28 वर्ष बाद भी देश के निवासियो की भाषा मे हम सविधान को नही दे सके है जो कि हिन्दी मे होना चाहिये, और देश की अन्य भाषाओं मे उसका अनुवाद होना चाहिये था ताकि प्रत्येक नागरिक के घर घर में उसकी प्रति रह सकती और वह उसको समझ सकते। सत तुलसीदास की रामचरित मानस देश के प्रत्येक कोने में और घर घर में पायी जाती है और वह हिन्दी मे लिखी हुई है। इसलिये हमारा सविधान भी अगर हिन्दी मे होता तो देश की जनता और विशेषकर गरीबों के हित के लिये जो इसमें संशोधन किये गये है वह संदेश उनके पास तक पहुंचता।

हमारे देश का संविधान आज भी बना हैं और पहले भी था और उसका मुख्य उद्देश्य

हमारे देश के 80 प्रतिशत लोगों के जीवन से सम्बन्धित था लेकिन सरकारी मशीनरी कहां तक उसे इम्पलीमेंट कर पाई हैं । पिछले 27 वर्षों में जो इम्पलीमेंटेशन हुआ हैं वह हमारे सामने हैं । आई० ए० एस० के अफसरों की जो पढ़ाई होती हैं, उसके मुताबिक वह ऐसा महसूस करते है कि राज्य करने के लिये पैदा हुए है, पब्लिक की सेवा करने के लिये नही । आज हमारी मशीनरी जो काम करने के लिये लगी हुई है वह जनता के सेवक है । और सोशलिस्ट प्रकारण में, समाजवादी विचारधारा मे हमारे लिये उनका कमिटमेंट हो, वे हमारी पालिसी के मुताबिक काम करने वाले हों, इसके लिये कानून मन्त्री से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इसके लिये कोई रास्ता निकाले जिससे हमारी कमिटेड मशीनरी हो और हमारी पालिसी को कार्यान्वित करे । जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 3, 4 बरस के लिये आते है, लेकिन कोई डेवलपमेंट का काम नही होता हैं । हमारे मन्त्री महोदय को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिससे हम उस मशीनरी पर हावी रहे और चाबुक हमारे पास रहे ताकि डेवलपमेंट के काम में किसी तरह की ढिलाई न हो ।

हमने 20-सूत्री कार्यक्रम को अपनाया हैं, उस कार्यक्रम के डिवलपमेंट के लिये बहुत कुछ होना चाहिये था जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है । मेरा सुझाव है कि इसकी तरफ मन्त्री महोदय ध्यान दे । गैर सरकारी वाचडाग कमेटी बनाये जो 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित करें ।

हमारे देश की अखण्ड राष्ट्रीयता हैं । पहले धार्मिक एकता थी लेकिन कांग्रेस के आने पर राजनैतिक एकता भी आई हैं और इस सम्बन्ध में एकता की दृष्टि से हम आगे बढ़े है । लेकिन आज भी आप देखेंगे कि लोगों को दूसरी जगहों पर काम करते हुए 15-15 और 20, 20 बरस हो गये है, लेकिन उनको वहां पर कोई अधिकार नहीं मिलता हैं । जो चीजे और सुविधाएं उनको मिली थीं, वह उनसे छीनी जा रही हैं । मध्य प्रदेश एवं आसाम मे हमारे प्रदेश के लोग 20-20 बरस से नौकरी तथा खेती में है, लेकिन वहां के लोग उनसे कह रहे हैं कि आधिक परेशानिया है और उनको वहां से निकालना चाहते है । अगर किसी एक प्रदेश का नागरिक दूसरे प्रदेश मे काम करता है तो वह भी तो देश का ही नागरिक हैं, वहां पर उसे उस के अधिकार मे वंचित नहीं करना चाहिये । अगर यह होता है तो हम राष्ट्रीय एकता की भावना को ठीक से नही समझते है । मेरी कानून मन्त्री मे प्रार्थना है कि वह इस पर भी अवश्य विचार करे कि जहा पर जो व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वह कही का रहने वाला हो उसका वहा अधिकार होना चाहिये । जहा वह पैदा हुआ है अगर वहा से दूसरी जगह पर जाकर काम करता हैं तो उसको वहा पर पूरा अधिकार मिलना चाहिये ।

समाजवाद के ढाचे की तरफ हमको तेजी से बढना चाहिये था, लेकिन आज 27 बरस के बाद भी जितना हमको बढ़ना चाहिये था, नही बढ पाये है । हम हरिजनों के उत्थान की बात करते है, लेकिन जब तक जातीयता रहेगी तब तक न हरिजनों को उद्धार होगा और न कुछ कर पायेंगे । संविधान की प्रस्तावना मे जातीयता को हटाने के लिये जोरदार उद्देश्य होना चाहिये था । मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस तरफ ध्यान दे ।

देश के पिछडे हुए भागों में जहां कि 80 प्रतिशत ग्रामीण मजदूर हैं उनको 20-सूत्री कार्यक्रम का लाभ मिलना चाहिये था । लेकिन बम्बई में काम करने वाले और बलिया व आरा में काम करने वाले मजदूर की पर-कैपिटा इनकम में बहुत फर्क हैं । इसको दूर करने के लिये हम चाहते है कि कोई न कोई कार्यवाही केन्द्रीय सरकार को करनी चाहिये मन्त्री सहोदय से मेरा निवेदन है कि किसी तरीके से भी उनकी इनकम का जो गैप हैं

[श्री चन्द्रिका प्रसाद]

उसको पूरा करने की ओर ध्यान दें। उपेक्षित तथा पिछड़े अंचलों को केन्द्रीय शासित प्रदेश होना चाहिये क्योंकि उनका पिछड़ापन तथा उनकी समस्यायें प्रदेश के बस की नहीं है।

श्री वामनकर (भिवंडी) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और कानून मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसे इस सदन में प्रस्तुत किया। इस सदन के लिये और हम सदस्यों के लिये यह बड़े गौरव की बात है कि आज इस क्रान्तिकारी बिल को हम पास करने जा रहे है। इस बिल से जो गरीब और पिछड़े हुए लोग है, उनको न्याय मिलेगा और तरक्की करने का मौका मिलेगा। पहले भी कानून बहुत से पास होते थे, सूबके विधान मण्डल और केन्द्र कानून बनाते थे, लेकिन वह कानून गरीबों की झोंपड़ी तक पहुचते नहीं थे। इसका नतीजा यह होता था कि जो साहूकार और पैसे वाले लोग है, वह वकीलों को पैसा देकर न्याय पर पा लेते थे और वह न्याय गरीबों को मिलता नही था।

हमारे प्राइम मिनिस्टर की अपील पर पिछले साल हमारे वकील मित्रों ने सेटर में एक बेशनल लीगल एड कमेटी बनाई। विभिन्न सूबों और डिस्ट्रिक्ट्स में उसकी शाखाये कायम की गईं। मेरे इलके, भिवंडी, जिला थाना, में एक शाखा कायम है और वह वहां के आदिवासी क्षेत्रों में लीगल एड उपलब्ध करने के सम्बन्ध में काम कर रही हैं। श्री प्रभाकर हेगड़े वहां पर डिस्ट्रिक्ट लीगल एड कमेटी के चेयरमैन है और वह अपने साथियों के सा एक साल से इस काम में लगे हुए है। इस के फलस्वरूप आदिवासियों में बड़ी जागृति उत्पन्न हुई हैं। हमने वहां पर लोक न्यायालय कायम किये है। यद्यपि इसके लिए हमें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन लोगों की सहमति से हमने यह कदम उठाया। लोक न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय कम्प्लेंट करने वाले, और जिसके विरुद्ध कम्प्लेंट हैं, उन दोनों ने मान लिये। पहले जिस तरह न्याय पंचायतें चलती थीं उसी तरह हम इन लोक न्यायालयों को चला रहे है और लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे है। मैं चाहता हूं कि कानून मन्त्री सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में सहायता देने की व्यवस्था करें।

पिछले हफ्ते थाना के ला कालेज के चालीस स्टूडेंट्स एक आदिवासी क्षेत्र कासा गांव में गये। सात दिन तक वे आदिवासियों की झोंपड़ियों में जाकर उनको कानूनों के सम्बन्ध में जानकारी देते रहे। सुप्रीम कोर्ट के पिछले न्यायाधीश श्री भगवती, उन स्टूडेंट्स के काम को देख कर बहुत प्रभावित हुए। आवश्यकता इस बात की हैं कि इस काम को आगे बढाया जाये। सरकार की तरफ से नेशनल लीगल एड कमेटी की शाखाओं को सहायता मिलनी चाहिये।

हमने ने इस संशोधन के द्वारा संविधान में फण्डामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा हैं। उस से ट्रेड यूनियन्स में काम करने वाले लोगों में यह डर पैदा हुआ कि उन के काम में बाधा डाली जायेगी। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एम० एल० एज०, एम० पीज० और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की एक मीटिंग बुलाई, जिस में संविधान (चालीसवां) संशोधन पर चर्चा हुई। वहां इनकटक के एक यूनियन कार्यकर्ता, श्री वसंत होशिंग, एम० एल० ए०, ने यह आशंका व्यक्त की कि इन ड्यूटीज के द्वारा ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज पर पाबन्दी लगाई जायेगी। मन्त्रिगण ने उन को समझाया कि इस संशोधन का इस्तेमाल ट्रेड यूनियन का काम बन्द करने के लिये नहीं किया जायेगा। मगर कुछ ऐसी घटनायें होती हैं जिन से यह डर पैदा होता है कि हमारे ट्रेड यूनियन का काम करने के राइटफुल अधिकार में बाधा डाली जायेगी।

बेड़ी कांस्टीट्यूएन्सी में अम्बरनाथ एक मजदूर क्षेत्र है, जहां बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं। मैं दो दिन पहले वहां इस संविधान संशोधन का विवेचन करने के लिए गया और वहां के मजदूर कार्यकर्ताओं से मिला। वहां पर एक मजदूर नेता, इण्टक के कार्यकर्ता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, श्री सलामत राय, को मीसा में बन्द किया गया है। मैं नहीं कह सकता हूं कि उन को गिरफ्तार करना गलत था। हो सकता है कि सरकारी अधिकारियों का यह मत हो कि वह प्राडक्शन में बाधा डालते हैं और उनकी गतिविधियों से शान्ति को खतरा है, इस लिए उनको गिरफ्तार करना जरूरी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो कानून मजदूर संगठनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह मिल-मालिकों और मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। दो महीने पहले सेन्चरी देयन की फैक्ट्री में लाक-आउट डिक्लेयर किया गया। यह लाक-आउट इमर्जेंसी में डिकलेयर किया गया. लेकिन फिर भी मैनेजमेंट के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमारे नेतागण और सरकारी अधिकारियों ने उस को मनाने की कोशिश की। लेकिन जब मजदूर संगठन ने कुछ कदम उठाया, तो मीसा का इस्तेमाल किया गया।

मैं कानून मन्त्री और होम मिनिस्टर से यह अनुरोध करूंगा कि इस मामले की जांच-पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि अगर मजदूर वर्ग पर ऐसा दबाव डाला जायेगा, तो एक्सप्लायट करने वाले मिल-मालिक और सख्ती से काम लेंगे। यह नहीं होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और केन्द्रीय सरकार इस घटना की पूरी जांच-पड़ताल करे, ताकि मजदूरों के साथ अन्याय न हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आप ने मुझे मौका दिया, उस के लिए बहुत धन्यवाद।

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक आज पेश है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि एक ऐतिहासिक महत्व का यह विधेयक है। मैं इस विधेयक को उस पहलू से देखना चाहता हूं जिस पहलू से इस विधेयक के प्रीएम्बल में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द जोड़े गए हैं और उन की व्याख्या की गई है। आप जानते है कि देश में 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और मैं उन शब्दों को यहां उद्धृत करना चाहता हूं जो मेटकाफ ने जंगे आजादी के बाद जो गांवों के किसानों की हालत होती है उसके सम्बन्ध में कहे हैं:

"Destiny after destiny tumbles down. Revolution succeeds to revolution Hindu, Pathan, Moghul, Maratha, Sikh, English are all masters in turns. But the village communities remain the same. In times of trouble, they arm and fortify themselves. A hostile army passes through the country. The village communities collect their little cattle within their walls, and let the enemy pass unprovoked."

मैं इस विधान के सम्बन्ध में जिस में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द प्रीएम्बल में लिखे गए हैं विधि मन्त्री से जानना चाहता हूं कि आज जो विधान में संशोधन किया जा रहा है क्या उस में उस का रेफ्लेक्शन है? क्या आज भी बहुत से आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें संशोधन और परिवर्द्धन की जरूरत है? और यदि है तो विधान कोई स्टेटिक नहीं होता। इस संसद् को पूरी ताकत है, यह ऐडल्ट फ्रैंचाइज से चुनी हुई संसद् है जिस को यह शक्ति है कि वह विधान की किसी भी धारा को समय के अनुसार बदल सकती है। जब मैं यह देखता हूं कि राइट आफ प्रापर्टी का सवाल ज्यों का त्यों है, इण्डिविजुअल प्रापर्टी का सवाल ज्यों का त्यों विधान में रखा गया है और उस पर किसी तरह की कोई व्याख्या नहीं की गई है, तो मैं जानता हूं कि आज जो मैं ने उद्धृत किया या जो प्रीएम्बल में सोशलिज्म,

[श्री नर्सिंह नारायण पांडे]

सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात कही जा रही है उस के बारे में हमें और विचार करना पड़ेगा। हमें इसे देखना पड़ेगा। यह कहा जाता है कि हमारे ये फण्डामेंटल राइट्स हैं लेकिन कांस्टीट्यूशन में डाक्टर अम्बेडकर ने कहा कि किसी तरह का कोई फण्डामेंटल राइट नहीं है। इस विधान में सब से फण्डामेंटल अगर कोई चीज है तो वह इस देश की जनता है। जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं वही इस देश के बेसिक फीचर हैं। बेसिक फीचर हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और देश की जनता। उस के द्वारा जो लोग लोक सभा में या विधान सभाओं में चुन कर आते हैं वही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हीं को अधिकार है कि वे कानून बनाएं। तो जो जनता के लिये कानून बनाते हैं, जो विल आफ दि पीपल को एक्सप्रेस करते हैं वही बेसिक हैं और वही बेसिक फीचर हैं। इस के अलावा कोई चीज न तो फण्डामेंटल है और न कोई नान-फण्डामेंटल है और अगर कोई विधान को बदल सकता है तो वह यह पार्लियामेंट बदल सकती है जैसा कि विधि मन्त्री ने साफ तरीके से आर्टिकल 368 में वर्णन किया है कि इस संसद् को पूरी शक्ति है, वह कांस्टीट्यूशन के किसी भी सेक्शन को अमेंड कर सकती है। लेकिन इसके बाद जरूरत इस बात की है कि जब हम ने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का निश्चय किया तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है? आज हमारे देश में नाना प्रकार की ऐसी शक्तियां हैं जिन की तरफ सुभद्रा जी ने इशारा किया, चाहे वह जमायते इस्लामी हो, चाहे हिन्दू महा सभा हो चाहे जनसंघ का मिलिटेंट विंग आर०एस०एस० हो, ये शक्तियां देश की इंटेग्रिटी को खतरा पहुंचाना चाहती हैं। हम ने जहां पर फण्डामेंटल ड्यूटीज को रखा है जहां हम ने यह कहा—"To abjure Communalism" वहां मैं यह जरूर चाहता हूं कि इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि 29—30 साल का इतिहास इस देश का चला आ रहा है कि आज गांवों का आदमी या शहर का गरीब आदमी किसी न किसी तरह कम्युनलिज्म का शिकार ऐसे उपद्रवों के बाद होता है। साम्प्रदायिकता जब होती है, सबसे ज्यादा जो उसका असर पड़ता है वह इस देश के गरीब आदमियों पर ही पड़ता है। उन लोगों का मैं प्रोटेक्शन चाहता हूं। आज इस सदन में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं उनको डी-फ्रेंचाइज करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में या कहीं न कहीं पर व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे लोग जो देश की यूनिटी, इन्टेग्रिटी के खिलाफ ऐसे तरीके से अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, इस देश में कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, कम्युनलिज्म के आधार पर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं मैं समझता हूं वह इस देश की इन्टेग्रिटी के लिए, यूनिटी के लिए और इस देश की सावरेण्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं आज साफ तरीके से कहना चाहता हूं आज 27 साल में बावजूद तमाम सैक्यूलर और डिमोक्रेटिक पार्टीज के प्रचार और प्रसार के और सामाजिक आन्दोलनों के और समझाने बुझाने के बाद भी इस देश में कम्युनलिज्म चलती है, साम्प्रदायिकता उभारी जाती है, नाना प्रकार से उसको बढ़ावा दिया जाता है इसलिए वह कांस्टीट्यूशन जो समाजवादी और सेक्यूलर कांस्टीट्यूशन है उसके डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में या कहीं न कहीं इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि आज इस तरह के जो लोग इस देश में इस तरह की भावना पैदा करते हैं उनको डी-फ्रेंचाइज किया जायेगा, उनको बालिग मताधिकार से वंचित किया जायेगा।

दूसरी बात यह है कि मैं मानता हूं जैसा डा० अम्बेडकर ने कहा था यह विधान

जो बनाया गया था वह 1935 ऐक्ट और इन्डेपेंडेन्स ऐक्ट की तहत बनाया गया था लेकिन उस समय इस देश में हालात क्या थे ? उस समय इस देश में बड़े-बड़े राजा नवाब और दूसरी ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें थीं जो इसको बनाने के लिए विधान निर्मात्री समिति में बैठी थीं, कुछ लोगों ने उसमें भाग लिया था और कुछ लोगों ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद इंडिया का पार्टिशन हुआ और ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन आया। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह एक कम्प्रोमाइजिंग कांस्टीट्यूशन है और इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। इसी पार्लियामेन्ट को इस पर विचार करने की जरूरत है।

श्रीमन् एक प्रश्न यह उठाया गया था कि ब्यूरोक्रैसी के बारे में हमारा इंस्ट्रूमेन्ट क्या हो जिससे हम सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म की व्याख्या को ऐचीव कर सकें। आज मैं अपने उस आदरणीय साथी मिनिस्टर को कोट किए बिना नहीं रह सकता जोकि आज हमारे बीच में नहीं है जिन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कमिटेड जुडीशियरी और कमिटेड एग्जीक्यूटिव को रखना पड़ेगा। आज मैं कहना चाहता हू कि समय आ गया है जब विधि मंत्री को इस पर विचार करना पड़ेगा आज बहुत सी इंडिवीजुअल बातें मैं इमरजैन्सी के सम्बन्ध में कहना नही चाहता हूं लेकिन बहुत सी एग्जीक्यूटिव एथारिटीज ने अपनी पावर्स को मिसयूज किया है। हमारे कांस्टीट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और समाजवादी विचारों की रचना में एग्जीक्यूटिव एथारिटीज को जो योगदान देना चाहिए वह योगदान वह नहीं दे पा रही हैं। इसलिए आज हम अपनी एग्जीक्यूटिव को किस तरह से रिफ़ार्म करें, किस तरह से उसकी रचना करें जिससे कि वह हमारी सामाजिक, आर्थिक उपयोगिता को साबित कर सके—यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आप इस कांस्टीट्यूशन में जिस तरह से चाहें परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन अगर आपने एग्जीक्यूटिव को नहीं सुधारा तो सफलता नहीं मिल सकती है। आज एग्जीक्यूटिव को जो शक्ति मिल रही है उसका दुरुपयोग, जैसा कि अनेक साथियों ने कहा है, येन केन प्रकारेण किया जा रहा है। इसलिए सरकार को विचार करना होगा कि किस तरह से पावर्स को डी-सेन्ट्रलाइज करें जिससे जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में वह शक्तियां रहें और सही तरीके से जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके तथा हम भारत के संविधान के अनुरूप चल सकें। इस प्रश्न पर विधि मंत्री को विचार करना पड़ेगा।

फ़ंडामेंटल राइट्स के बारे में बड़े पत्र अमरीका आदि देशों से बहुत लोगों के आये किन्तु वह कहां से आये और किस मार्ग से आये मैं उसमें नहीं जाना चाहता ? लेकिन मैं उस बात को जो डा० अम्बेडकर ने कांस्टिट्युएंट असेम्बली में फ़न्डामेंटल राइट्स के बारे मे कहा था, पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं। हालांकि विधि मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में इन चीजों को स्पष्ट किया है, लेकिन मैं उन चीजों को कहना चाहता हू—जिस समय आर्टिकल 13 कांस्टिट्युएंट असेम्बली के सामने आया था—अम्बेडकर साहब ने अमरीका के उस केस को कोट किया था —

In Gitlow Vs New York in which the issue was the constitutionality of a New York criminal anarchy law which purported to punish utterances calculated to bring about a violent change, the Supreme Court said:

> "It is a fundamental principle long established that the freedom of speech and of the Press which is secured by the Constitution does not confer an absolute right to speak or publish without responsibility whatever one may choose or an un-restricted and unbridled license that gives immunity for every possible use of language and prevents the punishment of those who abuse this freedom."

[श्री अरविंद नारायण पांडे]

इस से साफ साबित हो जाता है कि चाहे विचारों की बात हो, चाहे जिम्मेदारी की बात हो, चाहे इस देश में किसी तरह से अपने विचारों को रखने की बात हो, ये विचार जिम्मेदारी के साथ रखे जाने चाहिये, अगर जिम्मेदारी के साथ नहीं रखे जाते है तो चाहे व्यक्ति हो या कोई भी हो---डा० अम्बेडकर ने अमरीका की सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को कोट करते हुए कहा था ---इस में आज लाइसेंस नहीं होना चाहिये ।

श्रीमन्, मैं आप का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं पुन विधि मंत्री जी से कहना चाहता हू—देश की भाषा हिन्दी है हिन्दी हमारी जुबान है, देश के रहने वालों की जुबान है, लोकशाही की जुबान है, लेकिन हमारा जो संविधान है, मुझे यह कहते हुए शर्म आती है, वह अंग्रेजी भाषा में है वह भाषा जिसे इस देश के केवल 2 प्रतिशत लोग बोलते हैं । अगर इस तरह से अंग्रेजी को हमारे देश के साथ जोड़ा गया, तो इस देश में हमारी जुबान की कोई कदर नहीं रह जायगी । दुनिया के तमाम समाजवादी देशों ने अपनी जुबान में अपने संविधान को बनाया है । आप रूस चले जाइये, दूसरे समाजवादी मुल्कों में चले जाइये, वहां के लोग अपनी जबान में बोलते हैं और अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में तर्जुमा होता है । मुझे आज यह कहते हुए दुख होता है कि 27 सालों की आजादी के बाद भी आज जो अंग्रेजी जुबान बोलता है, उस को ज्यादा प्रतिष्ठा मिलती है, जो मातृभाषा में बोलता है उस की कम प्रतिष्ठा होती है । विधि मंत्री जी को इस के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये, आज लोकशाही के लिये लोक-भाषा का होना नितान्त आवश्यक है और इस विधान में लोकशाही की भाषा हिन्दी को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत शुक्रिया अदा करता हू, आप ने मुझे बोलने का मौका दिया ।

SHRI M KALYANA SUNDARAM: (Tiruchirapalli): Sir, my Party has moved several amendments, opposed some of the clauses and even voted against some of the clauses In spite of that, we have decided to vote for the Bill as a whole. What are the reasons? We do realise that we are taking a great responsibility in giving full support to this Bill as it is today and as it has been finalised before this House We are aware that the forces which are trying to decry this amendment, are still very powerful and very active outside In spite of that my Party has decided to give support to this Bill

12 00 hrs

The main reason for our giving support is that the supremacy of this House has been assured and the parliamentary democracy in this country has been preserved The threat to our form of democracy was really serious So, my party feels greatly relieved that this threat, although not completely eliminated, has at least been warded off for the present and the supremacy of Parliament is being retained and the parliamentary form of government is being continued as a form of government for our country so long as there are no threats Whatever happens, my party is pledged to give full support to the parliamentary form of Government being continued in this country and thus increasing the powers of Parliament

Parliament, as expressing the will of the people, is supreme Judiciary has no business to come in confrontation with Parliament. It should be the business of Parliament to decide what should be the socio-economic reforms, and not of any other agency outside this House All forces are welcome to campaign for their views

on all topics, but no force outside this House can place themselves above this House. That is our attitude, and that is why, in spite of all the negative features, some of which are very serious, still my party is inclined, feels it its duty, to give support to this Bill.

Some of the amendments given notice of by my party were with a view to give full dimension to the aims and objectives, to give fuller content and meaning to our democracy. We are now passing the Constitution (Forty-second Amendment) Bill, which at the time of introduction was called the Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill. During these 26 years of the existence, the Constitution has been amended 41 times before.

We have now added the two concepts of "socialism" and "secularism". We have no illusion that by adding these two words in the preamble, from tomorrow our country will be on the high road to socialism. But we are convinced of one thing, that the working class, the peasantry, the intellectuals, those who want to take our country forward, will agree with the aim of socialism. The symptoms that we are seeing in our country, the struggles that are taking place, are to bring about the necessary socio-economic changes towards the goal of socialism. Ultimately, it is the toiling people who are going to build socialism. Their co-operation is necessary. They must be roused and they must be involved in the struggle against all the forces which are working against the idea of socialism. We have chosen our own path. There is no need for us to imitate or copy from any other country. But, at the same time, we must be humble enough to learn from the experience of other countries which have built socialism, which have struggled to build socialism. We must know who are our enemies, not only from outside but also from inside.

The enemies of socialism inside will have their links with the enemies outside. So, if we want to build socialism, we must know the economic factors which are operating against the concept of socialism. On these points we may have differences of opinion with the ruling party, but we are sure that the ruling party also will gradually change as they have been changing during the last 21 years. So, with more experience, they will have to change. We are not opposed to all rights of property, that is a misconception. Under socialism, private property necessary for the living of the man will be ensured. What we are firmly opposed to and determined to fight is the private ownership of public property and the means of production. That is what we are against. If we fail to abolish private ownership of the means of production, the word "socialism" will only be an illusion This is a very fundamental question. That is why my party was so keen on moving an amendment in that direction. It has been defeated. In our experience we have seen that what we say is never immediately accepted, it is opposed, but ultimately it will be accepted. We are confident of that That faith gives us confidence and courage to support this Bill. If not this year, if not this Parliament, another Parliament will accept it. The history of our country will confirm it.

So, the means of production in the country must be nationalised and the day will come when even our Congress friends will also be agitating for it. Today I saw a news item that some Congress Members are giving a resolution to the AICC for the nationalisation of sugar industry. Sugar, textiles, etc. should be nationalised. Where is the difficulty? So, step by step we must see that the private monopolist control over the means of production is abolished. That is a very vital thing. That is why we gave some amendments and fought for this.

[Shri M. Kalyana Sundaram]

Another thing on which we are keen is the unity of the country. The forces of de-stabilisation and the forces of separatism and linguistic chauvinism are still active. They are attacking this Bill tooth and nail. They are adopting all forms of whispering and illegal propaganda against this Bill. We have to face and counter that propaganda. All the speeches here, however eloquent they may be, are no substitute for countering the activities of the forces of de-stabilisation and separatism outside the House. They must be countered by the unity of progressive and democratic forces, taking the spirit of this Constitution and explaining it to the people. That task remains to be done.

Education has been brought into the Concurrent List by this Bill. My party supports it. In fact, we have even suggested that agriculture and other things should also be included. This does not mean that this is against the interests of the State. On the question of language, we must proceed very cautiously. The formula laid down and the assurance given by the late Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, must be borne in mind.

You have to do it if you want to advance towards genuine national unity and the integration of the nation. The other day, our Prime Minister was impressing upon the unity of the country in diversity. English and Hindi, both must continue to be the official languages till the non-Hindi speaking people agree. This is a very important factor and should not be lost sight of. It is easy to sit here and say this thing and that thing. I am one of those who have faced this situation and we will face it.

If there is orderliness in Tamil Nadu, it is not because of police and army; it is because of the healthy attitude of the progressive forces standing for unity and national integration. I warn you about the socio-economic factors which give rise to such separatist forces. They have not disappeared. This fact must be borne in mind. This thing must be studied very carefully and the Tamil Nadu people must be helped in this respect. National unity is not just sentimental. The economic development lies through national unity.

Today, we are faced with the worst drought situation. If we do not get Cauvery water, then what the people will think about national unity. A large number of people are living below the poverty line. The economic development of Tamil Nadu should be helped by the neighbouring States and by the Centre.

Even under the President's Rule there should be some convention for giving advice. Whose advice will be taken? Now, you have postponed elections for two more years. What will happen to the big State with a population of nearly 4-1/2 crores and with such complex and complicated economic and political situation? How will they discharge their functions properly? Who will give them political guidance? If they look for advice from Delhi every time, then there will be inordinate delay. Delhi itself suffers from indecision.

I am sorry to say and warn you that the danger from the forces of de-stabilisation has not receded. How to rectify it? It should be rectified. You must appoint some committee. The Consultative Committee is not enough which meets once in three months and discusses about 200 items on the agenda. There should be an all-Party committee which supports the policy and the economic programme. The Governor of the State should act upon the advice given by this committee. There are disruptive

and separatist forces which are very active. The situation in Tamil Nadu is not as happy as you imagine sitting here. It is very sensitive. All the benefits that we got after the imposition of the President's Rule are in danger of being wiped out. With these words, I finish my speech.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Mr. Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me a chance to participate in this debate.

The present decade in our country has been full of epoch-making events. Our people bade good-bye to the forces of *status quo-ism* in the great conflict of 1969 and, I think, we have bade good-bye to those forces for all time to come. Since then, we have started on our long march to establish a socialist order through democratic means and processes to end poverty, exploitation and degradation in our society and to keep ourselves, at the same time, abreast of times. One feels privileged to find that after all this long period of conflict, stresses and strains, today we are going to pass this new amendment to the Constitution and I feel privileged to get this chance of participating in this great process that we are undertaking.

The present amendment of the Constitution, I consider, is another glorious milestone in our goal to achieve emancipation of masses from long ages of penury, deprivation and poverty and to build a new society. I consider that the unity and integrity of India and the supremacy of Parliament, meaning thereby the people of this country, are the two essential foundations of our Constitution. By enacting these amendments, today, once again we are taking a historic measure and strengthening these foundations. Once Dr. Radhakrishnan, the great philosopher of India had said:

> "Poor people who wander about, find no work, no wages and starve, whose lives are a continual round of sore affliction and pinching poverty, cannot be proud of the Constitution or the laws."

Therefore, I think, the steps that we are taking are in keeping with the times and the aspirations of our people.

Today, by adopting these amendments, we are giving primacy to the Directive Principles of State Policy which aims at establishing a just society, free from exploitation and various social inequalities. The vast masses of our people who live below the poverty line shall have more confidence in our political system, party and Government as they will now find that their Constitution is not something which is far away from them, that it is not something like a deity which is to be merely worshipped in the temples but that this is their Constitution, the people's Constitution and it is their instrument to improve their lot. They will feel that with the help of the Constitution their representatives are trying their best to fulfil the promises that our party made to the people in 1971. In this light, I consider, that today we are fulfilling the promises that our Prime Minister, our party and our leaders gave to the people in 1971 which for various reasons could not be implemented. Today, we are implementing those promises given to the people.

This is what Pandit Nehru had said in the Constituent Assembly on November 11, 1948. I quote:

> "And remember this, that while we want this Constitution to be as solid as a permanent structure as we can make it, nevertheless there is no permanence in Constitution. There should be a certain flexibility. If you make anything rigid and permanent, you stop a nation's growth, the growth of living vital organic people. Therefore, it has to be flexible."

[Shri Chintamani Panigrahi]

Today, the Constitution has stood the test of time. In the last decade, whatever changes have taken place in this country, our Constitution has imbibed them and it has tried to uphold the rights and the aspirations of the people.

I come from a State where 1200 sculptors built the Konarak Temple and spent 12 years to complete it. Like that, as good sculptors, we have chiselled out 103 statues in the form of amendments in this grand structure of our Constitution that was given to us in 1950 and even then this grand structure of our Constitution stands in its grandeur and invites us again, and again, to look into it and amend it to suit the needs and the aspirations of the people Still, I think the Constitution maintains its majestic grandeur and it invites us again and again to go to the people and to look to their needs and, if anything is found lacking, to complete it again in the form of other amendments. A marching, vibrant nation is always restless and a Constitution which represents its aspirations can never be static. In olden times our people went to various places of pilgrimage like Jagannath Puri, Rameswar and Dwaraka By man's ingenuity, milestones have been erected on the way, but these pilgrims who traverse these paths do not stop at every milestone to reach their destination Man put milestones on the way only to measure the distance a pilgrim has travelled Milestones are not millstones on his neck for him to be crushed under its weight A pilgrim who wants to reach his goal will not be deterred from his march by these milestones Our Constitution is also not a millstone around our neck nor a road-block When we achieved independence and set out to frame the Constitution ours was a wholly feudal society and with the aid and assistance of our Constitution and under its democratic processes our people have fully broken the stranglehold of feudalism in our society and country. We have also taken revolutionary measures to break the stranglehold of monopoly capital on our credit systems and various other means of production.

It is relevant to ask, at this point whether the Constitution that we have framed, the instrument which we have forged to break the stranglehold of feudalistic economy or feudal society would be adequate for our society when we are passing through democratic processes and when we have declared that we shall be a socialist Republic. We declared that we shall have a socialist Republic in 1976, after completing other phases of social transformation in the last 26 years. This is a great and historic achievement, and I can venture to say, if you will permit me, that we have entered a new phase of our nation-building process and this second phase stands committed to socialism which can be termed as second Republic To compete this task, we may take another 24 years; let us try to complete it by 2000 AD.

I was surprised to hear someone on the other side say that some private citizens had framed the five-point programme and he is not bothered about it I am simply astounded at the kind of knowledge he has. New revolutionary ideas are always from private persons of the Congress Party and they get into the national policies. The Prime Minister herself declared the 20-point and five point as national programmes. I think, therefore, that there should not be any misgivings on this score. Our Constitution now stands committed to ensure workers' participation in the management, to take care of the healthy growth of youth and children.

I would like to conclude by quoting the prophetic words of the great sage and revolutionary Shri Aurobindo. He said

"India must be re-born, because her re-birth is demanded by the future of the world."

And he exhorted the countrymen:

"Work that she may prosper; suffer that she may rejoice"

Shri Aurobindo in his earlier days in a letter to his wife, had written that he has three madnesses and one of these madnesses was that people see their country as a lifeless material object, in terms of fields, forests and rivers, but he said:

"I know my country as my mother and I worship and adore her.'

Therefore, let us worship our country as mother, and let us perform the duties that have been enshrined in the Constitution. This is a new phase that we have entered. Let us make it a success. I give full suport to this measure, and I am sure the country will stand by it.

श्री सुख देव प्रशाद वर्मा (नवादा) : अध्यक्ष महोदय मैं संविधान, (चवालीसवां संशोधन) विधेयक का न केवल हृदय से समर्थन करता हूं, बल्कि उस का स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और इस के लिए प्रधान मंत्री, विधि मंत्री और भारत सरकार को बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत उचित समय पर यह कदम उठाया है । हालांकि संविधान में और भी संशोधन करने की आवश्यकता है, लेकिन इस संशोधन विधेयक के द्वारा जो भी प्रावधान किये गये है, वे बहुत सराहनीय और स्वागत योग्य हैं ।

यह बड़े संतोष का विषय है कि हमारे प्रधान मंत्री ने ठीक समय पर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता को महसूस किया । कुशल डाक्टर वही है, जो रोगी को देख कर रोग की पहचान करे और तुरन्त उस का निदान करे । इसी प्रकार सफल नेता वही है, जो देश की जनता की आवश्यकताओं को समझ कर उन को पूरा करने के लिए समय पर पग उठाये । प्रधान मंत्री एक लम्बे अर्से से जो सराहनीय कार्य करती आ रही हैं, उसी का यह फल है कि आज संविधान का चवालीसवां संशोधन हमारे सामने है ।

यह बहुत सुन्दर बात है कि संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी" और धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को जोड़ा गया है । मगर हमारे देश में जो आर्थिक और सामाजिक विषमता है, हम उस को दूर करने में कहां तक सफल हो सकेंगे यह विचारणीय प्रश्न राष्ट्र के सामने है । इस संशोधन का उद्देश्य कुछ लोगों को सुविधायें देना नहीं है, बल्कि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण करना है । और भारत तब तक एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकेगा, जब तक उस के अस्सी प्रतिशत लोगों की स्थिति में सुधार नहीं होगा । जैसा कि कई बार कहा जाता है, हमारे समाज की बनावट ऐसी है कि एक तरफ लोग खाते-खाते मर रहे है और दूसरी तरफ खाने के बगैर मर रहे हैं ।

जब हम समाज की इस बनावट को बदल देंगे और खेतों खलिहानों तथा कारखानों में परिश्रम करने वाले लोगों और धंधे की फिक्र में मारे-मारे घूम रहे पढ़े-लिखे बेकार नौजवानों के लिए कम से कम इतने साधन जुटा देंगे कि वे अपनी जिन्दगी को सही ढंग से बिता सकें, तभी हमारा राष्ट्र मजबूत बन सकेगा । आज क्या हालत है ? गांवों में रहने वाले छोटे किसान और खेतिहर मजदूर परिश्रम करते हैं, मगर सतांईस साल की आजादी के बाद भी उन मेहनतकश लोगों को अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा है और वे विकास तथा प्रगति के सभी अवसरों से वंचित हैं ।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सम्बन्ध में संविधान में पहले से प्रावधान रहे है और उनको ऊपर उठाने के सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न भी हुए हैं । यह बात नहीं कि प्रयत्न नहीं हुआ है, प्रयत्न हुआ है और होता जा रहा है किन्तु मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उसी संविधान में अनुसूचित

[श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा]

जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी पड़े हुए हैं जिनकी व्यवस्था के लिये संविधान में जिक्र है जो देश के अन्दर बहुत बड़ी तादाद में हैं, जो हरिजनों से भी दुर्बल अवस्था में हैं, उनके लिये आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कोई व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे है। आज संविधान की वह धारा जिसमें इन को रखा गया है सूती पड़ी है। इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। हिन्दुस्तान के अन्दर हमारी प्रधान मंत्री जी ने संकल्प लिया है गरीबी मिटाने का तो यह देखना होगा कि ऐसे तमाम वर्गों का उत्थान हो, उनकी हालत में भी खुशहाली आए और उन लोगों की ही खुशहाली के लिए भी यह संविधान संशोधन किया गया है। लेकिन संविधान में संशोधन करने से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाता तो बड़ी खुशी की बात थी। किन्तु इस संविधान को कार्यान्वित करने वाला जो आपकी मशीनरी है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है उसका दिमाग जो हमारी प्रधान मंत्री या विधि मंत्री सोचते है, या जो हमारे लोक सभा के सदस्य सोचते हैं उसके अनुकूल कार्य करने के लिए सक्षम है या नहीं है, इस बात को देखना होगा। अगर सक्षम नही है तो सक्षम बनाने का उपाय करना होगा। तभी जाकर इस संविधान के कार्यान्वयन मे सफलता होगी। अगर ये उसके लिए सक्षम नही हैं तो संविधान के संशोधन से देश की समस्या का समाधान नही हो सकता है। समाधान अगर करना है तो हमें यह देखना होगा कि कार्यपालिका की यानी प्रशासनीय सरकारी यंत्र की मनोवृत्ति में उसके अनुकूल आवश्यक परिवर्तन हम लाए है या नही।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं और मै भी जानता हूं कि स्वराज्य की लड़ाई जब चल रही थी उस वक्त जो लोग अमन सभा करते थे और अंग्रेजी राज को रखने की साजिश कर रहे थे स्वराज्य के बाद वे राष्ट्रवादी बन गए हैं और उसी समाज से यह कार्यपालिका आई है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि उनकी मनःस्थिति को आज उस दृष्टिकोण से चेंज करना पड़ेगा जिस दृष्टिकोण से हम स्वराज्य की लड़ाई लड रहे थे। संविधान मे संशोधन कोई नया नही है। फैजपुर और कराची कांग्रेस का प्रस्ताव स्वराज्य के पहले का है और हम बार बार उसको दोहराते आए हैं। कांग्रेस के विभाजन का मूल कारण भी यही है कि प्रधान मंत्री चाहती थीं कि सारे जो कांग्रेस के प्रस्ताव है स्वराज्य के पहले से लेकर अब तक के जो फाइलों में पड़े हैं वे जमीन पर उतरें। इसके लिए यह विभाजन हुआ। विभाजन के बाद ऐसे लोग जो इस से सहमत नहीं थे बाहर चले गए लेकिन जो आपकी मशीनरी है उसमें भी आज ऐसे लोग मौजूद हैं। इसमे मुझे थोडा दुख तो जरूर होता है लेकिन मुझे विश्वास है अपनी नेता पर कि इस कार्य को करेगी। उस मशीनरी को आर्टिकल 311 के अन्तर्गत जो प्रदत्त शक्तियां है उनके सम्बन्ध मे हमारी कांग्रेस बैंचेज से भी विचार व्यक्त किए गए। वह सरकार को मान्य नही हुए। लेकिन सरकार को मान्य न हों, इस की मुझे चिन्ता नही, मुझे चिन्ता इस बात की है कि उन्हे इस कार्य के अनुकूल बनाया जाय। आज प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम ने, श्री संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम ने देश की आम जनता एवं जवानों में और देश के गरीब वर्गों में एक नया उत्साह पैदा किया है। वे जाग गए है और उनकी जागरूकता का परिचय है कि यह संविधान का संशोधन आया है। लेकिन यह सोने में सुगन्ध की बात होती अगर व्यक्तिगत व्यक्तिगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो मूलभूत अधिकार हैं उनको समाप्त करने के रास्ते पर हम चलते।

अगर ऐसा इसमें होता तो बड़ी खुशी की बात होती ।

समवर्ती सूची में शिक्षा को जो आपने रखा यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना जरूरी है लेकिन कृषि जिसके मातहत भूमि सुधार, अन्न उत्पादन आदि बहुत सी चीजें आती हैं उस को भी समवर्ती सूची में न लाने से बहुतेरे लोगों में थोड़ी निराशा हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गौर करे ।

साथ ही साथ राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में आज माननीय सदस्यों ने, सही बात कही कि हमारा दर्पण है संविधान और उसमें वह अपना चेहरा नहीं देखती है तो उसे निराशा होती है इसलिए राष्ट्रभाषा जो इस देश की लोक भाषा है उसको अवश्य स्थान मिलना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार इस आशा के साथ समर्थन करता हूं कि शीघ्र ही हमारी प्रधान मंत्री, और विधि मंत्री, जैसा आपने संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्म निरपेक्ष शब्दों को रखा है, तत्काल दूसरा संशोधन विधेयक लाकर इसको और अनुकूल बनायेंगे ताकि देश में 80 प्रतिशत जो गरीब लोग हैं जो कि शोषण से कराह रहे हैं वह शोषणमुक्त हो सकेंगे । मुझे आशा है ऐसे लोगों की रक्षा के लिए आप शीघ्र कदम उठायेंगे ।

SHRI M V KRISHNAPPA (Hoskote) I am very glad to suport the 44th Amendment After the third reading will be 103rd amendment of the Constitution Some of us one times are suprised why has there been 103 amendments in the course of 27 years? Did the respected, esteemed founding fathers of the Constitution not have so much of foresight to see the coming future and the development? It is also felt, if they would have kept the spirit and the substance of this very amendment as a part of the whole Constitution, India would have made much of progress by this time and we would have had lesser problems As was explained by some of our friends, the very character of the Constituent Assembly which framed this Constitution was peculiar There were no elected representatives at that time as most of them were nominated from certain places, such as Rajas, Nawabs etc The only redeeming feature of the Constituent Assembly was that our vetoran Congress leaders were there Men like Pandit Jawaharlal Nehru had to compromise on the very very fundamental and basic issues to bring unanimity in that Constitution. One of the basic and fundamental things on which he had a compromise was caste system But caste system is still the cancer of the Indian body-politic It is eating the bones of the Indian society We have not abolished it Even to day after 27 years of democracy, Yadav votes for Yadav, Reddi votes for Reddi Vochalika votes for Vochalike Mudahar votes for Mudaliar Where is the democracy in this country? Do we call it a casteless and classless society? Caste must go if India has to be a real democratic country

The second thing on which Nehru compromised was the bureaucracy There were so many ICS people Even the people who represented constituencies were IAS and ICS people He gave the greatest protection to them In the world you see either the communist or capitalist countries Bureaucracy had as much of freedom in this country as they have in any other country In a communist country when they come to power, they put their own party men

In capitalist democracy, when Carter is elected, he will bring thousands of his own persons to executive posts to carry out the promises which he made to the country But unfortunately in this country the ghosts of British bureaucracy still haunt the secretariats of Delhi and the States The Under-Secretary, Upper-Secretary, Down-

[Shri M. V. Krishnappa]

Secretary etc. are still there and it is they who execute our programmes, whether communist or socialist. It is no wonder the constitution had to undergo 103 changes so far. Do you think this is final? Not at all. Very soon we will have to go in for more amendments. That is why there is logic in the argument of many of my friends here who said that we may re-cast the constitution and have a constituent assembly for the purpose. Within 5 years there is going to be a younger generation in the country; the leadership is going to fall into the hands of the younger generation. The masses are getting awakened; people are getting enlightened; and our constitution must reflect their hopes and their aspirations.

The private property is something which should have a limit. There should have been a limit fixed to private property. They did not do it in the constitution. When we have unlimited private property on the one side corruption will go on like this. The big industrial houses which had an amount of Rs. 20 or Rs. 30 crores as assets during the time of our independence have now amassed Rs. 800 or Rs. 900 crores. It is also the same position with agriculture to some extent. The wealth of the country and the means of production (both in agriculture and in industry) is concentrated in a few hands in about ten per cent of the population and the rest ninety per cent still remain poor. The legal quibbling and constitutional quibbling may go on between high courts and supreme court but still the problem of the have-nots in the country has not been solved. The have-nots demand employment, food, and so on. The haves do not want to give away their wealth. They want fundamental rights to safeguard their own interests. Therefore I say that these legal and constitutional quibblings going on in the country regarding fundamental rights and so on are nothing but an impediment to wealth flowing from the haves to the have-nots. The people are awakening now and the rich people are bound to go.

If Indira Gandhi had not come on the scene in 1969-70 the Naxalites would have killed all the rich people in the country. They started from one place and they went on killing people. It is Indiraji who gave a halt to this movement. She said, 'I am going to do it constitutionally, I am going to do it peacefully, please don't take law into your own hands; we shall bring in the necessary legislation.' The people are awakening. Their aspirations and their wishes have to be reflected in the constitution and within 4 or 5 years we shall have a different constitution. With these words I support the Constitution Amendment Bill.

श्री राम देउरू (रामटेक): अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बिल बड़ी जल्दबाजी में पास हुआ है, जिसकी वजह से इसमें कई त्रुटियां रह गई हैं। जनता की मंशा को पूरा करने की दृष्टि से यह बिल पर्याप्त नहीं है। आज आजादी के बाद जो बढ़ती हुई विषमता, भूख, गरीबी और गरीबों का जो शोषण हो रहा है, उसको रोकने के लिये यह संशोधन सफल सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसमें कई धाराओं की मूल-भूत संशोधन होना जरूरी था, परन्तु वह नहीं हुआ। हम यह उम्मीद करते थे कि एक संविधान सभा गठित की जाएगी और उसमें उन संशोधनों पर गहराई के साथ विचार करने के बाद संविधान में संशोधन किया जायेगा। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। ऐसा करने की आवश्यकता हमें बहुत जल्दी महसूस होगी और इस पार्लियामेंट को भी महसूस होगी और एक काम्प्रीहैंसिव बिल संविधान में संशोधन करने का निकट भविष्य में लोक सभा में पारित करने के लिए लाया जायेगा। इसमें जो कुछ जोड़ना था उसके लिए हम ने भी एक संशोधन दिया था और वह यह था कि शोषण रहित, समाज का निर्माण हो। इस बिल में जो यह शब्द "सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक

धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य" रखे हैं, उनमें "शोषण रहित समाज" शब्द भी डालना बहुत जरूरी था क्योंकि जब तक शोषण हमारे देश में जारी रहेगा तब तक समाजवादी व्यवस्था का हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। गांधी जी से भी इस देश में ऐसे ही समाज की अपेक्षा की थी। जिस देश में इस प्रकार का शोषण नहीं होगा और जो आदमी आर्थिक, शारीरिक, बुद्धि और किसी और भी कारण से कमजोर है, उसका कहीं भी शोषण नहीं होगा और ऐसे शोषण को गुनाह माना जायेगा, यह अपेक्षा गांधी जी ने की थी और वही अपेक्षा इस संशोधन विधेयक के द्वारा थी, लेकिन उसको इसमें स्वीकार नहीं किया गया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम शोषण को जारी रखना चाहते हैं? आज हम देखते हैं कि पूंजीपति शोषण कर रहे हैं, बड़े-बड़े जमींदार शोषण कर रहे हैं, बड़ी जाति वाले शोषण कर रहे है, जिनके पास धन है वे शोषण कर रहे है, जिनके पास पावर है, वे शोषण कर रहे है और जिस तरह से एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, वह सब हो रहा है। यह चीज मेरी समझ में नहीं आती है। इस चीज को जारी रखते हुए क्या हम समाजवाद ला सकेंगे। यह सब कुछ इस में नहीं है और इस संशोधन में काम का अधिकार भी नहीं है। इसमें अगर उचित प्राथमिक देने की व्यवस्था होती, तो बहुत अच्छा होता। यह सही है कि हम ने बहुत से अधिकार कम कर दिये हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें काम का अधिकार देने की बात होनी चाहिए थी। आज भी हम ने उस अधिकार को देने की व्यवस्था इस बिल में नहीं की है और जब तक हम ऐसा नहीं करते हम सही माने में समाजवाद नहीं ला सकते। जब तक जनता की इच्छा की पूर्ति नहीं होती और उसको न्याय भी सस्ता नहीं मिलता तब तक समाजवाद नहीं आ सकता है। इसमें जो व्यवस्था की गई है उसमें जनता को सस्ता न्याय नहीं मिल सकता, जोकि उसको इन 25 सालों में नहीं मिला है। इस संशोधन से राज्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है। वे जनता की समस्याओं की ओर गौर से देखें और जनता की समस्याओं को बढ़ें और उनका हल निकालें और तुरन्त कार्यवाही करें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक में क्लाज 5 में जो संशोधन है, उसको इतनी चतुराई से बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति संगठित होकर या व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्या या दुःख के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसको वह सहते ही रहना पड़ेगा और इस संशोधन ने जनता के कान, आंख और वाचा पर बंधन लगा दिया है। गांधी जी ने सत्याग्रह की बात हमारे देश के सामने रखी थी। इतनी बड़ी अंग्रेजी सल्तनत को हटाने के लिए जो भी रास्ते अपनाये गये थे, उनसे स्पष्ट था कि जनता अपनी समस्या राज्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता अपनाये, वह शान्तिमय सत्याग्रह का मार्ग था। उस चीज को जनता से छीन लिया गया है क्योंकि अगर वह कुछ बोलती है तो उसको राष्ट्र विरोधी कार्यवाही समझा जा सकता है। उसका वे लोग कोई भी मतलब निकाल सकते हैं। इस तरह से इतनी बड़ी पावर जो जनता के हाथ में होनी चाहिए थी, वह आप ने ले ली है और जनता को शासन कंगाल बनाता जा रहा है। बहुत उपेक्षित आदमियों को, छोटे आदमियों को उठाना है, कमजोर वर्गों को न्याय देना है, उनका उत्थान करना है, उनका संतुलित विकास करना है तो छोटे राज्य बहुत जरूरी हैं।

हम देखते हैं कि बड़े राज्यों में कैसी अव्यवस्था का निर्माण हो जाता है। राज्य का एक मंत्री पांच वर्षों में भी अपने राज्य की सभी पंचायतों के हेड क्वार्टर तक नहीं पहुंच सकता। क्या वह जनता की समस्याएं सुनेगा, कैसे उनको हल करेगा? छोटे

[श्री राम हेडाऊ]

राज्यों में ये बातें नहीं होने वाली हैं। किसी भी राज्य की राजधानी किसी भी गांव से दो सौ मील से दूर नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान) दिल्ली की बात और है वह सारे देश की राजधानी है। अगर केन्द्र को मजबूत बनाना है तो भी छोटे राज्यों का निर्माण बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि बड़े राज्य केन्द्र पर गुर्राते हैं। छोटे राज्य अगर होंगे तो केन्द्र प्रभावशाली बनेगा। चारों तरफ इस देश में एकता दिखायी देगी।

छोटे राज्यों की मांग हम इसलिए रखते हैं कि जिससे प्रशासन शुद्ध हो, संतुलित विकास हो, सभी लोगों पर ध्यान देने की व्यवस्था हो जिससे लोग गरीब न रहें। छोटे राज्य गरीबों के हित में हैं। इसलिए इस सब को देखते हुए छोटे राज्यों के पुनर्गठन, पुनर्रचना का फिर से प्रयत्न करना चाहिए। इस बात को सामने रख कर प्रयत्न किया जाए कि इससे देश की एकता खतरे में नहीं पड़ती है बल्कि मजबूत होती है।

अध्यक्ष महोदय आप बाहर वाली बातों को ज्यादा न लाइये।

श्री राम हेडाऊ · यह जो संविधान में हम परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तित संविधान को हमें जनता के बीच में उपयोग करना है इसलिए इसके नेतृत्व के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। मेहनतकश लोगों का यह देश है। यह देश है गरीबों का; छोटे किसानों का, मजदूरों का, श्रमिकों का, हरिजनों का और गिरीजनों का। इस देश में 90 प्रतिशत लोग इस प्रकार के रहते हैं। किन्तु दुख इस बात का है कि जो पूंजीपति हैं, जातिवाद पर आश्रित हैं, उनके हाथ में सत्ता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि दस प्रतिशत लोग 90 प्रतिशत पर राज्य कर रहे हैं। इन 90 प्रतिशत लोगों को इंसाफ मिलने की हमें गुंजाइश नहीं दिखायी देती। इसलिए मैं चाहता हूं कि 90 प्रतिशत लोगों का नेतृत्व सामने आए। ये युवक कांग्रेस में जब अधिकतर बड़े घराने के लोग हैं जमींदार लोग हैं ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य . आपको युवक कांग्रेस के बारे में क्या पता है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इसीलिए कहा था कि बिल पर बोलिए बाहर की बातें न लाइए, इसमें आपका भी समय बर्बाद होता है।

श्री राम हेडाऊ : मैंने अधिकतर लोग कहा है।

शासन पर इन पूंजीपतियों का और पूंजी का जो प्रभाव है इसको हमें दूर करना है। प्रशासन पर इसका प्रभाव है। जब तक आप इसको हटायेंगे नहीं तब तक कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है।

आप समाजवाद की बात करते हैं। किन्तु जो साधन हैं वे मुट्ठीभर लोगों के हाथ मे ही सीमित हो गए हैं। जब तक ये साधन इन मुट्ठीभर लोगों के हाथों में से निकाल कर समाज के हाथ में नहीं दिये जायेंगे तब तक गरीब गरीब होता जायगा, अमीर अमीर होता जायगा। इस बात को भी हमे सोचना होगा।

ये जो हमारे यहां उद्योग हैं, जब हम आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें छोटे छोटे उद्योगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

काटेज इंडस्ट्री का गांधी जी ने दिलोजान से समर्थन किया था। सब काटेज इंडस्ट्री को आज खत्म किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसका पुनरुत्थान किया जाए और हाथकरघे का राष्ट्रीयकरण किया जाए।

शिक्षा को केन्द्रीय विषय बना कर बहुत अच्छा काम किया गया है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। एजूकेशन में क्वांटिटी, क्वालिटी, और इक्वैलिटी पर

बहुत जोर दिया जा रहा है। यह बहुत आवश्यक भी है। देश में करीकुलम एक सा होना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि देहात में अलग हो और शहर में अलग। वर्ग निर्माण करने की जो शिक्षा पद्धति है इसको खत्म किया जाए। देहात में भी वही शिक्षा दी जानी चाहिये जो शहर में बच्चों को दी जाती है। जो शिक्षा कानवेंट या पब्लिक स्कूल में मिलती है वही म्यूनिसिपैलिटी के प्राइमरी स्कूल में भी मिलनी चाहिये।

मैट्रिक तक की शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिये। व्यक्तिगत मालिकी में जो शिक्षा संस्थायें चल रही हैं उनको बन्द किया जाना चाहिये। वहां बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। शिक्षकों को तनख्वाह भी पूरी और समय पर नहीं मिलती है। ग्रांट वे लोग ले लेते हैं लेकिन उनका व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दुरुपयोग करते है।

मुझे समय बहुत कम दिया जा रहा है। मैं समाप्त करता हूं। मैं इस बिल का आंशिक समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्र सैलानी (हाथरस) आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। 44वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया गया था वह अंतिम चरण में है और आज शाम तक पास हो जाएगा। मैं इसका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता हूं कि संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब से हम आजाद हुए हैं अनेक बार संविधान में संशोधन किए गए हैं। उसका नतीजा यह है कि आज भी समय परिस्थिति और समाज के अनुकूल जो विधान होना चाहिये था वह देश को नहीं मिल पाया है। मैं आशा करता हूं कि कानून मंत्री इस पर गहराई से विचार करेंगे और शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि विधान में आमूलचूल परिवर्तन हो सके। कितने ही दिनों से इस पर बहस चल रही है। मेरे पूर्व साथी जो बोले हैं उन्होंने विस्तार से अपने विचार यहां पर रखे हैं। जो एक आध बात रह गई है उस पर मैं आपका विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तीस साल की आजादी के बाद भी देश में इस तरह की व्यवस्था चली आ रही है कि जो काम नहीं करते हैं, जो बेकार हैं, जो निकम्मे हैं और अगर उनको हरामखोर भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी उनके ऊपर अंकुश अवश्य रखा जाना चाहिये। जिन को पता नहीं कब सूरज निकलता है कब डूबता है इसके बावजूद भी उनके पास अथाह सम्पत्ति है। उन पर अंकुश अवश्य लगना चाहिये। दूसरी तरफ वे लोग हैं कड़ाके की सर्दी में और धूप में काम करते है, किसान खेत में पानी लगाता है; मजदूर कारखानों में काम करता है सुबह से लेकर शाम तक, जो मेहनतकश लोग हैं जो चोटी से लेकर एडी तक पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जब वे स्वयं या उनके बच्चे बीमार पड जाते हैं तो इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, कपड़े, मकान आदि की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि जो मूलभूत अधिकार है उन में काम करने के अधिकार को भी सम्मिलित किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

13.00 hrs.

देश का सबसे बड़ा विनाश जातिवाद ने किया है, ऊंच नीच; छोटे बड़े की भावना ने किया है। इस रोग वजह से समाज दुर्बल बना है, कमजोर बना है और आज भी यथा स्थिति चली आ रही है। आज भी हम देखते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं कि जाति-वाद के नाम पर छूआछूत ऊंच नीच के नाम पर इंसान इंसान के साथ नफरत करता है;

[श्री चन्द्र शेखर]

अमानवीय व्यवहार करता है, अमानुषिक कार्य करता है । उनके साथ ज्यादती होती है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन की स्त्रियों और बच्चों को जला दिया जाता है और उन के साथ अमानुषिक कार्य किये जाते हैं । उन को पेड़ से बांध कर लटका दिया जाता है और मारा जाता है । 30 साल की आजादी के बाद भी देश में कोई ऐसा गांव, कस्बा या शहर नहीं है जहां यह समस्या न हो और ऊंच नीच तथा जातिवाद का बोलबाला न हो । मेरी मांग है कि डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में इरेडिकेशन आफ अनटचेबिलिटी को जोड़ा जाय । आज भी बहुत से लोग अपने नाम के पीछे उपनाम लगाते हैं । इस प्रथा को कानूनी तरीके से बैन कर दिया जाय क्यों कि नाम सुनते ही मालूम पड़ जाता है कि कौन व्यक्ति किस जाति का है और इस से भ्रम पैदा होता है तथा जातिवाद को बढ़ावा मिलता है ।

मैं हमेशा से कह रहा हूं कि जातिवाद को मिटाना चाहिये और इस के लिये यह आवश्यक है कि अन्तर्जातीय और अन्तर-प्रान्तीय शादियों को प्रीफरेंस दिया जाय और भारतीय संविधान में यह लिखा जाना चाहिये कि जो लोग अन्तर्जातीय और अन्तर्प्रान्तीय शादियां करेंगे उन को नौकरियों में, व्यापार में और प्रगति के रास्ते पर बढ़ने के लिये हर तरह की मदद दी जायगी ।

मैं हमेशा से शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में रहा हूं । शिक्षा को जो इस वक्त स्थान दिया गया है उसका तो समर्थन करता ही हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश में जो लोग यह समझते हैं, महसूस करते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति में दोष है और यह दुरुस्त होनी चाहिये, वह मेरे विचार से सही है । एक तरफ तो देश में ऐसे लोग हैं जिन को चुंगी के प्राइमरी स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती दूसरी तरफ पैसे वाले लोग अपने बच्चों को कान्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं और नतीजा यह होता है कि आज जो नौकरशाही की आलोचना होती है उनका सब से बड़ा कारण यही है कि बड़े बड़े खानदान के लोग, पूंजीपतियों और अफसरों के बच्चे ही तमाम अखिल भारतीय सेवाओं में आ पाते हैं और वही हुकूमत करते हैं । उन की जहनियत जो अंग्रेजों के जमाने में थी आज भी वही है, उस में कोई फर्क नहीं आया है, केवल रंग और शक्ल बदल गई है, पर जहनियत वही आज भी कायम है ।

13.03 hrs

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मेरे बहुत से साथियों ने नौकरशाही की आलोचना करते वक्त यह कहा है कि उस के लिये भारतीय संविधान में कोई प्रावधान होना चाहिये । मैं चाहता हूं कि इस तरह का प्रावधान हो । लेकिन उस से भी अधिक महत्व की बात यह है कि उन की मनोवृत्ति को बदलना होगा क्यों कि हम देखते हैं कि जब हम लोग गांव, शहर या जनपद के बीच में जन-प्रतिनिधि होने के नाते जाते हैं और अधिकारियों से वास्ता पड़ता है तो हम यह महसूस करते हैं कि आज के अधिकारियों की मनोवृत्ति में कोई फर्क नहीं आया, फर्क केवल शक्ल और रंग में हो गया है । अंग्रेज गोरा था, लेकिन आज के अधिकारी की चमड़ी और चेहरा भारतीय जरूर है पर दिल और दिमाग में उन के कोई फर्क नहीं आया ।

मैं शिक्षा की बात कर रहा था कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय और शिक्षा के जो मन्दिर हैं, विश्वविद्यालय, कालेज, स्कूल

आदि उन के द्वारा हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की कृपा से सब के लिये खुले हुए हैं यहां तक कि शेडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के बच्चों के लिये भी खुले हुए है और ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिये उन को समान अधिकार दिया गया हैं परन्तु इन शिक्षा मन्दिरों में जो होस्टेल्स है उन में भी शेडयूल कास्ट्स और ट्राइब्स के बच्चों को अनुपात अनिवार्य रूप से तय कर दिया जाय कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी और कालेज में शेडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के विद्यार्थियो की संख्या हैं उसी हिसाब से 10, 15 20 या 25 प्रतिशत के हिसाब से उन्हें होस्टलो में भी रहना चाहिये ताकि सब धर्मों और वर्गों के लोग एक जगह बैठ कर खाना खायें। एक जगह सोयेंगे, एक मैज में खाना खायेंगे और एक साथ चलेंगे. तो उनमें अपनी एकता की भावना पैदा होगी और इस जातिवाद को खत्म करने के लिये वहां पर उनको एक मौका मिलेगा ।

भारतीय संविधान देश की जनता के लिये है । आज मुझे भगवान गौतम बुद्ध का वह सिद्धान्त याद आता है---बहुजन हिताय बहुजन सुखाय । हमारा संविधान इसी आधार पर होना चाहिये जिससे बहुत से लोगों को लाभ हो । वैसे आलोचना करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत से लोग हैं, लकिन हमें यह मानकर चलना हैं कि हम क्या कर रहे हैं । हमारे विधान से ऐसे लोगों को हर तरह का मौका मिलना चाहिये जो कि आगे बढ़ना चाहते है।

अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह जो संशोधन पेश किया गया है, इसका तो मैं हृदय से समर्थन करता हूं लेकिन हमारे जैसे शोषित समाज के लोग उस दिन खुश होंगे जिस दिन इस संविधान में आमूल चूल परिवर्तन होगा और यहां पर कोई सताया नहीं जायेगा किसी का शोषण नहीं होगा और हर इंसान को रोजी और रोटी मिलेगी और आगे बढ़ने के लिये मौका मिलेगा ।

मैं जिस सिद्धान्त में विश्वास करता हूं उसके अनुसार अगर कोई अच्छे मकान में रहता हैं, अच्छा खाता हैं अच्छा पहनता हैं तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं हैं लेकिन गरीब को रोटी जरूर मिलनी चाहिये चाहे बेझड़ की हो, पहनने के लिये लंगोटा हो चाहे गाढा हो और रहने के लिये मकान हो चाहे झोंपड़ी हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

SRI LILADHAR KOTOKI (Nowgong): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the amendments proposed in this Bill. Sir, I consider this day as a day of deliverence in more than one sense. Firstly, it has restored to this Parliament its rightful constituent powers which were kept under clouds for a number of years. Secondly, it has put the common interest over the vested individuals' rights. Thirdly, the elements that thwarted the implementation of various programmes for the common good, common interest and common welfare, namely, anti-social elements in this country, have also got to be put under proper check so that the entire people and set up, particularly the poor, backward and the weaker sections of our people are going to be delivered from oppression and given the hope that has been promised since the day of independence. That is why I say that although there are several stages to go through till these provisions become operative, even so this day is a very remarkable day, very significant day. I need not go into the various provisions, all of them are important. But the significant one, to my mind, is the amendment of the Article 368 itself. That has been passed in this House with all the legal and constitutional arguments. I need not go into them. The second one is the Preamble itself. We have asserted that the preamble is an integral part

[Shri Liladhar Kotoki]

of the Constitution in order to show the way where we are going and in that the insertion of these two words "Socialist Secular" are very important. In our manifesto for 1971-72 elections we indicated the various steps that are necessary in order to take our country forward and the first war was to be launched against the poverty.

In article 68 of our election manifesto, we have said like this: Poverty must go. Disparities must diminish. Injustice must end. There are but essential steps towards our ultimate goal—the goal of an India which is united and strong, an India which lives up to its ancient and enduring ideals and yet is modern in thought and achievement, meeting the future with vision and confidence. That is where we have to reach and by this Constitution (Amendment) Bill, all the road blocks will be removed. I urge upon the government that they should come forward with all the measures that are necessary and that could not be undertaken because of these hurdles, in as short a time as possible, so that we can take concrete steps and achieve tangible results to sustain the confidence of the people in our Parliament and in the government. I would not like to go into details, but these provisions indicate in what manner legislative and executive action will have to be undertaken.

So far as socialist republic is concerned, socialism cannot be brought about unless we take the whole people with us. That is why it is essential that in our plan we must associate the people in the process of planning itself. Then only we can expect that they will cooperate with their whole heart in the implementation of the various programmes of the plan. The fifth plan is going to be over in another two years and it has been finalised only recently. I submit that we have to initiate measures from now on to associate the people, particularly in the case of rural development, so far as the sixth plan is concerned. All the necessary infrastructure like power, irrigation, communication, etc. should be initiated in these two years of the fifth plan. Unless we do that, we will be faced with other hurdless and there will be delay. Delay means danger. If we delay the rooting out of poverty in the shortest possible time, the dangers we are seeking to avoid by these provisions perhaps may not be removed.

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। हम लोग उस पीढ़ी के हैं, जो स्वतंत्रता-संग्राम के सेनानियों की अन्तिम पंक्ति में दाखिल हुई। जिस संविधान से आज देश का प्रशासन चल रहा है, उसकी शुरुआत 19 सितम्बर, 1946 से हुई। ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन ने हमें यह अधिकार दिया था कि हम संविधान सभा के माध्यम से अपना संविधान बनायें। 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बाद में स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् उसका रूप बदल गया और अधिक लोगों को सम्मिलित करके संविधान बनाने का कार्य प्रारम्भ हुआ। लेकिन इस संविधान को बनाने वाले लोगों को लिमिटिड फ्रैंचाइज़ के आधार पर चुना गया था। उस संविधान सभा के सदस्य ऐसी विधान सभाओं द्वारा चुने गये थे, जो स्वयं लिमिटिड फ्रैंचाइज़ पर चुनी गई थीं। उस समय जो लोग कुछ पढ़े-लिखे होते थे, या चौकीदारी टैक्स या अन्य टैक्स देते थे, वही वोटर होते थे। आम जनता को वोट देने का अधिकार उस समय नहीं था। ऐसे ही वेस्टिड इन्ट्रेस्ट्स वाले लोगों द्वारा ही यह संविधान बना।

इसका नतीजा यह निकला कि संविधान के बनने के कुछ महीने बाद ही प्रगतिशील काम करने में बाधा उत्पन्न होने लगी और संविधान में संशोधन का काम प्रारम्भ हुआ। आज हम संविधान के चवालीसवें संशोधन पर, जिसको बयालीसवें संशोधन का रूप

किया गया है, विचार कर रहे हैं। किसी भी देश का संविधान वहां के कानूनों के संग्रह की कोई पुस्तिका नहीं है, बल्कि उस देश में बसने वाले लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं की पूर्ति का एक प्रतीक होता है। देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही संविधान का उद्देश्य होता है। जो संविधान उनकी आकांक्षाओं और आशाओं की पूर्ति नहीं कर सके उस संविधान का संशोधन या उसके बदले दूसरा संविधान बनाने का अधिकार वहां के नागरिकों को होना चाहिए। देश के नागरिक ही देश के मालिक हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था संसद् है। संसद् की सुप्रीमेसी होनी आवश्यक है।

अनुभवों के आधार पर हमने देखा है कि जो भी प्रगतिशील कार्य देश के सामने उपस्थित होते हैं उनमें कहीं न कहीं से बाधा आती है। या तो न्यायपालिका की तरफ़ से बाधा आती है या कार्यपालिका की तरफ़ से बाधा आती है और जो देश की असली 55 करोड़ जनता है उनके लाभ की जो बात होती है वह कार्यान्वित नहीं हो पाती। प्रायः उसमें ये कानून ही बाधक बन जाते हैं। लेकिन हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस संविधान में संशोधन लाकर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को स्थापित कर दिया और देश के सामने जो यह संस्था आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है, आम जनता की आकांक्षाओं और आशाओं का प्रतीक है उसे यह अधिकार दिया कि वह विधान में संशोधन कर सके।

आखिर ये संशोधन हैं क्या जिनसे लोगों को परेशानी है। प्रीऐम्बल में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द जो जोड़े गये हैं यह कोई नई बात नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के समय में ही सेकुलरिज्म और सर्व धर्म समभाव की बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किया करते थे। उनकी प्रार्थना सभा में सभी धर्म के लोग होते थे और सभी के धर्मग्रन्थों से पाठ हुआ करता था। इसी तरह से समाजवादी पद्धति का समाज बनाने का प्रस्ताव भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के शासन को चलाने वाली संस्था कांग्रेस ने आवडी में पास किया। उससे पहले भी स्वराज्य मिलने से पहले भी यह बात हुई थी कि स्वराज्य के बाद भारत में किस तरह का समाज बनेगा। इसके ऊपर भी स्वतंत्रता संग्राम के लिये लड़ने वाली सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस ने अपने इजलासों में प्रस्ताव पास करके इस बात का संकल्प लिया था कि समाजवादी पद्धति की सरकार बनेगी।

समाजवाद है क्या? यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरने की बात हो। यह केवल आर्थिक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, रहन सहन का तरीका, वे आफ़ लाइफ़ है। केवल किताबी बात करके और इसे कानूनों में ही रख कर समाजवाद नहीं आ सकता है। बल्कि अपने जीवन में समाजवाद के अनुरूप परिवर्तन करने से असली समाजवाद की स्थापना हो सकती है। आज समाज में किस तरह की विषमता है यह हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। आज कुछ वर्गों के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है और कुछ लोगों के बाथ रूमों से इतना पानी बहता है कि सड़क पर पानी आ जाता है। किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है और किसी के घर में पांच पांच पाखाने और नहाने के कमरे बने हुए हैं। आज स्वराज्य प्राप्ति के 30 वर्ष बाद भी बड़े शहर के किसी स्टेशन पर जाइए, खाना खाते रहेंगे और मांगने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जायगी। जो जूठी पत्तल आप फ़ेकेंगे उसको खाने के लिए कुत्तों और इंसानों में लड़ाई होती दिखाई पड़ेगी। उसके लिए स्पर्धा होती है। यह देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। इस देश की भलाई के लिए कोई कार्यक्रम बनाया जाये और उसके मार्ग में जो भी बाधायें हों उनको हटाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, बिना कर्त्तव्य के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। कर्त्तव्य

[श्री राम शेखर प्रसाद सिंह]

के मामले में जिन बातों को संविधान में जोड़ा गया है वह कोई नयी चीज नहीं है। अनुभव के आधार पर आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय ध्वज एक पवित्र चीज है जोकि स देश के लाखों करोड़ों लोगों के त्याग और बलिदान का द्योतक है। इस राष्ट्रीय ध्वज की बेइज्जती करने वाले लोग आज भी इस देश में मौजूद हैं। कुछ दिन पहले 1953 या 1954 में, जो लोग बिहार से आते हैं उनको मालूम होगा, बी० एन० कालेज के विद्यार्थियों और बस कंडक्टर्स में झगड़ा हुआ जिसके फलस्वरूप गोली चली और राष्ट्रीय ध्वज जलाया गया। उसके बाद इस देश में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि कपड़े के टुकड़े को जला देने से देश की बेइज्जती नहीं होती। वही लोग बाद में इस देश में कुछ विपक्षी लोगों के साथ टोटल रेवोल्यूशन और विद्रोह की बातें कहीं जोकि हम सभी जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह देश बहुत बड़ा है और इस देश के हर कोने में एक जैसी स्थिति नहीं रहती। 18 मार्च, 1974 को बिहार में एक घटना घटी थी जिस दिन आनन्दमार्ग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने विद्रोह खड़ा करके सरकारी इमारतों को जलाना शु कर दिया था। सचैलाइट की बिल्डिंग को भी जला दिया गया था। उस समय अगर हमारे संविधान में पार्शल इमरजेंसी की व्यवस्था रहती तो सम्भवतः आज सारे देश में इमरजेन्सी लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

इन शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि सारे देश के लिये एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिये। सरकार ने शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ कर बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया है जिसका सभी ओर से देश में समर्थन हो रहा है। मैं समझता हूं कार्यपालिका की ओर से जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसमें भी सुधार लाया जायेगा, चाहे विधान के द्वारा अथवा सर्कुलर और आदेशों के द्वारा।

श्री मुल्कीराज सैनी (देहरादून): उपाध्यक्ष महोदय, 44वें संविधान संशोधन विधेयक पर 25 अक्तूबर से 1 नवम्बर तक बहस चली है जिसमें 59 धारायें हैं, इसमें 600 अमेन्डमेन्ट्स दिये गये हैं। इस बीच में हमारे सामने सारे तर्क आ गए हैं कि संविधान संशोधन की जरूरत थी या नहीं। संविधान एक पवित्र और महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जोकि राष्ट्रपति पर भी लागू होता है, प्रधान मंत्री पर भी लागू होता है तथा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर भी लागू होता है। किसी मामूली बात पर उसमें संशोधन नहीं किया जाता बल्कि जब बहुत जरूरत होती है तभी उसमें संशोधन किया जाता है। हमें विपक्ष की अक्ल पर दया आती है कि वे लोग पार्लियामेन्ट में और बाहर सभी जगह जनतन्त्र की हामी भरते हैं लेकिन ऐसे अवसर पर उन्होंने बायकाट कर दिया। जनतन्त्र में जो राज्य करने वाली पार्टी होती है उसके व्यूज के साथ साथ माइनारिटी को भी अपनी व्यूज रखने का अधिकार होता है। वे भी यहां पर अपने व्यूज को रख सकते थे लेकिन उन्होंने बायकाट करना ही मुनासिब समझा। यह कौन सा जनतन्त्र है? हमने यहां पर देखा कि वे अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए। सारे देश में सत्याग्रह करना, धमकी देना, तोड़-फोड़, मार-धाड़ और हिंसा—क्या यही जनतन्त्र है? यहां पर कांग्रेस पार्टी और प्रधान मंत्री की सरकार चल रही है और वे बायकाट किए बाहर बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो महत्वपूर्ण संशोधन किए जा रहे हैं उनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि उनपर काफी रोशनी डाली जा चुकी

है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हमने जो समाजवाद का सिद्धान्त रखा है वह वास्तव में उस समय तक नहीं आ सकता जब तक कि संविधान में प्रापर्टी का राइट रहता है। इसके रहते एक तरफ तो गरीब रहेंगे, लोग भूखे मरते रहेंगे और दूसरी तरफ अमीर लोग ऐश करेंगे। एक तरफ अमीर सोचेंगे कि पैसा कैसे खर्च किया जाय और दूसरी तरफ लोग भूखे मरेंगे। इसलिए बिना ऐसा संशोधन लाये इस देश में कैसे समाजवाद आ सकता है। जनतन्त्र के रहते हुए हम सुनते आ रहे थे कि इस देश में सरकार का लक्ष्य क्या है। एक दफा कहा गया कि कोआपरेटिव कामनवैल्थ है। उस के बाद कहा गया-वैलफेयर स्टेट, जनकल्याणकारी राज्य है, उस के बाद कहा गया—सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी है, फिर समाजवाद की बात आई। अभी तक यह बात संविधान में लिखी नहीं गई थी, आज लिखी जा रही है और लिखे जाने का महत्व यह होता है कि उस पर सारी जनता विश्वास करती है कि वाकई यह सरकार समाजवाद लाएगी। लेकिन समाजवाद केवल संविधान में लिख देने से नहीं आयगा, यह तो रहन-सहन का एक तरीका है, वे आफ-लाइफ़ है, कल्चर है, इसके लिय सब को बदलना होगा, अपने अन्दर परिवर्तन लाना होगा। आज यह सरकार सारा, सदन, रूलिंग पार्टी अपने आप को समाजवाद से बांध रही है, लेकिन इस को प्राप्त करने के लिय अपनी दैनिक चर्या को बदलना होगा, खाने की आदत को बदलना होगा, शिक्षा की आदत को बदलना होगा।

शिक्षा को ही ले लीजिय बारबार यहां पर उस का जिक्र किया जाता है--आज गरीब आदमी को पढ़ने का भी हक़ नहीं है, पढ़ें भी तो म्युनिसिपल्टी और जिला परिषदों के स्कूलों में, जहां न मास्टर हैं, न स्लेट है, न कलम है और न बैठने के लिये टाट है। लेकिन दूसरी तरफ कान्वेन्ट स्कूल्ज़ है, बढ़िया-बढ़िया फैंसी स्कूल्ज़ हैं, जहां बच्चे की पढ़ाई पर चार-पांच सौ रुपया महीना खर्च आता है। यह खुशी की बात है कि अब इस को कान्करेन्ट लिस्ट में लाया गया है और ऐसी आशा की जाती है कि शिक्षा के लिये अब एक राष्ट्र नीति बनेगी और सारे देश में एक-सी शिक्षा चलेगी।

यहां पर कहा गया कि इस हाउस को अधिकार नहीं है-इस संविधान में संशोधन करने का। उन बड़े-बड़े पार्लियामेन्टेरियन्ज़ को जिन्होंने कानून की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, आर्टीकल 368 की याद नहीं रही, जहां इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया कि पार्लियामेन्ट सोवरेन-बाडी है। हमारी प्रधान मंत्री जी, हमारे विधि मंत्री जी, हज़ारों वकीलों ने, प्रोफेसरों ने, बुद्धिजीवी वर्गवालों ने बार-बार इस बात को कहा है, लेकिन ये जो नये किस्म के जनतन्त्रवाली पार्टियां बाहर बैठी हुई हैं, इन को पता ही नहीं है कि आर्टीकल 368 क्या है।

हमारे राष्ट्र में आज अनेकों इस प्रकार के रोग लगे हुए हैं —जैसे क्षेत्रीयवाद, जातिवाद, धर्मवाद, गरीब और अमीर के बीच विषमता की खाई, पक्षपात, भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार इन रोगों का इलाज होना चाहिये, ये ऐसे रोग हैं जिनसे सब कुछ बंटाधार हो जाता है। देश में तस्करी होती है, मिलावट होती है, करों की चोरी होती है, रुपया भरा पड़ा है, लेकिन उस को बाहर निकालने के लिये जो मशीनरी है, उस के बारे अनेकों विचार यहां व्यक्त किये जा चुके हैं। कार्यपालिका अपने तरीके से काम करती है, उन को विशेष अधिकार मिले हुए है। आर्टीकल 311 में इस तरह के संशोधन की जरूरत थी कि कार्यपालिका सरकार की पालिसी को चलाने के लिये कमिटेड होती। आज कार्यपालिका बिलकुल सरकार की पालिसी के उलट चलती है। हम नहीं समझ पाते हैं कि आज विधायिका राज्य कर रही है, पार्लियामेन्ट का राज्य चल रहा है या कार्यपालिका का राज्य चल रहा है।

[श्री मुल्की राज सैनी]

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं—एक जय प्रकाश शर्मा नाम का फायरमैन है। रेलवे के अन्दर उस को कह दिया गया कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैन्टल डिस्टर्बेन्स हो गया है। वह आल इण्डिया इंस्टीच्यूट आफ़ मैडिकल साइंस में जाता है, वे कहते है, कि उस का दिमाग सही है। उस को फिर से ड्यूटी दे दी जाती है, तीन महीने वह डायरी मैन्टेन करता है, लेकिन उस को फिर कह दिया जाता है कि तेरा दिमाग खराब है। वह एम० ओ० के पास जाता है, सी० एम० ओ० के पास जाता है—कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं उस को साथ लेकर मंत्री महोदय के पास जाता हूं, वे कहते है कि इस को दोबारा डाक्टर के पास भेज दो। अफ़सरान कहते हैं रेलवे रेल मंत्री को नहीं चलानी है, हमें चलानी है। आप बतलाइये-रेलवे मंत्रालय को चलाने की ज़िम्मेदारी किस की है? क्या रेलवे विभाग को चलाने की ज़िम्मेदारी रेल मंत्री की नहीं है? यह जय प्रकाश शर्मा 14 महीने से घर में बैठा है, उस को काम पर नहीं लिया जाता है। आज यह हालत है कि आप एक क्लर्क को भी इधर से उधर नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार की छत्रछाया में सब कुछ चल रहा है। हमारे संविधान में कुछ इस तरह का प्रावधान होना चाहिये जिससे ये राष्ट्र रोग खत्म हों।

इन शब्दों के साथ इन संशोधनों का जो संविधान में किये गये हैं समर्थन करता हूं तथा स्वागत करता हूं।

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI (Lakhimpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to speak on the 44th Constitution Amendment Bill which has been before us. We have been discussing it for the last few days. It is going to be accepted after some time.

According to me, it has its origin in the notes circulated by our beloved Prime Minister at the Bangalore session of the All India Congress Committee in 1969. It took over seven years to mature and as a result of that, government have brought this Bill. It will be interesting to see that in the year 1924 under the Chairmanship of late Pt. Motilal Nehru, our Swaraj Constitution was framed.

I am a common man with a little commonsense and representing common people in the House of the People. Therefore, I would like to highlight some of the amendments that have been contained in this Bill. In the Preamble, two words have been amended. One is socialism and the other is secularism. Some may refer to Shakespeare "what is in the name?" But here it has got great meaning. It will give a direction to the framers of the rules and serve as a constant reminder to them and to the legislators and the executive also. These two words, that is, socialism and secularism, have great significance for insertion in the Preamble to our Constitution. Simply inserting these two words will not serve the purpose. There are so many ways to implement them and to work towards those goals.

Now-a-days, India Tourism Development Corporation has been constructing five-star hotels all over the country. They are not constructing six-star or seven-star hotels, because there are no norms of six-star or seven-star hotels. For whom, are they constructing them? There the rent is more than Rs. 200 per day. Mr. 'A' is staying there. But Mr. 'B' will be tempted to stay there, who has no means to defray the expenses. Naturally, he will try to adopt corrupt means for collecting money. This is one of the ways which tempts to corruption. If such luxurious things are there, no socialism can be achieved. This is just an instance. As far as the word "secularism" is concerned, it should have a different connotation for us. We do not accept the connotation of the word "secularism" which is

prevailing in the western countries. But, however, in order to maintain that character, we must first try to remove superstition and blind faith. So long as these things are there among the people, no secularism can be achieved.

As far as education is concerned, it is to play a better role in this direction. It is good that education has been placed under the Concurrent List. In the text-books, undesirable things have been exaggerated according to the whims of the authors. It poisons the mind of the young children. If the mind of the child is poisoned at the formative stage, it is difficult to correct him.

यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथाभवेत्

Lessons have to be prepared in a scientific way. It is difficult to remove what has been once printed in the mind of the child. Government should see that no hatred or prejudice against any faith or religious group or community and region should find place in any text-book.

In this context, I would refer to another clause, unity and integrity of the country. It is good and it is desirable that our country should unite and stand like one man. The integrity of the nation, the unity of the country and the sovereignty of the country should be maintained by all concerned. How can the unity be achieved? Unless and until there is an equality to some extent, to a reasonable extent, there cannot be any unity. To illustrate the point, I may mention, the two pieces of iron can be joined together when those two pieces are heated to the equal degree. If one piece remains cold and the other is heated, then those two pieces cannot be joined together. This anology can be extended to all concerned. Therefore, it should be our attempt to bring about equality among the people and among the regions. The economic imbalances of the regions are also to be removed. Only then we can hope that there will be real integrity, the real unity of the country.

The Law Minister has presented this Bill. He has constructed a great building. It is now for different Ministers to furnish it with good equipment, with decent decoratives and such other things. When it is done the building will be useful, so also the provisions of the Constitution. I have already referred to the things to be done by the Ministry of Education, the Ministry of Industry and the Ministry of Home Affairs. The different Ministries can do many things towards achieving our goals. If it is left only by passing the Constitution Amendment Bill, nothing will be achieved. I wanted to highlight those points and, I hope, the concerned Ministers and the Ministries will pay their undivided attention to those respects.

I support this Constitution Amendment Bill for the reasons I have already stated. I am a common man as I have stated. I do not know the niceties of law, what clause is removed or what clause is modified. But I know that this Constitution Amendment Bill will do. It has established once for all the supremacy and the sovereignty of the House of the People, that means of the Parliament and for that matter, of the people. An eminent saint of Bengal has praised human being:

सबार उपरे मानुस सत्य तहार उपरे नाइ।

In ultimate reality, the man is the truth. There is nothing above the man.

Another thing that this Bill has done is to remove the doubt in the interpretation of the provisions of the Constitution. The Constitution has to be correctly interpreted as it has been intended by the founding fathers of the Constitution.

Last but not the least thing is that this Constitution Amendment Bill

[Shri Biswanarayan Shastri]

keeps in touch with the changing circumstances and it fulfils the hopes and aspirations of the millions of the people who have been starving, who have been deprived of their due, and who are under-privileged in the country. For these four broad reasons, I support and welcome this Bill warmly.

Regarding the integration of the country, I would like to say one thing more. There are two ways of making integration, emotional and cultural. As everybody knows, the emotions rise and fall. With the events, with the changing circumstances, the emotions may rise and the emotions may fall. If we stress more and more on emotional integration and neglect the other side, it will fail to serve the purpose. Therefore, we should see that there is cultural integration in the hearts of the people. That will lead us to the goal.

I would like to conclude my speech with the clarion call given by our Prime Minister to the people which I can repeat in the words of our ancient sage:

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत ।

SHRI AMARNATH VIDYALANKAR (Chandigarh): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I support this Constitution Amendment Bill. I regard it as a very important landmark in India's history of Constitutional, political and social development. I also regard it as a very significant landmark in the brilliant and glorious record of our Prime Minister's dynamic and decisive leadership. In the past decade, India has faced many problems, and whenever we faced any serious problem, our Prime Minister did not surrender before it, but she has taken decisive measures and she has tried to solve the problem. This Constitution Amendment Bill is in the same series of those measures.

We know that, before this Amendment was made, the idea of democracy was being distorted. Any effort to enforce law and order or discipline was termed as an anti-democratic measure. We know what had been happening in this very House and what had been happening outside. A sort of concept was created that democracy meant no discipline, no order. We have taken measures to plug the loopholes, and the whole country has welcomed this measure. When this Amendment Bill was introduced in this House, by and large, the people welcomed it. Here also, in this House also, the Bill has been welcomed and it has received the whole-hearted support from practically the overwhelming majority of the Members of this House. This shows that this House very correctly reflects the opinion and the feelings of the people outside.

In this Bill we have made clear as to what are our aims. Discipline must be enforced, but unless it is voluntary, unless the discipline is purposeful, with some purpose, people will not follow that discipline and they will consider it as coercion. This Amendment has given the purpose of our Constitution; the purpose has been made clear in terms of socialism and secularism. These two terms have been introduced in the Preamble.

Like the idea of democracy, the concept of socialism has also been very much distorted. I was surprised when my friend, Mr. Hanumanthaiya, described Pandit Jawaharlal Nehru as a Fabian socialist and tried to differentiate the socialism of our Prime Minister in certain terms. I think, socialism is not a commodity that differs from country to country. Mr. Swaran Singh has very correctly described socialism; he has said that the society should have full control over the economy; the whole economy should be under social control; the means of production should be in the hands of the society. We have already

taken measures in this direction by the nationalisation of banks and by giving predominance to public sector. We have been taking measures in this direction and we want to proceed on those lines. Socialism of our Party has been the same since the Karachi Resolution was passed under the leadership of Mahatma Gandhi. Since then, all the Congress leaders, whether Pandit Jawaharlal Nehru or our present Prime Minister or the other leaders, have given the same concept of socialism to the country. Therefore, to try to say that the socialism propounded by our Prime Minister is different is not correct. The Congress believes in socialism; we have already taken measures in that direction; and we will proceed on the same lines.

In this Preamble we have also added another word, *viz.*, 'secularism'. In the past many communal parties have tried to exploit politics and tried to mislead people in the name of religion, in the name of language or in the name of parochialism. Now they will be curbed and I expect that no political party will be allowed to be formed under our election law, that bases its ideology on communalism or parochialism or linguism or any kind of casteism. By including the word 'secularism' I think this aim also should be clear and it should be translated in a manner that this country is free from these kinds of divisive forces and divisive slogans.

I am glad that by passing this amendment—I am quite sure this House will pass it to-day—we will be giving a proper place to this Parliament and we have accepted the supremacy of the Parliament, that the constitution will not be challenged anywhere outside this Parliament. So, this is a great gain we will be achieving by passing this amendment.

Similarly, the Directive Principles have been given their proper place. Property rights and other rights will not be a basis on which constitutional amendments or the constitution will be challenged. This is also a great gain.

I think similarly we have clearly accepted the federal idea. Some members raised this question of the federal idea. We have accepted the federal idea but we have also consolidated the unity of India. There is a very thin line between the two, but we have accepted that this India is an entity and one unity. By providing certain measures we have accepted the federal character of the constitution. We have given proper freedom to the States but we have also declared that the country has to remain united and any tendency to divide the country into various parts will be curbed and will not be allowed.

As you have now rung the bell, I do not have much time. I think similarly making education and many other things as concurrent subjects is also a good thing. We have not taken away anything from the States. We have only tried to help them and the Centre is now free to go to the help of the States also and give the correct lead to the country. All this clearly reflects the concept of unity in divergence.

So, I think this Bill contains many elements that should be welcome and I think just as in the country people have welcomed it, we will also pass it and this Parliament will go down in history that they have taken the proper step at the appropriate time and given the constitution a new orientation that is consistent with the needs of the country to-day.

श्री नागेश्वर द्विवेदी (मछली शहर) : उपाध्यक्ष जी, भारतीय संविधान में जो 44वां संशोधन विधेयक पेश हुआ है यह बड़ा ही ऐतिहासिक विधेयक है और इसका देश की

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

जनता पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा है, जनता के हृदय में एक बड़ी भारी आशा का संचार हुआ है और शासन के प्रति जनता की आस्था जागृत हुई है।

संविधान में संशोधन करने के बारे में कुछ लोगों ने कहा था कि इस संसद् को संशोधन का अधिकार नहीं है। संशोधन करने का जहां तक अधिकार है, यह प्रश्न बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रिवीपर्स के समय भी उठाया गया था और उस सम्बन्ध में जो बिल पास हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द भी किया था और उसी आधार पर लोक-सभा भंग करके जनता से आदेश लेने के लिये 1971 में चुनाव कराये गये और जनता ने दो-तिहाई का बहुमत देकर शासक दल को अपना पूर्णतः समर्थन दिया था। उसके बाद इस तरह की शंकाएं उठाना निराधार और निर्मूल था। संविधान भारत के लिये कोई नई बात नहीं है। भारत में संविधान के अनुसार काम करने की प्रणाली प्राचीन समय से थी। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया की मान्यता में मनुस्मृति सबसे प्रथम संविधान रहा है। लेकिन वह संविधान भी अपरिवर्तनीय नहीं रहा।

मनुस्मृति के बाद, जिसमें बराबर स्मृतियों का परिवर्तन हुआ है, 18 स्मृतियां बनी हैं। हमने देखा है कि किस तरह से बराबर उसमें समयानुकूल और समयानुसार परिवर्तन आया। आखिरी स्मृति पाराशर स्मृति मानी जाती है। उसके बाद जो देश में विशृंखलताएं आईं, हमारे देश में कोई संविधान नहीं बन सका। पहली बार स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश को इस अवसर का मौका मिला कि संविधान बने और उसी स्थिति में हमारे देश ने स्वतन्त्रता के बाद पहला संविधान बनाया है।

इस संविधान में समयानुसार संशोधन हो रहे हैं। आज हमने इतने परिवर्तन किये हैं, संविधान बनने के एक महीने बाद ही संशोधन होने प्रारम्भ हुए और आज 44वें संशोधन तक हम पहुंच गये हैं। यही नहीं, हो सकता है कि कुछ समय बीते तो संविधान में संशोधन ही नहीं, यह संविधान ही हमको बदलना पड़े और पहले के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा संविधान बनाना पड़े। तो देश की जैसी आवश्यकता होगी, उसको देखते हुए परिवर्तन करना पड़ेगा। संविधान देश की जनता के लिये है, राष्ट्र के लिये है, राष्ट्र संविधान के लिये नहीं है। इसलिये यह कहना कि संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वह भ्रम है और गलत रास्ता है। हमारे यहां की परम्परा प्राचीन रही है और आज भी दुनिया के देशों में जहां संविधान बने हुए हैं, वहां संविधान में परिवर्तन होते रहे हैं। अगर कहीं कोई परिवर्तन न करता रहा हो, तो भारत ने इस मामले में प्राचीन काल से लेकर आज तक पथ-प्रदर्शन किया है कि वह परिवर्तन हो सकते हैं।

संविधान की भूमिका में ही जो हमारा उद्देश्य था, उसमें स्पष्ट किया गया कि अब तक लोकतन्त्रात्मक गणतंत्र के रूप में हम इस देश के विधान को मानते थे और इस समय इसमें धर्म निरपेक्षता और समाजवाद भी जोड़ा जा रहा है।

जहां तक हमारे देश की परम्परा है, विदेशियों ने या विदेशी इतिहासकारों ने चाहे जो कुछ लिखा हो, लेकिन हमारे देश की संस्कृति सहिष्णुतापूर्ण रही है। इसमें सबको एक समान दृष्टि से देखने की बात रही है। अगर उसके इतिहास का अध्ययन किया जाये तो देखा जायेगा कि भेदभावमूलक नहीं रही है। यह तो शासन करने वालों ने इस तरह का भेदभाव किया कि आज तक हम पिछड़े हुए हैं। आज कहना पड़ रहा है कि जातिभेद को मिटाना चाहिये।

एक समय था, जब जातियां बनी थीं, अगर आप और करेंगे तो वह जातियां आप

करने, पेशे के आधार पर बनी थीं । लेकिन आज वह पेशे नहीं हैं, फिर भी जातियों का नाम रह गया है । जब पेशा नहीं है तो उस जाति का बोधक नाम रखने के क्या लाभ है? उस नाम को मिटाना चाहिये और हटाना चाहिये । आज जो जिस तरह का पेशा करता है, उसके नाते उसको कहा ही जायेगा चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हिन्दू हो चाहे मुसलमान हो । अगर कोई सिलाई का काम करता है, तो उसे दर्जी कहा ही जायेगा, दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता । जो व्यापार करता है, उसे व्यापारी कहा ही जायेगा, चाहे किसी जाति का हो । इसी तरह से अगर पेशे के आधार पर बने तो अच्छा है, लेकिन आज जो परम्परा के नाम पर जातिवाद है, सचमुच उसके साथ लगे रहना ठीक नहीं है । लेकिन जब तक इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है, लोग उसका प्रयोग करते हैं, चाहे जायज हो चाहे नाजायज और उसका फायदा उठाया जाता है । इस तरह से अगर संविधान में आगे परिवर्तन किया जा सके तो बहुत अच्छी बात होगी ।

मौलिक अधिकारों बनाम निदेश तत्वों का प्रश्न भी उठाया गया है । मौलिक अधिकारों को व्यक्ति के लिए सीमित किया गया है, जब कि निदेशक तत्वों के माध्यम से सरकार को कुछ सार्वजनिक काम करने का आदेश दिया गया है । जहां तक व्यक्ति का सम्बन्ध है, उसको समष्टि की तुलना में कभी भी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है । हमारे नीति-शास्त्रकारों ने कहा है :

> त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे, ग्रामार्थे कुलं त्यजेत ।
> ग्रामं जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत् ।।

अर्थात् अनेक के लिए एक का परित्याग करना पड़ेगा । इसलिए मौलिक अधिकारों की तुलना में हमें निदेशक तत्वों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऊंचा स्थान देना चाहिए, जैसा कि इस संविधान में किया गया है, और वह हमारे देश के लिए बहुत ही अनुकूल है ।

इस संशोधन के द्वारा न्यायालयों के काम की सीमा बांध दी गई है । केन्द्रीय सरकार को यह भी देखना चाहिए कि हमारे न्यायालयों में किस तरह से काम होता है । हमारी आम जनता नीचे के न्यायालयों से परेशान है । वहां किस तरह से काम होता है, यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । हमें न्यायालयों की पद्धति में परिवर्तन करना पड़ेगा ।

अगर मैं भूलता नहीं हूं, तो अंग्रेजों ने—ईस्ट इंडिया कम्पनी ने—इस देश में पहली बार वारेन हेस्टिंग्ज के जमाने में न्यायालय स्थापित किया । उस अदालत के सामने पहला मुकदमा महाराज नन्द कुमार का था, जिनको जाली सुबूत पेश कर फांसी दे दी गई । जिस अदालत में पहले मुकदमे का फैसला इस तरह हुआ यह आशा नहीं की जा सकती है कि उससे निकली हुई अदालतें लोगों को न्याय दे सकेंगी । देश की जनता को इन अदालतों पर विश्वास नहीं है । हमें सोचना चाहिए कि हमारे न्यायालयों में क्या पद्धति अपनाई जाये, जिससे बिना खर्च किए हुए लोगों को न्याय मिल सके । आज स्थिति यह है कि न्याय बहुत महंगा है और जिसके पास पैसा नहीं होता है, वह मुकदमा हार जाता है । हमें कोई नया ढंग अपनाना पड़ेगा, जिससे लोगों को न्याय के बारे में विश्वास हो । न्याय व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करने के बारे में सरकार को गहराई से सोचना चाहिए ।

जहां तक भेदभाव का सम्बन्ध है, अन्य बहुत सी जगहों के अलावा सरकारी क्षेत्र में भी, अधिकारियों में भी, भेदभाव है । प्राचीन काल में जब अर्जुन रथ पर सवार थे, तो उनके साथ कृष्ण भगवान भी रथ पर थे । उनमें कोई भेदभाव नहीं था । लेकिन आज चपरासी और अफसर में भेद भाव है । चपरासी अपने अफसर के सामने

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। सरकारी कार्य के अलावा सामाजिक क्षेत्र में जो भेद भाव बरता जाता है, उसको भी मिटाना चाहिए।

समय कम होने के कारण अधिक न कह कर मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो टी० डी० कांबले (लातूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन और स्वागत करता हूं। देश की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और 20-सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस विधेयक की अत्यन्त आवश्यकता थी। इसलिये मैं सरकार और विधि मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं।

पहले कुछ विधिवेत्ता बार-बार यह प्रश्न उठाते थे कि धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद गवर्नमेंट की पालिसी बताये जाते हैं, मगर संविधान में उनका कहीं जिक्र नहीं है। इस संशोधन के द्वारा "सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर "सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य" शब्द प्रीएम्बल में डाल कर संविधान में धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद की नीति का समावेश कर लिया गया है। इस प्रकार एक संदिग्ध बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है, जो अत्यावश्यक था।

14.00 hrs.

इस संशोधन के द्वारा संविधान में दस मूल कर्तव्य रख दिये गये हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी से पहले भी और आजादी मिलने के बाद भी बार-बार कहा करते थे कि हर एक आदमी अपना अधिकार चाहता है, और सामुदायिक तौर-पर भी लोग अधिकार चाहते हैं। लेकिन अधिकार के साथ कर्त्तव्यों की पूर्ति होना आवश्यक है। वह कर्त्तव्यों की पूर्ति इस संविधान के अन्तर्गत आ गई है। इसलिए भी यह बहुत ही लाभदायक जनता और देश के लिए होगा।

मूल कर्त्तव्यों के अन्दर जो पांचवां कर्त्तव्य बताया है—भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका परिपालन कैसे होगा इसके बारे में दो शब्द मैं कहूंगा।

आज भी इस देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो जातीयता और अन्धविश्वास फैलाना चाहती हैं। ऐसी कुछ संस्थाओं को आपने बैन किया है, प्रतिबन्ध लगाया है जो राष्ट्र के अन्दर जातिवाद को फैलाने में मदद करती थीं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि ऐसे साहित्य पर भी आपको प्रतिबन्ध लगाना होगा जिनके अन्दर ऊंच नीच, जातीयता और भेदभाव की भावना भरी हुई है जिससे अस्पृश्यता और कई अहितकर बातें समाज म फैली हुई है। यह बहुत जरूरी है कि ऐसे साहित्य को भी बैन किया जाये जिससे लोगों में भेदभाव की प्रवृत्ति पैदा होती है।

साथ ही आप ने एक और अच्छी बात विधेयक में की है कि शिक्षा को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में लेने वाली है। मैं यह कहूंगा कि आप इस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जितनी भी हमारी पाठ्य पुस्तकें हों उनके अन्दर जातीयता उन्मूलन और सभी तरह के भेदभाव मिटाने के लिए पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि आने वाली अगली पीढ़ी का दिमाग इस बात के लिए तैयार हो कि इस देश में कोई जातिवाद या ऊंच नीच की भावना हमारे अन्दर नहीं आनी चाहिए। जैसे आपने इसमें शिक्षा का

भी जिक्र किया है जो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आती है। उस में आप देखेंगे कि बहुत से लोग खानगी संस्थाएं खोल लेते हैं और उस के अन्दर वे लोग अपनी-अपनी शिक्षा पद्धति के अनुसार अपना अपना कार्यक्रम चलाते है। मैं आप से यह कहूंगा कि ऐसी संस्थाएं जहां पर जातिवाद का फ़ैलाव होने की गुंजाइश है जहां शिक्षक से लेकर चपरासी तक सभी लोग उन्हीं के रख लिए जाते है, जहां उस जाति के अलावा दूसरे किसी को नहीं लिया जाता है, ऐसी संस्थाओं के ऊपर आप का ध्यान जाना चाहिए। जातीयता को मिटाने के लिए और समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करने के लिए पाठ्यक्रम के अन्दर इन बातों को लाना चाहिए। इस के साथ-साथ जो ऐसी संस्थाएं है जिन के द्वारा जातिवाद का फ़ैलाव होता है उन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है होस्टलों में और शिक्षा संस्थाओं में कि उसी जाति के लोगों को लिया जाता है जिन के हाथ में शिक्षा संस्था होती है। तो इस के ऊपर ध्यान रखा जाय और मैं विधि मंत्री जी से खास तौर से कहूंगा कि जहां कहीं प्रसंग आ जाता है पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने का और शिक्षा संस्था को सुधारने का हो, वहां उस के अन्दर ऐसी बातों को रखा जाय जिस से हमारे इन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

मेरे मित्र ने स्मृतियों का उदाहरण दिया। मैं सारी स्मृतियों के खिलाफ़ नहीं हूं लेकिन कुछ स्मृतियां ऐसी हैं जिन के अन्दर ऐसी बातें हैं। हो सकता है उस में मिलावट हो या यह भी हो सकता है कि उन के अन्दर वह पहले से विद्यमान हों। तो ऐसी पुस्तकों, धर्मग्रन्थों और स्मृतियों को जिन के अन्दर जातीयता, भेदभाव और अस्पृश्यता को बढ़ाने वाली बातें कही गई हैं सरकार क्यों नहीं बन्द करती है? अस्पृश्यता और ऊंच नीच ऐसी चीजें बन्द होंगी तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। समाज के अन्दर आज भी धर्म प्रतिष्ठा के नाम पर अन्धविश्वास के नाम पर यही चीजें चलती हैं और उन के जरिए इन्हीं किताबों का प्रचार होता रहता है जिस से लोगों के अन्दर एक दिमागी बुराई भर जाती है। इसलिए ऐसी भावनाओं को दूर करने के लिए शिक्षा संस्थाओं को और शिक्षा के अन्दर पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों को फ़िर से देख लीजिए और उसका उन्मूलन करने की कोशिश कीजिए।

आखिर में मैं एक बात और कहूंगा। हमारे देश का संविधान हमारे देश की भाषा में हो तो ज्यादा शोभा देता है। हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है लेकिन एक परकीय देश की अंग्रेजी भाषा में आज संविधान बना हुआ है यह शोभा नहीं देता। हो सकता है आज उस के लिए कुछ अन्य कारण हों या उस में कुछ असुविधा हो लेकिन आगे चल कर ऐसी सुविधा निकाली जाय जिस से कि देश का संविधान अपने देश की भाषा में बना रहे जिस से लोगों को उस का परीक्षण करने में और पढ़ने में सहूलियत हो। अन्त में मैं फ़िर से इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम भगत पासवान (रोसेरा)। उपाध्यक्ष महोदय, मैं 44 वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संविधान विधेयक से जनता की कुछ मोटी मोटी आकांक्षायें और आशायें जाग उठी हैं। पहले का संविधान जिस पर राजा-महाराजाओं और पूंजीपतियों की छाप थी, उसको हटाकर हमारे प्रधान मंत्री ने उस पर भारत की कोटि कोटि जनता की आकांक्षाओं और आशाओं की छाप दे दी है। आज भारत की जनता महसूस कर रही है कि समाजवादी व्यवस्था में अब कोई भी अड़ंगा नहीं लगेगा। इस संविधान संशोधन विधेयक के अन्तर्गत आर्थिक और सामाजिक

[श्री राम भगत पासवान]

व्यवस्था की गई है। लेकिन आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भारत के अन्तर्गत जो भूमि है वही वास्तविक सम्पत्ति है । जब तक देश में लैंड रिफार्म्स का कार्यक्रम अच्छी तरह से लागू नहीं होगा, जब तक भूमिहीनों को भूमि नहीं मिलेगी तब तक भारत की आर्थिक अवस्था में वास्तविक सुधार नहीं आ सकता है। अभी लैंड रिफार्म्स के कानून के अन्तर्गत जो यूनिट की व्यवस्था है कि एक यूनिट के अन्तर्गत परिवार में इतनी भूमि मिलेगी उसके चलते लोग 10-20 यूनिट दिखा देते हैं जिसके फलस्वरूप सारी भूमि उन्हीं के नाम रह जाती है । गरीबों को बांटने के लिए भूमि नहीं मिल पाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि लैंड रिफार्म्स के अन्तर्गत जो यूनिट की व्यवस्था की गई हैं उसको हटा दिया जाये ।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, जब तक गरीबों मजदूरों के लड़के और पूंजीपतियों के लड़के एक स्कूल में साथ-साथ शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक समाज में समानता नहीं आ सकती है । बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लड़के तो उच्चकोटि की शिक्षा प्राप्त करते हैं और बड़े-बड़े पद प्राप्त कर लेते है लेकिन गरीब मजदूरों के बच्चों को वह सुअवसर प्राप्त नहीं होता है । यह जो खाई है इसको मिटाने के लिए दोनों के बच्चों को एक ही प्रकार की शिक्षा एक स्कूल में ग्रहण करनी चाहिए । वर्तमान में जो कानवेन्ट और पब्लिक स्कूलों की व्यवस्था चल रही है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी निवेदन करना है कि कारखानों पर जब तक पूंजीपतियों का अधिपत्य रहेगा तब तक देश में आर्थिक सुधार नहीं हो सकता है। मेरा सुझाव है कि जितनी भी फैक्टरीज हैं उन पर मजदूरों की ओनरशिप होनी चाहिए ।

गरीबों को न्याय दिलाने के लिए लीगल एड की व्यवस्था की गई है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि गरीबों को किस प्रकार की सहायता दी जायेगी । उनको यह सहायता वकील के रूप में दी जायेगी, पैसे के रूप में दी जायेगी या किराये के रूप में दी जायेगी या फिर किस प्रकार से दी जायेगी—यह स्पष्ट नहीं है । वैसे तो अभी भी कुछ लीगल एड की व्यवस्था है लेकिन वह बिल्कुल निराशाजनक है । कौन गरीब एप्लाई करता है, कितना पैसा लेता है, कौन वकील है यह कुछ पता नहीं चलता है । इसलिए मैं चाहता हूं लीगल एड की परिभाषा साफ साफ दी जानी चाहिए ताकि जनता को न्याय मिलने में सुविधा हो ।

संविधान में आपने फंडामेंटल राइट की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिलाने की व्यवस्था की है लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अभी तक जो व्यवस्था है वह कुछ ही व्यक्तियों के लिए है, जो गरीब मजदूर और किसान हैं उनकी वहां तक पहुंच नहीं होती है । इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक गरीब मजदूर और किसानों का भी सामर्थ्य हो, इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

महात्मा गांधी ने कहा था कि जातीयता हिन्दुस्तान के लिये कर्स है । इसी जातीयता और भेदभाव के फलस्वरूप आज देश को यह दुर्दिन देखना पड़ा। दुर्भाग्यवश आज भी देश में जातीयता बढ़ रही है । पहले तो जातीयता समाज के अन्दर थी लेकिन अब प्रशासन के अन्दर भी आती जा रही है । आर्थिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र और न्यायिक क्षेत्र में भी जातीयता बढ़ रही है। इस लिये जातीयता को निर्मूल करने के लिये आप को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा और ठोस कदम उठाने के लिये, जैसा शेखानी साहब ने कहा, अन्तर्जातीय-विवाह, अन्तर्प्रान्तीय विवाह

होने बहुत जरूरी है । जालीयता को एक घोर अपराध माना जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में जो संशोधन किये गये हैं, इन के प्रति जनता को बड़ी-बड़ी अकांक्षायें हैं, बहुत आशायें हैं, लेकिन अभी तक हम देखते हैं कि बहुत से कानून जो सरकार द्वारा समाज के उत्थान के लिये पास किये गये, धरती पर भी नहीं उतरे हैं, अफसरशाही की अलमारियों में सजे हुए रखे हैं । हमारी सरकार जनता की भलाई के लिये कानून पास करती है, लेकिन ये अफसरशाह बीच में अड़ंगा लगाते हैं, उन कानूनों को कार्यान्वित नहीं होने देते, जनता तक उन का लाभ नहीं पहुंचने देते । ये अफसरशाह वे लोग हैं जो बड़े-बड़े घरानों से आते हैं, जिनका पालन-पोषण बड़ी-बड़ी इमारतों में हुआ है, गरीबों का शोषण कर के हुआ है । आज इन पर नियन्त्रण करना हमारी सरकार की पहली नीति होनी चाहिये, हर वह अफसर जो काम नहीं करता है, सरकार की नीतियों के पालन में अड़ंगा लगाता है, उस को सी० आई० आर० में बन्द करने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि आजादी की ब्लैसिंग्स, संविधान संशोधन का आशीर्वाद जनता तक पहुंच सके ।

हमारा सुझाव है कि इन आई० सी० एस० अफसरों, बड़े-बड़े पदाधिकारियों पर नियन्त्रण करने के लिये पार्लियामेन्ट की एक कमेटी होनी चाहिये । यह कमेटी उन के आचरण, उन का जनता के साथ क्या रोल है, उस पर नियन्त्रण करे और उन में जो समाजवाद के विरुद्ध काम करें, उन को समाजवाद के पक्ष में काम करने के लिये बाध्य करें ।

उपाध्यक्ष जी, गांधी जी ने कहा था— भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है । अभी तक जो कुछ व्यवस्था की गई है, जो कुछ काम किये गये हैं शहरों के लिये किये गये हैं । अभी भी गांवों में गरीबी, कलह, बेकारी, अशिक्षा, सड़कों का अभाव, बिजली का अभाव सब कुछ व्याप्त है । मैं एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से आता हूं, जब मैं अपने क्षेत्र के गांवों में घूमता हूं तो बाढ़ के कारण वहां जो स्थिति पैदा हुई है, उस को देखने का मौका मिलता है ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार ने जनता के लिये जितने विकासवादी कानून बनाये हैं वे जनता तक नहीं पहुंच सके हैं, क्योंकि हर साल बाढ़ गरीबों के घरों को ढ़हा जाती है, वे लोग घर छोड़-छोड़ कर भागते जा रहे हैं । सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये, वहां की गरीबी दूर होनी चाहिये, अशिक्षा दूर होनी चाहिये, छोटी-छोटी काटेज इण्डस्ट्रीज की व्यवस्था होनी चाहिये । जब तक गांवों की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक गांवों का उत्थान नहीं होगा, तब तक हमारी प्रगति संकेतमात्र होगी । इस लिये संविधान का जो संशोधन हुआ है, यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये एक बहुत बड़ा कदम है, इस के द्वारा हमारी प्रधान मंत्री जी भारत में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का गणतन्त्र स्थापित करने के लिये वचनबद्ध हो गई हैं । इस से भारत की जनता के अन्दर एक आशा बंधी है कि आजादी का आशीर्वाद, संविधान संशोधन का आशीर्वाद भारत की कोटि कोटि निरीह जनता तक पहुंचेगा । ऐसी आशा और आकांक्षा रखते हुए, मैं भी इन संशोधनों का तहेदिल से समर्थन करता हूं ।

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar): Sir, the gathering storm around this Constitution Amendment Bill has started withering away, both inside and outside the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The storm never broke.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Well, it was not very strong, and started breaking away. You are perfectly correct, that it is yet to be broken away. The debate on this new Constitution Amendment Bill

[Shri B. K. Daschowdhury]

or these provisions in this Bill which is under consideration, is now going on but some people started objecting that there are certain basic changes in the Constitution. What are the main points of their objections? They have started objecting to the passing of this Constitution Amendment Bill questioning whether this House has got its mandate? The Erosion of Fundamental Rights, the Erosion of Judiciary, the excessive power, irrationalities in the Second Part of the Fundamental Duty Chapter that has been proposed to be added, as some of them have interpreted, are in conflict with these Fundamental Rights and above all whether this Parliament has got this power?

Let us discuss it on the basis of these points which have been raised by some hon. friends. My friends have aptly said that this House has got the mandate on the basis of the programmes of the party given in 1971. I do not want to refer to all that. But if in order to uphold the Constitution, in order to work within the framework of this Constitution—in the Preamble it is said, "to secure justice—social, economic and political"—if in the furtherance of securing justice—social, economic and potical—certain changes are made in order to give relief to the poorer sections, I do not know where is the conflict therein and where is the question of mandate that comes in. The mandate is there. The moment this House was elected, composed of 526 members, they have their bounden duty to secure for the society justice—social, economic and political.

What are we going to do by this amending process? They have said, erosion of fundamental rights. The Law Minister and other members also explained that any laws passed in the furtherance of the directive principles *i.e.* Chapter IV of the Constitution, should not be challenged on any of the grounds mentioned in articles 14, 19 and 31. What are the things that are mentioned in the directive principles. The things are betterment of the society, welfare of the people and in its totality whatever is possible that is to be done. I would like to add one word here. So far as those things which were not being done earlier are concerned, an attempt has been made to do them and also to see that the society marches forward both in the economic sphere and political sphere and also to transform the society into an egalitarian society. Certain new clauses have been added for this purpose which are laudable. But some persons have found fault with it. I do not know what is their argument.

Then, let us take the question of erosion of the judiciary. Where is the point of erosion of the judiciary? No powers of the judiciary have been curbed. Rather the powers of the judiciary which were hitherto not well-defined have been streamlined and well-defined. Nothing else has been done. But we have seen out of our experiences what actualy has been the role of the judiciary in our country. One after the other the judiciary tried to interpret the Constitution in a manner they wanted to do and even by one judge's point of view, either in the High Court or Supreme Court, they wanted to uphold that their views were supreme and none else's. Though we are in this democratic process and we believe in democracy and adult franchise, yet the views of the representatives of the people in this House and in the other House are not supreme, only the judges' views are supreme! This is nothing but a new despotism on the part of the judiciary who deliver judgments as if they are the only kings and rulers in this country and nobody else, completely ignoring the will and consent of the people who send their representatives to this House to look after their welfare and well-being. Therefore, the question of erosion of the judiciary does not hold any ground.

I have gone through one of the articles published in the Indian Express sometime before. About Fundamental Duties particularly, they mention and I quote: "The challenges follow the noble ideals that inspired our national struggle for freedom." Our national leaders took part in the national struggle and they aptly have said that there are certain inalienable fundamental right and those rights, particularly referring to art. 14, 19 and 31 are, somehow or the other, being taken in view of the Directive Principles of the State Policy of the Constitution. I do not know what is their actual view point. If their view point is to stick to the law *i.e.* the fundamental rights are fundamental rights, then those fundamental rights are for whom? Those fundamental rights are for the so-called higher echelons of the society, for the so-called haves and not for have-nots. What is their grievance? The poorer sections of the society, the vast multitudes of the country do not consider that fundamental rights are embedded in the Constitution. They consider what their fundamental needs are. Their fundamental need is that their hunger should be removed and their economic conditions ameliorated. In view of these things, which one is to be given more weightage—the poorer sections who are demanding better transformation of the society or those who are clinging to the position that the fundamental rights should be followed by this country. The problems of the poorer sections are to be given more weightage. This position, in brief, seemed to have shocked many people. I would only quote one of the observations of George Bernard Shaw that it is not only necessary that some people should have to be shocked but it is absolutely necessary that they should be shocked very often and not occasionally, for the progress and prosperity of the country. With this view, these articles or constitutional changes which are under consideration, are welcome measures. There is no doubt about it. But I would only appeal to the hon. Minister to consider one of the provisions. The hon. Minister has mentioned that the increasing number of seats of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been frozen according to the census figure of 1971. I have no quarrel with that. But I would request the hon. Minister to consider and let me know after passing this Amending Bill, whether it will conflict with the recently passed Amendment Order of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If it conflicts, then it will certainly encroach on the powers whch have been given under that Order. The Constitution is supreme and any act contrary to the Constitution cannot act properly. Therefore, with reference to this Act, it should be given serious consideration. I would also request the hon. Minister to give a reply to this point. With these words, I support this Bill.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Amending Bill that has been brought forward by the Law Minister. While introducing this Bill, the Law Minister has aptly said that it is the finest hour in the post-independence era. I entirely agree with his sentiments The nation is on the march under the able leadership of our Prime Minister. Never in the history of our country have we made ourselves felt as the emerging leader of the new nations, and our voice is now heard with respect in the world councils. This happy situation has been facilitated by the fact that we are enjoying political stability in this country coupled with economic prosperity.

I am really surprised at the attitude of some of the opposition parties, who have run away from their sense of duty by not participating in the historic deliberaions. At the same time, I congratulate some of the other political parties and Independents who have thought it fit, and I feel rightly so, to participate and give their contribution for the passage of this amending Bill.

[Shri P. Venkatasubbaiah]

Democracy is a form of Government where consensus emerges through discussion. It is not fair to say that democracy will thrive only if there is indulgence of politics in the streets and confrontation.

This Amending Bill has asserted that Parliament is supreme to make laws, to amend the Constitution. Parliament means the will of the people. It is rightly said that Parliament reflects the aspirations of the people. In order to remove some of the stumbling blocks that stand in the way of socio-economic revolution, it is necessary that Parliament should reflect the real feelings of the people and the Constitution should reflect the aspirations of the people. As our Prime Minister and President of the Republic have aptly said, the Constitution is not sacrosanct, it is not static. It needs constant changes so as to meet the changing needs of the people.

Coming to some of the basic features, the supremacy of Parliament has been asserted and the federal character of the Constitution has been kept in tact, though some doubts were raised with regard to the sending of the federal armed forces to the various States in case there is some trouble in those States. In this connection, the Law Minister has rightly pointed out that our Constitution is neither completely federal nor completely unitary. It is a mixture of both the federal and unitary structure. So, there should be constant rapport between the Centre and the States. Then only we will be able to utilize to the maximum the resources that are available in the country.

In this context, it is relevant to refer to the transfer of certain subjects to the Concurrent List. Now Madras city is suffering from lack of drinking water. There are four million people living in that city and the only available source of water is the River Krishna, failing which there is the danger of the entire population of Madras city going without satisfying the elementary need of drinking water. Now, because of the dynamic personality of the Prime Minister, she will be able to convince the respective Chief Minister to part with some of the available water of Krishna. Had she not taken into her heart to help the thirsty millions of Madras city, the diversion of the Krishna water to Madras would not happen because water is considered to be a State subject and the States are fighting among themselves to appropriate as much water as possible merely due to the fact that by some geographical accident they happen to be by the side of certain rivers. The same is the case with drought-affected areas like Rajasthan and Rayalseema where there is necessity to take water from the mighty rivers to irrigate the land and bring prosperity to the people. So, if irrigation and power or river waters is included in the Concurrent List, it will go a long way to bring about economic prosperity to the arid and drought-affected areas. I hope the hon. Minister will have a second look at it and come forward with an amendment for including this subject in the Concurrent List.

In order to have political stability, defection from one political party to another should be avoided. There is already a Bill pending before the Joint Committee and I think it will soon come to the House to be passed. I had the privilege of moving a resolution in this connection as early as 1967 and it had the unanimous support of this House. So, I hope the hon. Minister will see that such a Bill is passed.

We have stated in the Preamble now that ours will be a socialist, secular State. So, the removal of regional imbalances must be given greater care.

Only in this country is the bureaucracy enjoying constitutional protection. The sooner we remove it the better will we be able to implement the socio-economic policies and programmes for the amelioration of the economic condition of the poor people.

I hope the hon. Minister will take these matters into consideration and that we will ere long re-cast the Constitution in its entirety if necessary for benefit of the common man.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): It is a good thing that in the Preamble we have made it very clear that we stand for socialism, but the point is that there are certain articles which come in the way of the implementation of the letter and spirit of the Constitution.

For instance, if the democratic set-up and federal character of our Constitution is to be implemented, the authority of the bureaucracy should be limited. The mere constitution of administrative tribunals will not be sufficient. Articles 311 and 312 should be suitably amended We must create a more dynamic, living Constitution which will reflect the real aspirations of the people of the country.

Although we have extended the term of the Lok Sabha for one year .

MR DEPUTY-SPEAKER. We have not.

SHRI K. LAKKAPPA:. . but we are not incapable of facing elections. We have previouly faced elections and got ourselves elected by the people. But political freedom is not enough. Therefore, we have to take into consideration economic freedom also. After the declaration of the emergency, the Prime Minister had launched the 20-point economic programme. How far these amendments would really help in the implementation of the 20-point economic programme is to be seen because there are certain obstructions also.

Uptill now, our Directive Priciples have been mere pious promises and we could not enforce them. We want to aradicate poverty, but we are not in a position to provide gainful employment to the people of this country. Unless the right to work is also incorporated in the Seventh Schedule, it will be very difficult to give employment to the people of this country. I hope the hon. Minister will give a new thought to this and also a suitable and convincing reply about this point.

It goes without saying that large resources have to be ear-marked for giving employment to the people of this country. Shri Venkatasubbaiah was just now referring to the economic imblamances existing in the country.

Today, millions of people of our country are unemployed and gainful employment is not available to them At the behest of the bureaucrats, their kith and kin have been employed in the various public sector undertakings and there has been no scrupulous scrutiny about it. One of the main difficulties is that millions of people of the country are not fully involved in the development of the country. It is, therefore, necessary that the right to work should be guaranteed, and the Central should give mandatory directions to the States to provide gainful employment to the people. All people, whether they be literate or illitrate should be given some work to do. Unless it is done, it will be difficult to introduce meaningful socialism in the country. If it becomes necessary to make further changes in the Constiru-tion, we will support them. But the most important thing is to guarantee the right to work and to provide employment to the people, and it should not remain merely ornamental and a pious wish as it was in the Directive Principles of the Constitution.

श्री रामचन्द्र बिकल (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने के लिये समय दिया, उसके लिये मैं आप का आभारी हूं । मैं प्रधान मंत्री, विधि मंत्री और सरदार स्वर्णसिंह का भी, जिन की अध्यक्षता में कमेटी में संविधान में ये आमूल-चूल परिवर्तन का सुझाव दिया था, हृदय से आभार

[श्री रामचन्द्र विकल]

मानता हूं । मैं आशा करता हूं कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्दों का जो समावेश किया गया है, उन को व्यावहारिक रूप दे कर उन का लाभ देश के गरीबों और किसानों तक पहुंचाया जायेगा और उन को कार्यान्वित करने में राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति सरकारी कर्मचारी आदि सभी लोग सहयोग देंगे। मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हू ।

इस सम्बन्ध मे राज्यों के बीच सीमा विवाद और पानी सम्बन्धी विवाद की चर्चा की गई है । ऐसे विवाद काफी व्यापक रूप मे मौजूद है और केवल केन्द्रीय सरकार ही उन को शीघ्र हल कर सकती है । जहा तक हरियाणा और यू० पी० के सीमा विवाद का सम्बन्ध है, वह श्री दीक्षित के फैसले के बावजूद इस स्थिति तक पहुच गया है कि दोनो राज्यो की पुलिस का एक दूसरे के सामने खडा रहना पडता है । इसलिये उन पर शीघ्र कोई फैसला लिया जाय और उस मे कोशिश की जाय ।

मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि यह राज्यो की अनेक बाते इसलिये भी बढ रही है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने मे बहुत सी पाबन्दी लगा रहे है । उन से करप्शन के अलावा न तो उत्पादन करने वाले को लाभ हो रहा है न उपभोक्ता को लाभ हो रहा है, या तो वे लोग जो बीच के है या कुछ ऐसे लोग जिन को मैं करप्शन मे फसा हुआ कह सकता हू उनको लाभ हो रहा है । इस से हमारे प्रान्तो मे एकता के बजाय अनेकता की भावनाए बढ रही है । इस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिये । चाहे वह कोई भी चीज हो उस के ऊपर पाबन्दी लगाने से कोई भी फायदा नही है । इस देश मे सभी लोगो ने देश की एकता के लिये कोशिश की है और मैं तो यह कहूं कि काश्मीर के लिये जो 370 धारा है उस को भी अब अधिक देर तक रखने का महत्व मैं नहीं समझता । मैं अनेक बार वहां के बैकवर्ड क्लासिस के लोगों के बीच में गया हूं, वहां के कांग्रेसियों से मैंने बात की है, सब इस चीज को कहते हैं । यह दूसरी बात है कि इसको कैसे और किस वक्त किया जाय । यह अलग अलग दर्जे के रखना देश के हित में नहीं है । इस पर भी प्रयत्न कुछ आपको शीघ्र करना चाहिये ।

यहा हिन्दी के बारे मे बहुत चर्चा हुई । मैं इतना ही कहना उचित समझता हू कि जब हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे स्थान मिल रहा हो, राष्ट्र सघ मे इसको स्थान दिलाने के लिये राज्य सभा और लोक सभा के अनेक ससद् सदस्यो ने अपने हस्ताक्षर वहा भेजे हों और हमारे देश मे नागपुर मे तथा देश के बाहर मारिशस मे विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ हो जिस मे ससार के करीब छत्तीस देशो के लोग आए हो, जबकि बाहरी देशो मे जैसे चीन, जापान, हगरी, फास इत्यादि के विश्व-विद्यालयो मे हिन्दी के ऊपर शोध कार्य हो रहे हो, तो हमारे देश से कुछ लोग यह कहें कि हिन्दी हम पर थोपी जा रही है यह कुछ उचित नही लगता है । मैं दक्षिण भारत के अनेक उदाहरण दे सकता हू । वहा हिन्दी का विरोध नही है । कुछ चन्द राजनीतिक लोगो को छोडकर और कोई उसका वहा विरोधी नही है । आबडी कांग्रेस के समय मे कुछ मुस्लिम बच्चो से बात कर रहा था तो उन्होने बडी खुशी से कहा कि अगर हम सात समुद्र पार की अंग्रेजी भाषा को सीख सकते है तो हिन्दी को भी उसी तेजी से सीखेंगे । पी ए सी के चेयरमेन श्री सेठ पान के साथ जब मैं मद्रास गया था तो उन्होने कमेटी का स्वागत करते हुए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा उस मे लड़कियो ने हिन्दी के गीत गाये । तब मैंने उन से कहा कि आप वहां तो ऐसी बात करते है और यहां कितना सिर हिला-हिला कर हिन्दी गाने सुन रहे थे । तो सास्कृतिक कार्यक्रम

[श्री राम चन्द्र विकल]

और तिलंगानों में दक्षिण में सभी जगह हिन्दी अच्छी तरह चलती है। मैं दक्षिण भारत के और उदाहरण देता हूं। अनन्त गोपाल शेवड़े नागपुर के रहने वाले है जिन्होंने दो विश्व हिन्दी सम्मेलन वहां किये। हैदराबाद में हिन्दी महाविद्यालय है। मैंने स्वयं देखा कि विज्ञान की शिक्षा भी वहां हिन्दी में दी जा रही है। आपको सुन कर खुशी होगी कि उस में केरल मद्रास, उड़ीसा, मैसूर आदि प्रान्तों के अनेक अध्यापक हैं जो और जगहो से कम वेतन पा कर भी हिन्दी का काम कर रहे हैं। हिन्दी का दक्षिण में आम जनता में इतना विरोध नहीं है जितना चन्द राजनीतिक लोगों में। जब मैं उ० प्र० में एक मंत्री था, झारखंड़े राय जी उस समय हमारे साथ थे उस समय अनेक मद्रास के सरकारी कर्मचारियों से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने फाइलो से बडे अच्छे नोट्स हिन्दी में लिख रखे थे। मैंने पूछा आपने हिन्दी कहां पढ़ी तो उन्होंने कहा कि हमने तो घर मैं हिन्दी सीख ली। तो इतनी सरल और वैज्ञानिक भाषा को यह कहा जाय कि हम पर थोंपी जा रही है उचित नहीं है। विदेशी भाषा को थोंपी हुई न माने और अपनी भाषा को थोपी हुई मानें यह ठीक नहीं हैं। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं। मैं चाहता हूं कि हर भाषा का विकास हो। लेकिन जो हिन्दी के थोपे जाने की बात कहते हैं वह मुझे हास्यास्पद लगती हैं। जो हिन्दी के विरोधी हैं मैं उनका नाम नही लेना चाहता लेकिन मैं कहूंगा कि वे भविष्य के लिये सोचें। हिन्दी के लिये सब से पहले गुजरात में स्वामी दयानन्द ने कहा था स्वराज्य से भी पहले कि हिन्दी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। स्वराज्य के पहले की बात और आपको मैं बताता हूं। गांधी जी ने उस समय कहा था: "स्वराज्य यदि सबके लिये हो तो हिन्दी एकमात्र भाषा बन सकता है।" पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि हिन्दी एक जानदार भाषा है, वह जितना बढ़ेगी देश का उतना ही लाभ होगा। इसी प्रकार से सरदार पटेल ने कहा था कि हिन्दी अब सारे भारत की राष्ट्र भाषा बन गई है, उस भाषा का अध्ययन करने में लोगों को गर्व होना चाहिये। श्री एस० मूर्ति, जोकि मद्रास के रहने वाले थे, ने कहा था कि मुझे अपनी मादरी जबान तमिल पर बड़ा अभिमान है। पर मैं यह जानता हूं कि दो करोड़ आदमियों की भाषा हिन्दुस्तान की राष्ट्र भाषा नही हो सकती है। हिन्दी ही उनके लिये सर्वथा उपयुक्त हैं। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण मैं और भी दे सकता हूं।

अन्त में मैं किसान की बात कह देना उचित समझता हूं। किसान द्वारा उत्पादित चीजों का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है सरकार की तरफ से चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्रीय सरकार वह मूल्य उसकी लागत के मुताबिक हो, इस बात की व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए। साथ ही साथ कम से कम एक वर्ष पहले इस देश के किसानों को देना चाहिये कि उसके गन्ने का दाम क्या होगा, चीनी का दाम क्या होगा, चावल का दाम क्या होगा या गेहूं का दाम क्या होगा। जितनी भी फसलें उसकी ली जाती हैं उनके दामो की घोषणा एक वर्ष पूर्व कर दी जानी चाहिए।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि संविधान मे संशोधन करने के साथ साथ कुछ व्यावहारिक कदम भी संविधान को बनाने वाले, उसको चलाने वाले और सरकारी सर्विसेंज उठायें ताकि गरीबो को इस संविधान का लाभ पहुंच सके। इन शब्दों के साथ मैं इस सविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI P. NARASIMHA REDDY (Chittoor): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I consider this historic Constitution Amendment Bill not merely as an amendment of the Constitution but as restoration of the Constitution to its original place of primacy as intended by the founding fathers of the Constitution. It is unfortunate that, on account of the attitude of the judiciary in the country, we have been obliged

[Shri P. Narsimha Reddy]

to resort more and more to amending the Constitution. If we look back and see the various amendments that we have been making to the Constitution, we will find that most of them have been undertaken as a reaction to judicial pronouncements. Nowhere in the world and at no time in the history has there been such a yawning gap between the national aspirations and the judicial pronouncements. Unfortunately, the judiciary has developed this sort of attitude for no reason.

In this connection it may be recalled that, in interpreting the Constitution or the laws of the land, the judiciary as one of the organs under the Constitution, must be extra cautious and careful not to interpret it in a manner which will impinge upon the domain of the other organs under the Constitution. If that sort of cautious attitude had been taken, this situation would not have arisen.

I would recall, in this connection, the valuable words pronounced by the eminent jurist, Justice Holmes: the judiciary should be very cautious in interpreting the laws or the Constitution so as not to impinge upon the domain of equally important other organs under the Constitution; the judiciary should interpret the Constitution or the law as it is and not as it ought to be. This dichotomy, in my opinion, has given rise to periodic Constitutional crisis as it were, in this country. I welcome this Bill as the final and last word in the matter, as an attempt to settle once and for all the overlapping function of these organs. Article 368 of the Constitution has been amended as the final attempt to rescue the Constitution from the judiciary and the judiciary from itself. I am sure, the Constitution has been finally rescued and put on the pedestal on which it ought to be, and I hope, the judiciary in this country will have the wisdom not to refuse to be saved from itself.

Having said all this, I would like the House to take note of some of the special obligations that flow from this amendment Bill we are passing to-day. The amendments we have made to circumscribe the domain of the judiciary in turn bring on us, devolve on us certain obligations which, as a legislator and as a government, we cannot shirk. It devolves upon us to be extra-cautions in passing legislations and make them foolproof in as much as by the extra-legal protection and immunity we have given to law-making, it is incumbent on us to reform or adopt suitable parliamentary procedures and other methods to see that the legislation we are going to make is foolproof and is vetted through proper legislative committees as in the United States Congress. This much of special attention to legislation—making is called for inasmuch as legal protection and immunity from the courts has been taken by our legislation.

I would like to add here another important obligation that has devolved on us as a result of the very many new features in the Constitution we have been obliged to adopt—the fundamental duties and the provision against the anti-national activities, etc. These are all aimed to shield our democracy from the sort of overt and covert activities that have been habitually indulged in by certain sections of the people so that this democracy and this State which the founding fathers handed down to us can be fully protected, developed and taken towards our cherised goal of socialism and secularism which have been enshrined in our preamble.

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar): To-day the long chapter, the controversial chapter in the history of our constitutional amendment is coming to a close. To trace the history a little, this struggle was initiated in 1969 and in 1971 we went to the people and got the mandate that the Parliament was competent to amend the Constitution itself. Even then it was delayed. Then we got the onslaught against our system. Demands for the dissolution of assemblies and also the Lok Sabha

itself, resignation of members and a partyless system—all these demands were made. Not only at that time it seemed that the whole government would be paralysed before these people not here but mainly outside; but having been in this House we have faced it for quite a long time and we faced it single-handed when several stalwarts of our comrades were attacked and injured.

After all this, it is good that we are getting this amendment which is most comprehensive and most far reaching than any other amendment to the Constitution made so far and it will be adopted also. The ruling party approved it, the Swaran Singh Committee has approved it, the AICC has approved it, the Cabinet also approved it and it was moved in the last session of the Lok Sabha and a national debate then ensued. Mr. Gokhale and others led the discussion.

Again dangers arose which were posed from outside from threats, actual walk-outs, boycott of the session of Parliament and demands that the Parliament is not competent enough to amend the Constitution and only a constituent assembly can do it and that voice got another impetus from the ruling party itself and in 3-4 States demands were made even on the very eve of this special session that a constituent assembly should be formed.

So, these were the pangs of birth of this amending Bill and this again went before the whole country because it was not an inner party affairs. It was widely publicised and all these made the country almost on the verge of suspecting whether another 1969 had come. Now, it is good that friends on that side, inside the Parliament and outside the Parliament, in the ruling party, and inside the government all have asserted that the Parliament is competent to enact this Bill and scotched that attempt for referring it back to a constituent assembly or even to Select Committee. Thereby the supremacy of Parliament and our own commitment to the people were maintained. For that I congratulate all those elements, the individuals and forces who have been helpful to us in this regard. Another thing about which we are happy is about the inclusion of the word secular n our Preamble. Uptill now we said, sovereign democratic republic. Even now our sovereignty is there, the democratic basis is there. These have to be strengthened and defended against the onslaught of anti-secular forces. We know how various forces have been operating in this country directly and indirectly, sometimes hidden, sometimes open, to destroy the very secular basis of our Constitution. Therefore, it is necessary that the term secular should be spelt out. We have included what we have preached for the first time in the Constitution. We know how voices were raised in this country against all isms and ideologies. I want to congratulate the Prime Minister, her partymen, Shri Gokhale and others for counteracting such forces and for having incorporated their own commitment to the people. The word 'socialist' is being added. Socialist democracy is going to be our constitutional preamble hereafter. There was another attempt intentionally or unintentionally to say only democratic socialism. Now we have put it properly saying, socialist, secular, democratic republic. It is not that we are under an illusion that we have got the socialist republic. We are heading towards it. This is our solemn resolve. This is our declaration. We now start another chapter in our political life. Another new chapter hereafter begins. We will have to see step by step the realisation of this goal.

Another important change is this. The Judiciary has been given a more respectful place. By siding with the princely order, by siding with the monopolists and the vested interests, the judiciary allowed its prestige to go down in this country in the past. Now we have put it properly that judiciary will not be allowed to interfere with the constitutional amendments. We have said that Directive

[Shri Bhogendra Jha]

Principles should have precedence over fundamental rights. Judiciary therefore will behave in a more responsible manner and they will be able to fulfil their role in the lives of our people.

But there are certain aspects where we feel that the amendments have not gone for enough. We feel that they have not gone to the extent they ought to have gone or should have gone. There is one slur which we have with the unlimited, unbridled right to property. I would refer to an axiom in the Bhagavat Gita:

यावत् भ्रियते जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनां।
अधिकं याऽभिमन्यत संस्तेनो दण्डमर्हति ॥

Property is only for a person's needs. If he amasses more than that he is a thief. I am sure through the democratic process we will overcome this hurdle also.

President's power to act on the advice of the Cabinet has also been clearly spelt out. We are happy about it. Although this was understood, now we have clearly spelt it out. Our happiness is not an unqualified thing because there are certain things about which we are not happy. We go out from the House, we go to the constituencies. The Prime Minister is hereself saying that we should go and meet the people. How can this be done when there is total ban on meetings in Bihar? I think nobody will expect that I will not go and meet my people.

15.00 hrs.

I do not know whether I will be arrested or not, because there is a total ban. Now no smuggler is being arrested, no hoarder is being arrested. So the prices have risen during the last four months. In turn, this has had other undesirable results. Those very elements who were working against us, who were forcing people to resign are demanding a Constituent Assembly, and with the Youth Congress cap on their heads, they are now taking revenge on those who have restored our democratic structure, and in a violent way. Only the lebel has changed; the elements are the same. They are abusing the Prime Minister privately. Openly they go about saying that the 20-point programme is nonsense. They want simply to hide their own criminal offences. I am not talking of people in the political sphere only; I am talking of all. Most of those people are doing this. If I come to individuals, most of the people on the other side will not dispute what I say. In these conditions, it is disastrous to do some of the things we have done. We have now amended the Constitution to say that if there is emergency declared in a single part of the country, it can be enforced in other parts also. This is a strange thing. Then again the proposal to send armed forces into a State without the consent of the State Government, while the State Government is functioning there. This will add to avoidable strain in Centre-State relations.

Similarly, with regard to the protection of minorities, our Constitution is clear on the point. Certain amendments made require some additional safeguards more in consonance with the secular character of our polity.

On the question of language, I have been fighting for Hindi all my life. But I would like my friends from the Hindi area to realise that while Hindi is most popular, is spoken by most people in the country, is understood by most people in the country, India after Partition is bigger than Hindi. Bharat is bigger than Hindi. There are many other languages. Take, for example, Tamil. It cannot be compared to Hindi. It can be compared to Sanskrit. So if our unity is to be preserved, let Hindi be developed by giving all incentives and impetus to it side by side but without bringing in pressure so that the whole of the culture of India and all the languages develop in a proper way.

SHRIMATI M. GODFREY (Nominated—Anglo-Indians). Mr. Deputy-Speaker, thank you very much for giving me an opportunity of saying a few words The whole world, all the countries of the world are undergoing a change and stepping forward So I think our country has taken a step at the right time of introducing this 44th amendment to the Constitution of India I feel happy that many amendments were introduced and passed yesterday I am also particularly interested in the safeguards given to the minorities I only hope that these safeguards will be meticulously carried out by the people who are guarding them

I would like to make a request to Government Now the duties of citizens have been very clearly put down here I would suggest that these be put down in the educational syllabus also so that children as they come up to discharge the higher tasks feel the duties of the citizens of this free country If they are taught at the school level what these duties are I am sure they will come out as very good citizens of this country of ours

I am glad to note the change in the Preamble to the Constitution by bringing in the words 'Sovereign, Socialist Secular, Democratic Republic'. The word 'Secular' struck me most, because when I go about, everybody asks me 'How is it that you are a Member of Parliament and you dress in this fashion?' This proves to you the secular character of our country. So I am a living proof of secularism in this Democratic Republic of ours I openly tell them 'This shows how secular our country is'. We accept all languages, all dresses, all religions. We are people of all colours, all dresses speaking different languages and we are all in the mainstream with the rest of the people of India We are all Indians. We may wear different costumes, different dresses, but we are all Indians. We all know very well; I am a living example to show how secular our country is, I am proud to tell people outside and in the country also that we are secular.

In our education system I should like to have once again moral science subject They have now put in civics I think a little more of moral science, if added to that, will help our students to become very good student citizens of the country With these words, I thank you very much for a chance to speak on this Bill

Shri N K SANGHI (Jalore) We had been having a marathon debate for the last nine days and this has really been a special session when the entire time of the House had been devoted to one subject, discussion on the 44th amendment Bill The Bill was introduced by the hon. Law Minister in the last session of the House so that there could be wide publicity and public discussion, and the views of the people at all levels could be known We have had a thorough discussion in the last three months; we have also had a threadbare discussion in Parliament and no one can deny that it has received the widest publicity though a few persons criticise and say that it is not so There has been a national debate on this Bill The Bill has heralded a new era in constitutional history.

Since 1952, we have been following the democratic procedure; and having elections to the Lok Sabha, State assemblies, panchayats and municipalities and nagarpalikas and so on. Every man has been inducted to take part in the elections and in this background of political education, people began to know what their rights were and what they should expect from the government. Year after year we have been talking about the aspirations of the millions of people. There has been some delay in achieving these objectives. In fact, this amending Bill should have come much earlier in 1967—70. You all know what happened in 1967—70. Congress lost the majority. There has been a mixed govern-

[Shri N. K. Sanghi]

ment of the opposition parties in the different States which did not know what their objectives were and in fact they had no common objective except to cling to power. We in the Congress Party wanted to nationalise banks; difficulties came in our way. We wanted to abolish privy purses; we lost on that point in the Rajya Sabha. There were road blocks and the courts took a different view. So we had to go to the polls and asked the people to give us their confidence. Our party was elected with a thumping majority and people said: we are electing you so that the road blocks might be removed and steps could be taken to fulfil their aspirations. In this background many things had been done in the last few years. We have seen many good results.

People say that we have to have a static Constitution. How is this possible? What was the situation in 1952? And what is it today? We have had large scale industrial development; today we are self-sufficient in many respects; our agricultural production has more than doubled. Our population has grown. We are a fast developing country and many new things have to take place and in this background the Constitution has to be amended to meet the changing situation.

Socialism is not a new word. Even from the pre-Independence days, from its inception in 1931 the Congress Party has been clearly saying that it stood for socialism. After Independence there came some parties which said that they wanted to have a particular kind of socialism. Others pointed to other directions. The Congress Party was the only party which said: we want to go in one direction.

The Preamble was very clear but the word 'Socialism' was not there in the Preamble. The judges interpreted the law as if they have to interpret the law in a text-book manner. But the feelings of the people and the structure of the Constitution were not taken into consideration. Since 1931, Congress Party has been saying that they are for the socialist type of country. Now, the aspiration of the people has also been roused towards this and this word 'Socialism' is included in the Preamble and I think we have really got the Preamble by reflecting in a deeper colour to purport the aspirations of the people in the Constitution.

From 1951—57, the power of Parliament was supreme to make changes in the country's Constitution. It could do anything to amend the Constitution, it could change the Constitution if the people so desire. But in Golaknath case, we were told that the Parliament did not have the entire power of changing as per Article 368. It provided according to Article 368, the procedure to amend and not the power to amend the fundamental rights. But then in Keshavanand Bharati case, in 1973, they declared Article 24 and Article 25 as valid but raised the question of basic structure. They did not define what the basic structure was and what they really meant. It is these doubts that have made the Parliament to come and clarify the issues to meet the aspirations of the people. These road blocks and these difficulties are there not only now but have been there in the past and we have to remove these road blocks once for all. We have to go on the road of progress and anything that comes in the way of progress has to be changed or removed. I would like to quote the words of Pandit Jawaharlal Nehru here. While speaking about the Constitution, he said:

> "Laws are meant to fit existing conditions, and they are meant to help us to better ourselves. If conditions change, how can the old laws fit in? They must change with changing conditions, or else

they become iron chains keeping us back, while the world marches on. No law can be an 'unchangeable law'. It must be based on knowledge, and as knowledge grows, it must grow with it."

In this context I may also quote Mr. Jefferson, the great American Statesman, who observed as:

"We may consider each generation as a distinct nation, with a right, by the will of the majority, to bind themselves, but none to bind the succeeding generation, more than the inhabitants of another country."

I hope the present Amendment Bill will bring peace, progress and advancement to the millions of people who are downtrodden and poor. I am sure the aspirations of the people will be cherished and fulfilled. In case further roadblocks come in the way of progress we should be prepared for them and see that they are removed and the aspirations of the people are achieved.

SHRI NIMBALKAR (Kolhapur): Sir, I think that our country has been modernising itself quite rapidly, both in our way of life and also in the ways of our customs and laws. You might remember that it was not very long ago our brides were chosen for us by our parents. Now, I think that there are a few persons in the country who would prefer their parents to choose their brides. In the same way, we find that as far as the Constitution is concerned, there must be a rapid change, for the simple reason that the people are advancing in every way and if we are going to remain with the choice of our fore-fathers only, then it would not be possible to look upon the Constitution as something for us rather than we for the Constitution. Sir, I want to suggest here something for the future and I think that it is time this House committed to create a Committee which should be called 'Constitution Amendment Committee' and whenever any Constitution Amendment Bill is to be introduced, whether it is a private Members' Bill or a Government Bill—it should be first referred to that Committee for its comments.

Such a process will give the people also confidence in the proceedings of the House and the seriousness with which we like to go forward, particularly when it comes to Constitution (Amendment) Bills. I do hope, however, that our Law Minister and the Government are serious about the reasons that they had given for bringing in this Bill. They say, it is to bring in socialism and to develop our country fast. Bad carpenters usually blame their tools. I do hope a time will not come when the people will say, if the government has not done its work, "The government is the one that is weak and since it has nobody else to blame, it is blaming the Constitution for not having brought in development". So, a big responsibility falls on all of us to make the future of this country successful. Only then it can be proved whether we were right or not in amending the Constitution.

Mr. Gokhale said, since the Rajya Sabha has six years tenure, he thought the Lok Sabha also can have a tenure of six years, inkeeping with the wishes of the members of this House. I think that is a fallacy and a wrong way of looking at it. The fact of the matter is, we are directly elected representatives of the people and the longer we remain away from the people, the more the value of this chamber diminishes. Every two years one-third of Rajya Sabha gets renewed. If you look into the last 1½ years and what Lok Sabha has given to the people, you will find that the returns as far as the people are concerned have been in my opinion negative; they have been diminishing. I feel quite strongly that if we start increasing the life of Lok Sabha, one day we will be fully thrown in the hands of the Rajya Sabha both in serving the peo-

[Shri Nimbalkar]

ple and also in serving the government. This is one of the reasons why our fore-fathers thought that five years for Lok Sabha and six years for Rajya Sabha were good. They did not want the value of this chamber to diminish. When the value of Lok Sabha diminishes, how is the value of the people going to be upheld? I go with the party, of course, but the fact remains that the arrangement laid down by our forefathers was the real and proper thing to do.

SHRI C. H. MOHAMED KOYA (Manjeri): Sir, in spite of the unjustifiable and unfortunate boycott by some of the opposition parties, the House passed the historic Constitution (Amendment) Bill. The sovereignty of the people expressed through their duly elected representatives has been established. Since the scope of the debate in the third reading is limited and since you have reminded the House of it, I do not want to say anything about the amendments which have been rejected.

The Constitution is not a magic wand by which you can change the miserable lot of the toiling masses of the country. And, we cannot make the erstwhile Constitution of the country a scapegoat for all the omissions and commissions of the rulers. If at all there was any road block in some provisions of the Constitution, that is also removed now.

15.20 hrs.

[SHRI P. PARTHASARATHY *in the Chair*].

Mr. Gokhale said in the Lok Sabha on August 3, 1971:

> "A Constitution cannot be immutable and if it is so held that it is immutable, it means that we subscribe to the theory of stagnation."

If at all there was any road block of the Constitution, that is also removed and we have nothing which can stop us from our onward march to socialism. There is no use by merely providing something in the Constitution. Did we not provide in the Constitution for universal primary education? But, what is the position today? What is the position in the slums, in the villages of U.P. Bihar and other States?

Many fears and apprehensions were expressed by the feeble opposition that chose to remain in this House. Mr. Gokhale vehemently argued that India is not a Federal State. He may be on narrow technicalities. Does it mean that India is a Unitary State? We have reluctantly voted for the clause about deployment of Central forces in the State. This we did especially in view of our bad experience in dealing with communal riots. But, here, I would like to give a word of caution. The Centre should not behave in a manner which will affect the autonomy of the States. This should be borne in mind in all our actions especially in future legislations and other follow up actions of the amendments of the Constitution. The State assemblies should not be made glorified Panchayat Boards. Deployment of forces by the Centre to the State is a delicate subject. It should be handled in such a way that the unity of the country is not affected even in the slightest manner. There should not be clashes of policies between the Centre and the State and as far as possible, consult the States before the extreme action is taken.

Then there is the question of minorities. Though our efforts to include certain safety valves have failed, we are thankful to Mr. Gokhale for the assurances he has given. We hope and believe that these assurances will be borne in mind. The minority problem is not a small problem. The total population of some of the minorities in India is more than the

population of many countries Take, for example, the Muslims. Barring Indonesia and Bangladesh, India is the biggest Muslim country So, as Mr. Gokhale has assured the House that in future legislations the rights guaranteed under the Constitution should not be eroded Their culture, religion, language and personal law should be protected

About representation in services, we tried to argue our case to give more representation to the minority communities There could have been no objection even if the Commission was appointed to go into the question of economic standard and position of the minority communities, but that was not attempted in this Bill Some sort of a *modus operandi* should have been found out for giving adequate representation to the minorities in Government services

Mr Gokhale has said that judiciary is three generations behind I hope, he did not mean any disrespect to the judiciary by saying so I also hope that the independence of the judiciary will not be interfered with Our constitutional limits are judiciary executive and legislature These three part combined make our Constitution Therefore I hope, whatever may be his personal opinion about the judiciary in this country, the status of the judiciary shall be maintained and there shall not be any erosion on the powers of the judiciary I hope the judiciary will surely be allowed to work in its own sphere

SHRI D BASUMATARI (Kokrajhar) Sir I have been listening with rapt attention to the Constitution Amendment Bill that is being discussed I may recall here as I had the privilege of being one of the members of the Constitutent Assembly, which started on 9th December 1946, and adopted in November, 1949 and we all signed the Constitution on the 24th January, 1950

Since the Constituent Assembly was constituted on the British pattern, most of the provisions which were adopted were on the pattern of the Government of India Act, 1935 What was the Government of India Act, 1935? It was an Act meant to rule India, to exploit the Indian society and to keep it under subjugation Since we had copied the pattern of the 1935 Act, naturally we had to face difficulties on account of which even now the Law Minister had to bring in as many as 59 amendments to the Constitution

At the time when the Constitution was adopted as well as now, many amendments have been brought forward Whenever any advocate brings forward an amendment, he sees how he could protect the judiciary

AN HON MEMBER I hope he excludes the judiciary

SHRI D BASUMATARI I am referring to prastising lawyers The Law Minister is no longer a practising lawyer I am tired of hearing these statements that the judiciary is in danger These are all jugglery of words

As I said the other day, the only answer would be to give a new look to the Constitution with a new Constituent Assembly I feel strongly that if we want to have the betterment of the country through an egalitarian society which we are thinking of if we want a socialist structure a socialist society and all that if we want to bridge the gulf between the rich and the poor, it is possible only if we give a new look to the Constitution by having a new Constituent Assembly

The Constituent Assembly which framed the Constitution consisted of people belonging to various classes of life My respected friend, Shri Samanta, will bear me when I say how Nehru had to struggle with the members of the Constituent Assem-

[Shri D. Basumatari]

bly, because it consisted of so many kinds of people. There were representatives of princely States numbering 93, of the Muslim League and the Hindu Mahasabha and so many vested interests. Barring Nehru, Sardar Patel and a few vocal members, all the rest were non-Congress members, who represented the capitalists and businessmen.

AN HON. MEMBER: What about you?

SHRI D. BASUMATARI: I am a common man; I am not a capitalist

What can you expect from such a Constituent Assembly The day after we signed the Constitution, Prime Minister Nehru said that this Constitution is not a rigid Constitution which can not bind down next generations. Dr Ambedkar also said that it will not suffer from the fault of rigidity or legalism Another occasion Prime Minister Nehru said:

> "Not with a view to challenge any judicial interpretation but rather to find out and to take the assistance of this House in clearing up doubts and in removing certain approaches to this question which have prevented us from going ahead with measures of social reform and the like."

This is what Pandit Jawaharlal Nehru said just after the adoption of the Constitution.

After all, what is the Constitution? Are we going to spend all the time in a struggle between the judiciary and the executive? I am tired of hearing these things. Some hon. Members have said that it was a compromise Constitution. So, to put an end to all these uncertainties and controversies, I would request our leaders and Mr. Gokhale to consider whether it is not possible to convert this House into a Constituent Assembly. I do not think it is difficult. I will leave it at that.

Mahatma Gandhi wanted to bring all the weaker sections of the society, the scheduled castes and scheduled tribes into the mainstream within ten years. Seats were reserved for them till then, but it was found that it was not at all possible to complete the process within ten years, and so, reservation was extended by another ten years and so on So, we have not been able to achieve socialism as envisaged by Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru through this Constitution Therefore, we are now changing it. But it will not stop here. You will have to bring further amendments, because it has to be interpreted by the courts, and the lawyers have a mentality which will not interpret the Constitution the way we intend it for bringing about social equality. They are thinking in their own old way, in favour of the vested interests.

We have now introduced fundamental duties Why? In order to infuse a sense of duty, a sense of responsibility, among the citizens.

Now I come to my learned friend Shri Bhogendra Jha who was saying that there were no right-thinking persons in the Congress Party, as if right-thinking people were to be found only in the Communist Party .. (*Interruptions*)

Shri Indrajit Gupta stated that the five-point programme had no *locus standi* coming from a private citizen. But is not Jayaprakash Narayan a private citizen taking whose advice some Members of the Opposition have boycotted this House? It is no good doing all sorts of anti-national activities here and outside. When you speak, you speak with some sense. Do not speak without sense? That is my request to you.

(*Interruptions*)

Your party is not just to advise us. You want dictatorship. We want democracy. That is the difference between you and me. The word "socialism" is also used in the capitalist

countries. There is a difference between your socialism and our socialism.

(*Interruptions*)

Ours is persuasion; yours is compulsion.

SHRI M. C. DAGA (Pali): I will request the hon. Chairman to change the time for speaking.

MR. CHAIRMAN: I appreciate your suggestion.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Tellicherry): With mixed feeling, our party is welcoming the 44th Constitution Amendment Bill. We are very happy that you have adopted socialism as our goal in our Constitution. You have inscribed the words "socialism and secularism" in the Preamble of the Constitution. It is an important development, because it shows that in the world today we are living in a period where great achievements of socialism have come to stay and not only that, it has been proved that capitalist part of development is no more suitable for developing countries. It is in that background, we suppose, that we are inscribing the word "socialism" in the Preamble of the Constitution as the goal that we want to achieve. We welcome that. But, at the same time, it is necessary to point out one of the glaring contradictions which is there in the Constitution.

When we adopt socialism as our goal, as the previous speaker from our party had pointed out, it is a contradiction that in the Chapter regarding the Fundamental Rights, we are again keeping the right to private property as one of the very important fundamental rights. When we say that the right to private property should be taken away from the Constitution, we do not mean that there should not be any *panwallah's* shop or there should not be a small trader or a small farmer.

The main consideration is that the means of production should not be privately owned as a means of exploitation of the masses of the people. The Constitution, as it is amended today, when we retain that clause regarding the fundamental rights to private property, we do not think is in tune with what has been written in the Preamble of the Constitution.

Mr. Basumatari was just now quarreling with us. The point is, whether it is by persuasion or by whatever means it is in this country, under socialism, there should not be a Birla; there should not be a Tata; there should not be a Goenka; there should not be a *kulak* lobby pressurising the Government all around. You can adopt whatever means you like. If you want to adopt the Sarvodaya method, you try it. If you want to go and fall at their feet and beg, "relinquish your property", you do it. But in this country, when we say that we are going towards socialism, there is no place for private property as a means of exploiting the masses. That is what we mean. This contradiction remains in the Constitution. The Government refuses to adopt our proposition. Many of our friends on that side also have proposed that the right to private property should be deleted.

Then, we have fears about the clause that has been included in the Constitution, that is, about anti-national activities. It is not to say that we support anti-national activities, not the least. But in the name of fighting anti-national activities, this clause can be misused against the legitimate trade union activities in the country. I think, the Members from both the sides of the House have expressed their fears about it. This amendment enables the Government to bring forward the necessary legislation. The Law Minister said that at that time, he will take care of it. Several promises were made in this House before that Emergency powers will not be misused and that MISA will not be misused. There are cases after cases brought before

[Shri C. K. Chandrappan]

the Government about the misuse of these powers. It is not Mr. Gokhale who is going to implement it. It is the bureaucracy that is going to implement it. In our administrative system, as it is today, the bureaucracy plays a very important role and there is no guarantee that they will not misuse these powers. I express this fear because that is a fear not merely being expressed on the floor of the House but it is a fear in the whole country among the democratic-minded people.

Another point which I would like to bring before the House is about the deployment of Central armed forces. There are newly acquired rights of the Central Government for the deployment of the Central armed forces in the States without taking into consideration their views.

About the declaration of partial Emergency and for the enforcement of partial Emergency there may be a legislation enacted for that particular part of the country which is under partial Emergency and we feel that that also can be misused against the people who are living in the neighbouring areas, in places which are not declared under partial Emergency. This also should be taken note of by the Government.

Lastly, Mr. Gokhale said, when you adopt this Constitution Amendment Bill, it is to bring about a social revolution in the country. I would like the Government to take into account one fact that in this country, the people, specially the new generation of people should be given proper education as to what socialism means so that they can understand socialism and the new goals that you have set before the country.

Your educational system should be oriented in that fashion. The members of the Congress Party like Mr. Basumatari should know what socialism means. There are a large number of young people who should be educated on that. A cultural revolution might be necessary to enforce what you mean by bringing about a social revolution. It may not be in the Chinese fashion. What I say is that an effort should be made by the Government to educate the people on the meaning of socialism, on the great achievements of the socialist world. What has been the experience of the Soviet Union? There may be people who are allergic to that. But, without knowing that, you cannot implement socialism in this country; you cannot implement socialism with Birlas and Tatas. This should be taken care of.

These are some of the things which I would like to bring to the notice of the Government. Otherwise, I welcome this Bill.

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI (Gauhati): Mr. Chairman, Sir, I associate myself with the others in congratulating the Law Minister for having piloted this Bill through the first and second stages and which is now in the process of the first stage.

Two contradictory views have been expressed in this debate. Some have said that the Constitution needs a fresh look because it has outlived its use or utility; and the other view has been that the Constitution is a sacred and sacrosanct document and it should not be touched. I do not share any of these extreme views. I feel that this Constitution has stood by us all these years. By this Constitution, we have been able to meet a number of foreign aggressions; we have also been able to meet our economic difficulties as we have provided stability in the country. Therefore, there is no ground to subscribe to the view that the Constitution should be scrapped. We should undoubtedly remove those provisions which are coming as roadblocks in the implementation of our socio-economic programmes.

To those who have said that the Constitution is sacred and sacrosanct, I can do no better than quote what Pandit Jawaharlal said when he dealt with this particular aspect in a debate in this very House. He said:

"Some hon. Members who have recorded their dissent have referred to the sacred and sacrosanct character of the Constitution. A Constitution must be respected, if there is to be any stability in the land. A Constitution must not be made the plaything of fickle fortune. All this is true. At the same time, it should be remembered that we have, in India, a strange habit of making Gods of various things and adding them to our vast pantheon. Having given them our theoretical worship, we do exactly the reverse of what we should. If we want to kill something in this country, we deify it first. That is largely the habit in this country.

"So, if you wish to kill this Constitution, make it sacred and sacrosanct. If you want it to be a dead thing, not a growing thing, a static, unwieldy, unchanging thing, then by all means do so, realizing that it is the best way of destroying it."

Therefore, to those persons who are talking in terms of sacred and sacrosanct character of the Constitution, I would say that they are doing it in order that the Constitution may outlive its use and may die a violent death. But we on this side of the House want that the Constitutional form of Government should survive and should continue. In order that it may be a living thing, in order that the Constitution may respond to the urges and aspirations of the people, the Government has come with the necessary changes and I welcome them.

A view has been expressed that, by these Constitutional provisions, we have attempted to denigrate the judiciary. I think—and the Law Minister will also confirm it—that, in the Constitutional amendments that we have brought forward, we have not, in any way, compromised with the independence and integrity of the judiciary. These amendments have become necessary because the courts came in the way of legislative experimentation. Whenever we made an experimentation, be it bank nationalisation or abolition of privy purses or any other socio-economic reforms, in many cases, the courts tried to stop these experiments. And it is not that, for the first time, this has happened only in India.

In a democratic country like America this has happened and may I quote in this context one passage from what Mr. Holmes, one of the most renowned jurists of the world, when he said

"He (Mr. Holmes) denounced sharply Taft's assertion that the Constitution was intended as a perpetual bar to legislative experimentation. The proper function of the court was, he thought, to encourage experimentation carried out by the elective branches, the validity of such experimentation to be determined largely by a general social evaluation of the desirability of the social results thereby achieved. This posture of judicial self-restraint meant that the Court, while serving a liberalising function, should no more play a positive role in achieving specific liberal social policies than a negative one in invalidating experimental regulatory legislation. Rather it should interpret the law in such a way as to make it possible for the people's representatives to move in the direction they felt desirable."

Unfortunately, in spite of the fact that many a year have passed by after this pronouncement arising out of American historical experiences, the tendency still prevails in the country. Therefore, it has become once more necessary for this Parlia-

[Shri Dinesh Chandra Goswami]

ment to assert in unqualified terms its right to amend the constitution in any manner as it thinks necessary to really give expression to the urges and aspirations of the people. That is what we have precisely tried to achieve by these amendments.

Then, Sir, so much has been said about *'socialism'. I think at the risk* of repetition I have again to say that it is not that we have brought something new when we have talked about socialism. I can do no better than quote what Pandit Nehru said while moving the objectives Resolution in the Constituent Assembly:

> "We have given the content of democracy in this Resolution and not only the content of democracy but the content, if I may say so, of economic democracy. Others might take objection to this Resolution on the ground that we have not said that it should be a Socialist State Well, I stand for socialism and, I hope, India will stand for socialism and that India will go towards the constitution of Socialist State and I do believe that the whole world will have to go that way. ...'

Because of the compulsions of the Constituent Assembly, they could not incorporate the provision of socialism but Panditji kept a hope that in the future constitution the independent, sovereign Parliament of India will go towards a socialist State. So, what we are doing today is not something new, we are only giving expression to a long-cherished desire which Pandit Nehru in his life-time could not achieve because of various compulsions. Therefore, I feel that the objection does not have any sound basis

Then, Sir, much has been said against fundamental duties. Here again I would like to quote what Pandit Nehru had to say:

> "Freedom carries with it the obvious responsibility, which every one realises, of defending it from external attack. But, ultimately, the other responsibility is more important and that is to maintain the inner strength, the morale, the self-confidence of a nation, which can be done only by following what I roughly call the right advice and, more especially, developing the habit of dispassionate thought and the *calm consideration of problems.*"

He went on saying:

> "We, who have been fighting for our rights and have finally achieved them, are apt to forget that a right by itself is incomplete and, in fact, cannot last long if the obligations which accompany that right are forgotten by the nation or by a greater part of it."

Therefore, I feel what we are doing —though some may claim that it is really revolutionary in the true sense of the term—is that we have really tried to give expression to some of the aspirations and expectations of the framers of the Constitution which they could not do because of various compulsions of the time. I know that we have framed these amendments. These are not the last word on the subject. After we have incorporated the word 'socialism', we shall have to go in for further amendments as time will pass by. I think, for instance, the right to work will have to be made a justiciable right one day or the other.

Sir, let us not forget that the world is moving very fast. The other day I was reading a book. There it is said that upto 1880 the maximum speed that the vehicles could attain was 100 miles. Now we are speeding at 1800 miles per hour.

In a century, mankind achieved a *speed which is 1800 times greater* than the speed which took centuries to achieve. Earlier, in a century, it is estimated that one lakh new books came into the circulation and today

we are having every year 1,20,000 new books.

Therefore, what a century book to achieve some years back we are achieving today within ten months. The world is moving at a rate which we are not even capable of comprehending And therefore in order to keep pace with it changes will have to be made. And so in such a situation more particularly than others, those who want statusquoism ovbiously will not be forgiven by history With all humility, we have brought these changes because we have felt that but for these changes the constitution and the country will not be able to go together

Because of all this, criticisms, which my learned friends levelled against the Constitutional amendments, have no validity I hope that the House will unanimously pass the amendments

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI (Calcutta-South). I congratulate the Leader of the House and the leader of the country, our leader Shrimati Indira Gandhi for once again proving to the world that parliamentary democracy and parliament as such in the country is supreme and it is parliament which is representing the will of the people It is due to her courageous leadership from 1969 upto this day that the politics of the entire nation got a new strength and confidence and I feel that by amending the Constitution through this Bill it is not Government alone which will get a new strength, but, it is the whole country which will get a new strength and confidence to make further fresh break-through in the socio-economic transformation

I am extremely sorry to offer a few of my comments against those hon Members who tried to justify what they had to say on the ground that the amendments to the constitutions have been so many that they are feeling tired and as such there should be a new constituent assembly. While there is a struggle going on in a country of the size of our country, when someone gets tired, the only prescription that he or she can take is to take rest or retire Till the struggle reaches its victorious march there should not be any sense of tiredness I am not tired It is the beginning of a great journey which is embarked, which is yet to be seen The concept of constituent assembly in such great issues as the constitutional amendments is not only against the wishes of the people, but also, it is against the interests of parliamentary democracy and the concept that parliament is supreme. Our leader Shrimati Indira Gandhi has shown by her courage that this Parliament is not only supreme but that it is the custodian of the will of the people and there shall not be any alternative to it

I am sorry to hear a few members making suggestions that during independence days Pandit Nehru had to compromise with many people like the kings and others It is nothing but paying disrespect to the great achievements of Pandit Nehru Pandit Nehru did not make any compromise Gandhiji and Nehru have said one great thing, and that is, that India is not composed of the concept of a particular tribe or community, that India is not composed of the concept of a particular class or of a particular society Pandit Jawaharlal Nehru said what this concept is from Kashmir to Kanyakumari in his great book, the Discovery of India He has said what that peculiarity of India is, what its unity in diversity is, in that concept Therefore it is not a compromise but it is a reality when we had the freedom struggle stage by stage After independence we have been able to persuade Hyderabad and other small territories to come within the Indian Union It is not a compromise To say that it is a compromise would be paying disrespect to the martyrs of the country who have laid down their lives for the freedom of the country It was, as I said, not a compromise, but a reality.

[Shri Priya Ranjan Das Munsi]

We are sitting today in Parliament House where many members who by their class ideology are opposed to the tribals, opposed to scheduled castes, opposed to communal harmony and all that. We have to educate the people, don't send them. So long as we are not able to educate the people the democratic system will not give good results It is a systematic process, it is not an automatic result.

The concept of the Constituent Assembly comes in due to three major reasons:

First, while a foreign regime changes its power to a regime which is called liberated regime, it is done While the British people left India they evolved the Indian Independence Act. When the Indian people, under the leadership of Pandit Nehru, got freedom, they thought of having a constituent assembly.

Secondly, I wish to say this While some extraordinary force works outside the purview of the constitution, either revolutionary or counter-revolutionary, there may be people's upsurge and they may denounce a system demanding a constituent assembly It was mooted by JP during the Bihar agitation He said it was a 'total revolution' for a totally new India, for a totally new Constitution We opposed it Have we not opposed it? It is on record

16 00 hrs.

The third reason for having a Constituent Assembly comes when you want to have a system completely different from the present system See what was done by Mujibur Rehman in Bangladesh He did not like the Parliamentary system He approved of the Presidential system, and wanted to bring about such a system there. Here in our parliamentary system, while the Parliament is supreme, Parliament is responsible to the people.

On these three grounds, the question of having a Constituent Assembly here does not arise. Look at the sub-continent in Asia. Look at the Asian countries. What happened in the Philippines? They mooted the idea of a Constituent Assembly. What happened in Thailand? We see the military taking over power. What happened in Indonesia, in Burma? What happened in Bangladesh?

Knowing about these patriotic sentiments, knowing about the arguments made by JP, for God's sake, let us not plead for a Constituent Assembly for a new Constitution. I know the new generation may come. They may consider the idea of a revolution from a different angle. We cannot make a prescription for them. But at present, under the leadership of Mrs Gandhi, the people's will, through this Parliament, is supreme in the country and nothing whatsoever can come as an obstacle in our way

In this context the Bill as it has been amended and as it is now in the Third Reading, is going to give us a new light, a new hope, a new era, in the country Let us work in that spirit

I only make one appeal to the Law Minister while we are in the third reading We have now adopted the popular word, a revolutionary theme, in the Constitution, namely, Socialism, uttered many times by Pandit Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi but which was practised to a greater extent by our leader, Mrs. Gandhi. Please see that the main implementing authority, which is the executive, is tuned to implement it Unless we tune them to the actual concept of socialism, the main purpose will be absolutely a flop. For that reason, if we are accused of politicalising the bureaucracy, if we are accused of making the bureaucracy committed, we do not bother. We have to do it. Otherwise, the greatest task handed

down to us by our forefathers, which we have taken up just now, would be a great flop.

With these words, I further appeal to the Law Minister to gear up the government machinery in the spirit in which we think of bringing about a greater socialism in the country free from the past. And for God's sake, for heaven's sake, do not revive this idea of a Constituent Assembly. Let us revive the idea of the people's spirit, the idea that Parliament is supreme, nothing can come in the way of Parliament, that Parliament represents the people's will, that Parliament is the main custodian of the nation and the Constitution.

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया। सरकार और सरकार का नेतृत्व इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने इस संविधान के संशोधन को लाकर एक बार पुन: उन बुनियादी सिद्धान्तो की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है जो हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के आदर्श और प्राण थे और जिन के आधार पर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो संविधान बना है उसका एक दर्शन है और वह यह कि देश मे प्रगतिशील व्यवस्था की स्थापना की जाए ताकि इस देश की महान जनता और 60 करोड़ लोगों के जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। 1949 मे यह सम्भव नही था कि संविधान सभा द्वारा उन आदर्शों को पूर्ण रूप दिया जा सके जिन के लिए स्वतंत्रता संग्राम या आन्दोलन हुआ था और जो कांग्रेस का, राष्ट्रपिता बापू का, पंडित नेहरू का आदर्श था। इसीलिए बार बार इस संविधान मे संशोधन लाने की आवश्यकता पड रही है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि 1976 का भारत 1949 का भारत नहीं जबकि संविधान सभा मे संविधान के प्री-एम्बल में समाजवाद शब्द को जोड़ने पर इतना विवाद था और उसको जोड़ा नही जा सका था। आज देश में इंदिरा जी के नेतृत्व में ऐसा माहौल बना है जिस में समाजवादी शब्द पर कोई विवाद नही है। समाजवाद की परिभाषा दूसरे लोग दूसरी समझ सकते हैं, हम लोग यह समझते है कि समाजवाद समान अवसर का सिद्धान्त है, देश के प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो और सब को समान शिक्षा का अवसर मिले, रहने के लिए मकान मिले और पहनने के लिए वस्त्र मिले। और सर्वोपरि उन्हें शिक्षा का समान अवसर मिले तथा साथ ही साथ उनके जीवन यापन के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सके। 1976 का भारत एक नया भारत हैं। 1976 का भारत 1949 का भारत नही है इसलिए 1976 के भारत को नये संविधान की आवश्यकता है। आज संविधान पर बुनियादी रूप से विचार करने की आवश्यकता है। प्रश्न उठता है कि यह किस तरह से हो सकता है। मैं समझता हू संसद् काफी समर्थ है और इस संसद् के द्वारा देश को एक नया संविधान दिया जा सकता है। हमने देखा कि बार बार कचहरियों द्वारा समाजवाद की दिशा में बढ़ने मे बाधायें उत्पन्न हुई हैं। आज भी जो हम 268 धारा मे संशोधन ला रहे हैं उसके द्वारा ला कोर्टस के अधिकार को सीमित ही कर पा रहे हैं। मैंने यह संशोधन दिया था कि इस संविधान संशोधन विधेयक में यह विधान होना चाहिए कि संसद या विधायिकाओं द्वारा पारित जो कानून होंगे उनके स्पष्टीकरण, उनके कानूनी रूप पर विचार करने या उनका लेखा जोखा करने का अधिकार इस प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद् द्वारा नियुक्त एक 25 सदस्यीय समिति को होगा तथा वह समिति यह बताने के लिए समर्थ होगी कि किस तरह से संविधान मे संशोधन लाये जाये और जो कानून बनते हैं वह सांविधानिक दृष्टि से ठीक है या नही। मै सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर विचार होना चाहिए। मैं इस बात को नही मानता कि जो जनता के प्रतिनिधि है, जो इस देश की प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद् है वह जो कानून बनाती है सारे देश के लिए उसपर विचार करने का

[श्री हरि किशोर सिंह]

अधिकार थोड़े से नियुक्त हुए किए व्यक्तियों को है । जुडीशल रेव्यू का सिद्धांत इस देश के संविधान मे नहीं है मैं चाहता हू इसका सपष्टीकरण हो जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं पुन इन साविधानिक सशोधनों का समर्थन करता हू और समझता हू देश की प्रगति की दिशा में यह एक कदम है और आगे फिर ऐसा समय आयेगा जब हमारे संविधान को समाजवाद की दिशा मे और आगे ले जाने के लिए और सशोधन आयेंगे तथा हमारी देश और आगे प्रगति की ओर बढेंगे ।

SHRI P G MAVALANKAR (Ahmedabad) Sir, I am rising to register once again my opposition to this omnibus Bill which contains several drastic provisions making the entire constitutional structure highly centralised, almost to the point of being unmanageable, impracticable, for a vast and great country like ours My opposition is also because of the fact that this particular Bill which this House is about to pass brings an almost qualitative change in our constitutional structure The tragedy of the situation is that by this 44th amendment Bill, the citizens, the courts of law, the states, the President and indeed even this House of Parliament are all sought to be denigrated and only the Union executive is sought to be made to thrive, grab and aggrandise This Bill is therefore opening the floodgate, indeed more than one floodgate, to regimentation and dictatorship That is why I had to oppose the introduction of the Bill when it came up on the 1st September and again when it was discussed here last week at the consideration stage; I am also now doing it in the third reading

Before I come to the main Points, may I with your permission take a little more time to clarify on two speeches particularly from the Congress benches? My good friend Shrimati Mukul Banerjee who followed after my speech last week, on 27th October, had among many other things this to say· "I would like specially to remind Mr Mavalankar that his father who was here supported that amendment" She was referring to the 1st Constitutional amendment moved in 1951 I do not want to go into other details, I want only to tell her that my father was at that time the Speaker, how could he either support or oppose that particular amendment? She should have done her home work a little better

Sir the Hon'ble Prime Minister referred to the Constitution or "The Basic Law" of the Federal Republic of Germany I have a copy of it here The Prime Minister quoted Article 18 dealing with 'Forfeiture of basic rights' But she did not read out the whole Article She left out the last and telling sentence in it, that is,

> "Such forfeiture and the extent thereof shall be pronounced by the Federal Constitutional Court"

And in the next Article 19(2), it is stated further as

> "In no case may the essential content of a basic right be encroached upon"

So, Sir you will see that it is no use merely saying that the basic rights, liberties etc when converted into licences can be curtailed Of course, they can be curtailed, but the moot question is· Who will decide it? Surely not Parliament, not executive but only a constitutionally established court of law, the Supreme body, the judiciary

Now, this Government is strengthened today by a majority, if I may say so, an arrogant yet obedient majority—but I want to tell a good number of my friends here—that although you are in a strong majority, you are not sustained and strengthened by morality, in what you are doing today. I

agree that a majority is not always wrong, but neither is it always right! And, because a thing is supported by a majority, it does not necessarily mean that it is fair, just or wise. What is being passed today has no sanction of the peoples' thought, opinion, will and consent. So many thinking persons and countless commoners outside this august House are sincerely and solidly opposed to this Bill. If the Government, in their present mood and temper of riding rough shed over everything, chooses not to look into those dissenting views, well it is the Government's business. What is more important is that the Opposition, a big chunk of it, have abstained from this entire debate of this Constitution Amendment Bill. I will not go into the merits of their decision or otherwise. It is for them to decide. I have nothing to opine this way or that way, but the fact is that they have abstained from the proceedings of Consideration of this Bill, and, indeed, some of our colleagues significantly belonging to both sides of the House are still behind the bars, and yet, Government have been passing this Bill! But it can also one day suddenly be demolished, as easily and swiftly as it is being passed today.

Now, you say that the Parliament 9th December 1946 and 26th November 1949 laboured for long and took so much pain "to enact, adopt and give to ourselves this Constitution. But this Government has done all this with the help of the present Parliament in just 8 days! And, all this is being done by this Rump and rubber-stamp Parliament! In the 1971 elections, the total votes polled were roughly 54 per cent. The Congress Party's votes then was just over 43 per cent. How can this 43 per cent be equated to the national, near total will, particularly for matters of Constitutional changes?

Now, you say that the Parliament is supreme, but it is a myth. Not only that, it is a dangerous doctrine. For, it would mean in reality supremacy of the Parliamentary majority which in turn means of the Parliamentary Executive, nay of the Parliamentary Caucus and ultimately, indeed, of one leader and he or she then is supreme. The concentration of power, centralisation of authority, defication of one or perhaps two individuals, shutting down all free opinion, cornering the judiciary and regimenting the citizenry—all these are on the Dictator's Menu. They are certainly not on the Democrat's table. All this regimentation and authoritarianism is on the menu of a dictator.

The Law Minister Shri Gokhale's speeches in the House during these last eight days are a definite contempt of the court, in the context of our judicial system and practice. The minister has been threatening the judiciary when he says "No confrontation with Parliament"; it is nothing but an outright intimidation! When you yourself are having a confrontation with the judiciary, you are telling them not to have confrontation with Parliament! Moreover, Sir under article 368, Parliament's amending power is not unlimited. If you have unlimited power, you come to an absurd situation. We can then undo what has been done by our previous fellow countrymen and Constitution-makers. Parliament is a creature of the Constitution. Constitution is above Parliament. And, of course, the people are above the Constitution. But have the people been consulted adequately and fully? For, if they were, I am sure they will never agree to signing their own death warrant!

Sir, Article 14 and 19 guaranteeing Fundamental Rights are being reduced to mere pious platitudes. There are certain rights of individual citizens which even the majority must not take away, like freedom of conscience, freedom of expression, freedom of assembly and freedom of association. Presence of these rights is a hall-mark of open society. Judicial review is also being drastically curtailed, to the detriment of the health of a democratic policy.

[Shri P. G. Mavalankar]

So, Sir, I oppose this Bill because (a) I am opposed to arming the executive with vast, arbitrary, almost unlimited powers; (b) because I stand for a just and healthy relationship of the State with the individual; and *not* for the erosion of the liberties of the individual and in the end, indeed, the elimination of the individual; (c) because we should not use our amending power to destroy the well-laid basic tenets of our Constitution; (d) because we cannot be just outwardly constitutional, be formal and correct in letter only, but not being truthful and honest and democratic, (e) because I am opposed to absolute power in the hands of the rulers without the institutionalised checks and balances, and (f) finally because there is no popular consensus behind this Bill

My fervent appeal to my Congress friends is this. You seem to be fearing nobody because you have got blanket powers But be at least God-fearing! For, God will not forgive the sins you are about to commit when the House passes this Bill today!

श्री स्वामी अछूतानन्दजी (हमीरपुर) सभापति महोदय, मैं यहां पर इस संविधान (संशोधन) विधेयक पर हुए भाषणों को सुनता रहा हू और आज तीसरे वाचन पर बोल रहा हू ।

मैं कहना चाहता हू कि आखिर ये सरकारे क्यों बनाई जाती है ? ये जनता के लिये होती है और यहा पर जो लोग आते है वे बालिग मताधिकार से चुन कर आते है । मैं पूछना चाहता हू कि ये जो सिद्धान्तविहीन पार्टिया है, ये क्यो नही चुन कर बहुमत मे आ जाती हैं ? इसलिए जो चुने हुए एम० पीज हैं उन के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वे जनता की भलाई के लिए संविधान मे संशोधन करे । दूसरी पार्टिया आज नही रही हैं और सिद्धान्तविहीन पार्टिया खत्म हो गई हैं । इसलिए अब जो जिम्मेदारी है वह कांग्रेस की जिम्मेदारी है और हमारी प्रधान मंत्री श्री ने बहुत सही कदम उठाया है, हमारे न्याय मंत्री जी ने सही कदम उठाया है लेकिन मैं यह कहूंगा कि हिम्मत कर के थोड़ा सही कदम उठाया है क्योंकि मैं तो कहता हूं कि ये हाई कोर्ट के जो जज हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इन की कोई जरूरत नही है । ये अंग्रेजों की देन हैं । यह काम पंचायतों से हो सकता है । हमारी जो पंचायतें हैं, हमारी जो जिला परिषदें हैं और हमारे जो एम० पी० अथवा विधायक हैं जोकि जनता के द्वारा चुन कर आते हैं, इनको आप अधिकार दीजिए । पब्लिक अगर इन से नाराज होगी तो दूसरों को चुन लेगी । इसलिए आप ने जो उठाया है वह थोड़ा सा बढाया है । मैं तो कहता हू कि क्या यह विधान था कि जो अमीर था वह और अमीर होता गया और गरीब और गरीब होता गया और यह क्या विधान था कि नौकरशाही का राज्य हो गया । इस के अलावा मैं यह कहूंगा कि ये न्यायालय क्या हैं ? ये न्यायालय हमारे ही बनाए हुए है । इसलिए न्यायालय हमारे नीचे हैं, ऊपर नही । हम क्या तलवार बनाने वाले लोहार हो गये और तलवार चलाने वाले ये नौकरशाह जोकि हमारा ही गला काट देना चाहते है । ऐसी बात नही है । मैं तो कहता हू कि पूरा अधिकार संसद् को है और पूरा अधिकार जिला परिषदों को है । अंग्रेजी जमाने मे जो जिला परिषदे थी, उन को जो अधिकार थे वे आज नही है । उन के पास स्कूल थे और सडकें थी । आज सारे काम आप ने नौकरशाही के हाथों मे सौंप रखे है ।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हू कि प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति, इन दो की जरूरत नही है । मेरा कहना यह है कि सिर्फ प्रधान मंत्री होना चाहिए और राष्ट्रपति की कोई जरूरत नही है । क्या जरूरत है कि ये दोनों के दोनों ही आज राष्ट्रपति के यहा पचासों और सैकड़ों आदमी रहते है । जरूरत आज इस बात की है कि इतने बड़े मैदान राष्ट्रपति भवन मे, कोठियों, गरीबों के लिए

अस्पताल हों और स्कूल हों । मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट किस का बनाया हुआ है । यह अंग्रेजों का बनाया हुआ है । विधान बनाना हम लोगों का काम है और यहां पर जो लोग आए हैं वे बालिगमताधिकार से चुन कर आए हैं । इसलिए संशोधन करने का उन को अधिकार है ।

इन विरोधी लोगों को, सिद्धान्त विहीन लोगों को ठीक करने की हम दवा देंगे, इन को हम ठीक करेंगे । चाहे जयप्रकाश हों, चाहे अजयप्रकाश हों, सबके दिमाग ठीक करेंगे । काहे के लिए ठीक करेंगे ताकि जनता को आराम मिले । आज हरिजनों में विषमता है मजदूरों में विषमता है । वेद, पुराण सब कुछ है लेकिन मजदूर वहीं बैठा हुआ है और ब्राह्मण उसके ऊपर बैठा है । ब्राह्मण और हरिजन सभी एक समान होने चाहिएं । समाजवाद का यही अर्थ है कि सारे प्राणी एक समान हों । सब को भोजन मिले, सबको वस्त्र मिलें, सब को न्याय मिले ।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन लडने जायगा ? जिनके पास 5–6 हजार पया हो, वही लडने जायगा । हम बधाई देते हैं अपनी इंदिरा गांधी को और न्याय मंत्री को कि उन्होंने यह सब कुछ किया । बिचारी इंदिरा गांधी हिम्मतवर हैं, मगर उनके हाथ कमजोर हैं । मैं कहता हूं कि इंदिरा गांधी दिन-रात काम करती हैं, उनका कोई मन्त्री कमेटी में बैठा है, कोई मन्त्री बाथ रूम में बैठा है । इंदिरा गांधी सुबह चार बजे से रात के बारह बजे तक काम करती हैं । हमारी प्रधान मंत्री ने बडी हिम्मत के साथ कदम उठाया है । प्रधान मन्त्री ने रही सही आदमी को कांग्रेस से निकाल दिया ।

जब देश में हत्याएं होने लगी, तो हमारी प्रधान मन्त्री ने देशद्रोहियों को ठीक किया । अगर हम गांधीवादी न होते तो इन देश-द्रोहियों को एक लाइन में खड़ा करके गोली से उड़वा देते । मगर यह गांधी का मुल्क है, विवेकानन्द का मुल्क है । हमारी इंदिरा गांधी जगत जननी हैं । हम गांधीवादी हैं । यह हम नहीं होते तो इन देशद्रोहियों के साथ गोली से काम लिया जाता । पर हम ऐसा नहीं करेंगे । क्योंकि इंदिरा गांधी जगत जननी हैं और वह नहीं चाहती हैं कि इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाय । इंदिरा गांधी ने बराबर सबको, चाहे वे विरोधी हों या और कोई हों, एक भावना से देखा है । वे जयप्रकाश जी जैसे आदमी से भी बात करती हैं ।

मैं इतना ही कहूंगा कि पूंजीवाद के खिलाफ हमारी सरकार ने, हमारी कांग्रेस ने कदम उठाया है । सारे समाज में अगर पंचायती राज होगा, चुने हुए आदमी उसमें होंगे तो वे न्याय करेंगे । अगर वे गलती करेंगे तो फिर नहीं चुने जायेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha). Mr. Chairman, Sir, I rise with a deep sense of gratification and a feeling of elation to support this Bill. The observations of Mr. Mavalankar are such as if something terrific is taking place today I would appeal to him to assess this Amendment Bill with a certain measure of objectivity and without any pre-conception or prejudice. As I said in the first reading of the Bill, I do not find anything shattering in the Bill as some people are attempting to make it out.

Sir, the year 1976, according to me, is a water-shed and a major milestone in the long march of the nation to transform the destinies of this country by sharpening and reforming the Constitution 25 years ago, we enacted the first constitution amendment. First, look at the provisions of that amendment. With one stroke, we put restraint on the freedom of speech and we provided for the state mono-

[Shri C. M. Stephen]

poly over the private enterprise. Article 31A dealt a blow on the zamindari system.

The most sweeping of all was the introduction of the Ninth Schedule concept, whereby any law which is put in the Ninth Schedule would just sweep out the entire fundamental rights. We have now put in the Ninth Schedule about 300 Acts. We introduced certain amendments even with respect to the House of the People. I am saying that even in the first year, when the Constituent Assembly was sitting as Parliament, it introduced amendments abridging the fundamental rights, sweeping away the fundamental rights, and the inclusion of laws in the Ninth Schedule was the most revolutionary thing. Therefore, in the course of the 20 years, which ended with the beginning of this Parliament, a large number of amendments have been taking place.

The Constitution (Fourth Amendment) Act practically ruled out the property rights. The Constitution (sixth Amendment) Act introduced new provisions with respect to taxation and altered the first and second list. The Constitution (Seventh Amendment) Act brought about territorial adjustment in the country and the territorial pattern of the country was changed. The Constitution (Fifteenth Amendment) Act dealt with the Judges and assumed power to decide questions relating to their age. That power was assumed by Parliament and then it was given to the President. By the Constitution (Seventeenth Amendment) Act, article 31A was amended and 44 Acts were put in the Ninth Schedule. By Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, article 368 was amended, declaring that Parliament has got the constituent power. Subsequently, during the course of the last five and a half years, we have amended the Constitution 20 times. The princely privileges were abolished and banking was nationalised. Therefore, in the course of the last 25 years, before the Constitution (Forty-second Amendment) Bill was brought in, many amendments were brought in one after the other, touching every sphere of the Constitution that was framed in 1949. If I may be permitted to say so, the Constitution that we gave to ourselves in the year 1949 was far far different from the Constitution that we are now having. Major changes have been brought about. Nothing new, nothing shattering is taking place today because of the Forty-second Amendment.

In spite of that, there was never a national debate. For the first time, we had a national debate, preceding the Forty-second Amendment Act, a very long national debate, the details of which have already been explained in this House. Why did we have a national debate? Because, we have now rung a curtain on a particular period and we are starting on a new period.

The new amendments which we are bringing about have got certain significant changes. In the first place, the preamble comes out with a strident note that this nation stands committed to socialism and secularism. A perfectly strident note coming out of the change of the preamble is the announcement that a determined new era is coming, about which there is no doubt. Another important change is the supremacy of the Directive Principles. Formerly, it was only with respect to some sub-clauses of article 39. Today we say that every item of the Directive Principles is supreme and the effort of the State Legislatures and Parliament should be to be in conformity with the Directive Principles, overriding every other consideration. If by putting an Act in the Ninth Schedule, it can override the entire Third Chapter relating to Fundamental Rights, what is wrong in saying that a law, rather than being put in the Ninth Schedule, if it is in pursuance of the Directive Principles, should override three Articles in the Fundamental Rights Chapter, I do not understand.

A new branch of law, the administrative law, is beginning to develop in this country So far we have been tied down by what is known as the Anglo-Saxon jurisprudence system We are now having a departure into administrative law The dictum of Dicey that administrative law was a negation of the rule of law has been thrown into the limbo of the past It has lost its relevance after the French developed administrative law and showed the world the way in which it should be developed

Finally, the supremacy of Parliament is established I spoke about the confrontation between the judiciary and the legislature and I felt that the amendment that was brought to article 368 was not sufficient to meet the challenge I am deeply indebted to the Government for taking note of that and further amending article 368 Now, amendments of the Constitution are put beyond the purview of the courts We have said that the power of this Parliament is unlimited This is for those who have the ears to hear and the minds to understand This has got to be done Now, the power of this Parliament is declared to be without any limit and the laws passed by this Parliament by way of amending the Constitution are declared to be out of bounds for any court It is left to the courts whether they should defy it I do not know whether they will have the temerity to do that but if they do, as the Law Minister said, that it will be a bad day for the judiciary The Committee of the House is sitting with regard to the enquiry into the conduct of Judges and all that We have got our methods, our machinery I hope this final decision will be accepted by everybody The unquestioned authority in this country is, has to be, and will continue to be, whatever may be said by anybody, the Parliament of India, and its voice will have to be listened to by everybody, it will have the final say in all these matters. That is declared beyond any doubt

What will follow immediately Immediately a large number of laws and regulations which today remain imprisined in the portals of the courts will have their freedom They will be released Stay orders will stand vacated, and the bunch laws which were meant for the people will now have a forward march

I am grateful to the Government for having shown a complete sense of responsiveness to the debate that has taken place For instance, when the lacuna in article 368 was pointed out, it was rectified when the lacuna regarding Parliamentary rule-making power was pointed out, it was rectified When the Central laws were defined, it was pointed out that unless the amendments under article 368 were specifically put beyond the Central laws, the Supreme Court might catch hold of it and might start adjudicating It was rectified Similarly it was pointed out that if a State Government issued rules and regulations under a Central Act, to that extent it should be considered a State law, so that the citizen may not have to go to the Supreme Court That was accepted by Government

Still I am not saying that there is no defect at all I have got my reservation on one or two clauses I do not want to say anything more on that But I finally say that this effort of Parliament to reshape the Constitution in conformity with the conditions changing from time to time has reached a particular stage The curtain is drawn and a new start is being made, a start with the confidence that we can face up to all challenges, a start with a strident note that the nation is completely committed to socialism and secularism.

The one hing is that we have raised the period to six years. There were some reesrvations about it here I do not understand why should there by any reservation from the CPI benches Mr Indrajit Gupta has said that if it is four years, then he would agree to

[Shri C. M. Stephen]

it. By the same logic, he can agree to 3 years or two years or even one year. He can say that if it is two years, it is better; if it is one year, it is still better and so on. If an election takes place every week, it is much more better. Is this his yardstick? I do not understand it.

If the extension of the House is immoral, then he should have opposed it. The period was extended in the Kerala Legislative Assembly also. There was no opposition to that. They were supporting it completely Let there not be two stands.

The position is that the country, according to us, is passing through a revolution and a transformation. This is not the time when you try to go back and quail. This is the time when you must stand up to the task. Here is a Constitution which is Sharpened to serve the purpose. Taking the stand on that basis and under the cover of the Constitution and the liberalisation that has been given, let us march forward to accomplish the task Therefore, with complete gratification, I support this motion without reservation Let us march forward with this end in view and try to achieve our goal of socialism and secularism

SHRI VAYALAR RAVI (CHIRAYINKIL) I congratulate the Prime Minister for giving her leadership for this Bill and Shri Gokhale for ably piloting it All the amendments of the Constitution have been forced on us by the third chamber, the Supreme Court The Government all the time is forced to bring amendments whenever they feel that the third chamber is taking their own decision to prevent the progress of the nation What is this Constitution? Is it ornamental? I do not want to go into the legal question of the Constitution and so on

The ordinary citizens of the country got freedom from the Britishers after the long struggle against them. Naturaly, they will ask for what purpose they have won this freedom. 30 years have passed. It means that two generations have passed. Freedom does not mean the right of franchise after five years. It means freedom from hunger and poverty. All the time, the State Governments and the Centre have been making laws for the betterment of the people. We find, all the time, that this third chamber is coming in the way. There are millions of people in our country who do not have any shelter. Let us take the example of my State Kerala. There was one Bill which was meant for giving land to the landless people. It had been questioned in the Supreme Court At last, the Government of India had to come to the rescue of the Bill. Otherwise, about three lakh people who got the tenancy right would have been put to loss.

Mr. Mavalankar was speaking about the Constituent Assembly They would have a long debate on it. What is the purpose of the whole debate? Does it mean exploitation of the poor people? In the last 30 years, it has been proved that it has degenerated into an instrument of exploitation of the poor people.

Now, in the name of freedom, in the name of democracy, they have served their vested interests There has been an economic growth for only a few people The poor people have suffered all the time Every progressive legislation is nullified by the Supreme Court, the third chamber

The time has come when after the two generations, we have to think about many basic amenities of the people not only about these amendments Many hon Members here have spoken about the first amendment to the Constitution The first amendment to the Constitution itself is an example of how the Constitution has stood as a stumbling block to the progress of the nation On the basis of the Directive Principles, the Bihar Government thought that they could enact some legislation touching the tenancy rights. It was questioned in the High Court. The High Court said

that it was against the fundamental rights enshrined in the Constitution. Even in the very first year of its coming into being, the High Court and the Supreme Court started interpreting the Constitution not only against the progress of the country but even stood in the way of a little benefit being given to the people. In the circumstances, Pandit Nehru, the great leader of our country moved the first amendment to the Constitution in the very first year, soon after the long debate in the Constituent Assembly. The Constitution had become an instrument in the hands of the few to block the progress of the nation and to look after their own vested interests. The rich became richer and the poor became poorer.

I do not say that this Constitution amendment will make everything perfect. But certainly it is only a beginning. And it is a beginning for the better. This will make a way for the better future of our country.

The elections have been postponed by another one year. Mr. Stephen has ably dwelt on that. I do not want to comment on it. This is a period of transition. After amending this Constitution under which the Directive Principles have been given a priority, it is the duty of the Government to prove that to the people and convince the people about the purpose of the amendment of the Constitution. If that is to be done, the Government could not divert their attention by going in for elections. The Government needs time, whether it is one year or two years, to do that. That is why elections have been postponed.

The hon. Member, Mr. Mavalankar, said that Parliament is not supreme We derive strength from the people. The democracy derives strength from the people; the Parliament derives its strength from the people. We are the representatives of the people and we are voicing the views of the people in Parliament. It is Parliament which is supreme. As the Prime Minister said the other day, the Parliament has got the right to amend and change the Constitution to any extent.

With these words, I support the Bill and I congratulate the hon. Law Minister for the able way in which he has brought forward this Constitution Amendment Bill. I hope, this will be for the better future of the country.

SHRI S. A. KADER (Bombay—Central-South): Mr. Chairman, Sir, the curtain will rung down after the third reading of the Bill is over.

We have really made good progress. As far as the Constitution amendment is concerned, all the amendments that have been proposed have been carried through successfully. Our Constitution came at a time when the very makers of the Constitution were agitators and they were involved in movements. They had only one business, that is, of opposing the foreign powers and to incite the people against them. It was their duty. That was the patriotic duty which they did. Therefore, at the time of Constitution making, the experience that was needed was not available to them.

Therefore, we can say that this Constitution which had emerged in 1952 was a sick Constitution because in the very first year, the first Amendment came. Now we have 44 Amendments, the Forty-Fourth having 59 Clauses in it. All these show that the Constitution as such needs looking into at various levels and as circustances arise.

I want to deal with one aspect of the Constitution. The powers of the courts have been reduced so far as government's action and its services are concerned. It is very good and I welcome it. But at the same time, much needs to be done to bring in accountability in the adminisration. In my humble opinion, what is needed

[Shri S. A. Kader]

is not a Tribunal but an internal structure for justice with a time limit so that every case is disposed of within the proper time. The most important thing is that there should be a revision of the Service Rules which were framed by the British Government. If that is done, I think, the accountability will be brought in, and what is needed in administration today is accountability.

It is well known that the sovereign power is with the people. The people have the right to elect their Members of Parliament and Legislatures. But when it comes to Assemblies and Parliaments, the sovereignty disappears. The three organs under the Constitution are the Parliament, the Executive and the Judiciary. The sovereignty should run to its logical end, but that does not appear to be happening. Therefore, I feel that the time has come when we should have a second look on our Constitution. After this great debate which has taken place throughout the country, in various seminars, and also in this House. Also very responsible organizations have said that this House should convert itself into a Constituent Assembly. Punjab has gone a little further and suggested that the country should get the Constitution which it needs. I would, therefore, suggest that, in order to have a proper idea of our future Constitution, the present Constitution must be completely analysed on the basis of our experience of its working in the last 24 years and the negative and positive aspects have to be tabulated and brought before the public and the Parliament in the form of a White Paper. This White Paper should be prepared as soon as possible, and in that we can bring out the deficiencies and also the positive aspects which have resulted from the implementation of the provisions of this Constitution. If that is done, to my mind, the thinking on the future set-up of our Constitution will be absolutely logical and relevant. Without a White Paper, without a critical analysis of the working of the Constitution in the last 24 years, we will not be able to come to proper conclusions, and amendments after amendments will be brought which will not serve the purpose. I welcome this Constitution Amendment Bill, but I do not see a complete solution of our problems in this.

A kind of accountability has been brought about by Emergency. What we want is that this accountability and stability should be always maintained. Therefore, I would humbly suggest this to the Law Minister. Although we accept this Bill, we would request him to consider this suggestion about preparing a White Paper on the Constitution. Now, who will prepare this White Paper? Not only Members of Parliament, there may be experts in social sciences, there may be experts in political science, there may be administrative experts and others—all these people should be put together and a time limit set to bring out a White Paper and that White Paper should be placed before the Parliament . (*Interruptions*) Ordinary man is represented by the people's representatives who will be there.

Therefore, in that context, if a White Paper is brought out, I think it will go a long way in enabling us to come to a right thinking about the future constitution.

That is all I wanted to say.

SHRI R V. SWAMINATHAN (Madurai): Our Prime Minister has been telling the country that this Parliament is supreme and it has got every right to amend the Constitution Accordingly, now her stand has been vindicated by passing the 44th Amendment to the Constitution.

In this constitution, the preamble has been changed by adding two words, socialist and secular, that India shall be a sovereign socialist, secular, democratic republic. When

I think of 'socialism', my mind goes back to what has happened 40 years ago in this country. It has been rightly pointed out by Mr. Indrajit Gupta the other day during the general debate, that in the Lucknow Congress in the year 1935, our great leader Pandit Nehru, in his presidential address, declared that socialism was the only solution to this country. Next year in the Faizpur Congress also over which he presided, in his address he reiterated our goal and further defined what sort of socialism he wanted. He wanted scientific socialism. Afterwards, in the year 1955, at Avadi near Madras, our idea was changed. Then a socialistic pattern of society was declared as our aim. Then, in the Bhubaneswar Congress, it was resolved that a socialist society should be established in the country.

Once upon a time, during British rule, if anybody uttered the word 'socialism', he would have been immediately arrested and sent to prison. But it was Pandit Jawaharlal Nehru who first came forward to mention that socialism was our aim. Now, the dream of Jawahar Lal Nehru is being fulfilled by amending the constitution as SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC.

No society is static. It changes. We are in transitional period. There is a revolution taking place in the country in all walks of life and in the society. Therefore, we have to amend our basic document. This amending Bill, according to me, is not sufficient. We must amend the entire Constitution and redraft the entire constitution for which there must be a Constituent Assembly. I appeal to the Government and also to the Prime Minister that we should have a Constituent Assembly.

The word 'socialism' should be properly used and the high ideals of 'socialism' should be properly defined and clarified. Various countries call themselves socialist countries. The East European countries are all socialist countries. But every country has its own pattern of socialism according to their own conditions. Therefore, the Government should come forward and also some public organizations should organise seminars on socialism according to Indian conditions and focus public attention on this matter and define what type of socialism our country should have. France achieved independence after a great revolution. They have a different type of socialism. Whether that will apply to our country or not is a question. Therefore, I appeal to the Government and the Law Minister that something should be done to define 'socialism' and indicate what type of socialism India will have.

Then a new clause 43 has been inserted Some members even on this side and on that side expressed some fears that it is giving more powers to the centre to send central forces to the States.

In this connection, I want to inform the House one instance. During the year 1967 when the elections were held, in Tamilnadu, the DMK party came to power. The DMK Government was formed under the leadership of Shri C N Annadurai. There was some trouble in the whole city after a month or two. A train was coming from south. This train has to stop at Madras Egmore which is the terminal station. Before that there is a station called Membalam where the train was forcefully stopped When the train stopped, some rowdy elements went to a petrol bunk and got some petrol cans and sprinkled the petrol on the train and they set fire. Large number of police men were also there who were looking at them. People nearby asked the police to intervene. The Police said: 'We have got orders not to interfere; We cannot do anything but only watching'. Suppose such a thing is done, is it not the duty of the Police

[Shri R. V. Swaminathan]

and the security forces to stop destruction of public property? Therefore, it is right that this New Clause 43 is inserted.

Regarding Clause 46, it is a new clause and as per this clause we are going to create new administrative tribunals. We have given very wide powers. I request the Minister and the Government to look into the matter and be careful that when they are taking such wide powers, they take into consideration and look after the interests of the backward classes and the other minorities.

With these words I support the Bill.

PROF. S. L. SAKSENA (Maharajganj): Mr. Chairman, Sir, Today will go down as the darkest day in the history of this Lok Sabha when this Constitution 44th Amendment Bill, 1976 will be passed by this House.

This Bill proposes to take away out most cherished Fundamental Rights and subordinates them to Directive Principles. By Article 31 (D), it makes all anti-government activity anti-national, including even non-violent satyagarh against unjust laws and their tyranny which Gandhiji taught us to resist as a scared duty.

This Bill exhibits serious distrust and lack of confidence in the President, the Chief Justice and other Justices of the Supreme Court and the High Courts, Comptroller and Auditor General of India and the Election Commission. The Constituent Assembly took the greatest care to ensure the sturdy independence of these bodies. But this Amendment Bill demolishes their independence and makes them subservient to the Cabinet, which means its Chief Executive, the Prime Minister.

It amends article 368 in a manner which enthrones the deceptive doctrine of the supremacy of Parliament above the supermacy of the Constitution which the judgement in Keshvanand Bhartis' case had settled.

The best thing about the Kesvananda's case is that it is a decision given by the full Court Bench; there cannot be a bench bigger than the one consisting of 13 judges which heard this case. It is this aspect which should be welcomed. It makes the position certain. The declared and settled law of constitutional amendment is that Parliament can amend the Constitution including Part III subject only to the limitation that an amendment cannot impair the essential features of the constitutional edifice. The limitation grafted upon the power must protect and preserve the Constitution, without making it unamendable. Amendments can be made to permit the State to strive "to promote the welfare of the people by securing and protecting, as effectively as it may, a social order in which justice, social economic and political, shall inform all the institutions of the national life." The State is not prevented from its duty "to apply" the Directive Principles of State Policy without avoidable damage to the core of the Bill of Rights. However, it rejects the legal supermacy of Paliament; and thus saves the country from over emotionalism and sloganism of a temporary legislative majority in Parliament. It saves the people from the tyranny of the majority bent upon doing little and undoint vast. It still puts Supreme Court in the central position, by putting in it an ultimate jurisdiction to review amendments and laws solely in discharge of its high inalienable obligation to preserve and protect the Constitution. This jurisdiction must be exercised sparingly; and the Court must in all normal times raise the presumption that Parliament acts to amend the law to secure and promote the objectives declared in the Preamble. The presumption must approximate to irrefutability, except

only when an amendment is nothing short of an act of political subversion and sabotage.

17.00 hrs

The emerging situation must make the Court assume an important role as an institution of the national life side by side with Parliament and the Executive Any two of them should not be at loggerheads with the third The Court must not be in a situation of confrontation either with Parliament or with the Executive or with both Parliament must remain the central focal assembly of the representatives of the people with a clear mandate to speak, decide and declare the will of the people on all delicate and complex issues It may, if necessary, amend the Constitution which would not be disallowed by the Court, merely because it would permit what is forbidden in connection with enactment of laws in contradiction of article 13(2) and this may provide for even an abridgement of a fundamental right Nevertheless, the Court must disallow an amendment which deprives the people of their Fundamental Rights destroys the core of the Bill of Rights or otherwise impairs the basic tenets, aspects, maxims, forms, features and violates the underlying principles, mandates and precepts of the makers

I challenge the Government to point out any Constitutional Amendment after 1971 which was intended to promote socio-economic revolution being struck down by the Supreme Court

The only Constitutional Amendment struck down by the Supreme Court after 1971 was the 39th Amendment Act which was not a socio-economic measure at all

The very fact that both the Houses of Parliament passed this 39th Amendment Act, 1975 and the Rajya Sabha passed the 41st Amendment Bill, 1975 is the most powerful argument that Parliament cannot be supreme and cannot be allowed to amend the 'Basic structure of the Constitution'.

Clause 329A of the 39th Constitution Amendment Act, 1975, which was struck down shamelessly, asserted that—

> "No election to either House of Parliament of a person who holds the office of Prime Minister at the time of such election or is appointed as Prime Minister after such election shall be called in question"

So even if the Prime Minister is elected by committing the worst corrupt practices, his election cannot be challenged in any court of law

This was obviously intended to nullify the judgment of Justice Jagmohan Lal of the Allahabad High Court declaring the election of our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, invalid on grounds of commission of corrupt practices

The Constitution 41st Amendment Bill, 1975, which has been passed by the Rajya Sabha, but has not yet been introduced in Lok Sabha, says in its clause 2(2) as follows .

MR CHAIRMAN He may lay it on the Table.

PORF S L SAKSENA It says·

> "(2) No criminal proceedings whatsoever, against or concerning a person who is or has been the President or the Prime Minister or the Governor of a State, shall lie in any court, or shall be instituted or continued in any court, in respect of any act done by him, whether before he entered upon his office or during his term of office as President or Prime Minister or Governor of a State, as the case may be, and no process whatsoever including process for arrest or im-

[Shri S. L. Saksena]

prisonment shall issue from any court against such person in respect of any such act".

What a contrast to our Parliament is presented by the Congress of the United States where President Nixon was going to be impeached for having committed corrupt practices in his election as President of USA and to save himself from impeachment he had to resign.

Like Justice Jagmohan whose sturdy independence in finding the Prime Minister guilty of corrupt practices brought lustre to the Indian judiciary for its sturdy independence, similarly the Supreme Court rose very high in public estimation when it struck down the Constitution 39th Amendment Bill, which, as a consequence, Government have not dared to introduce in Lok Sabha so far.

The Supreme Court ruling about basic structure of the Constitution not being unamendable still stands. I had, therefore, raised my objection at the time of introduction of this Bill in the House on 1st September, 1976 that in view of the aforesaid ruling of the Supreme Court this discussion on this Constitution 44th Amendment Bill was beyond the competence of this House and so it should not be allowed to be introduced.

But the Speaker overruled my objection and allowed the Bill to be introduced. And the House is now debating the Bill on its third reading.

But I warn the Government that all this labour in passing this Bill has been futile; the Bill, if passed into law, will be struck down by the Supreme Court.

Before I close, I will refer to cl. 13 of the Bill which says in so many words that the President shall be bound to carry out the advice of his Council of Ministers.

This is the convention, but no democratic constitution lays it down in so many words in its constitution. I have read the Constituent Assembly debates on this point. There all our great leaders, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and great jurists like Alladi Krishnaswami Aiyar, Shri K. M. Munshi and Dr. B. R. Ambedkar opposed such a provision being incorporated in the Constitution.

We are now defying all our great leaders and great jurists by incorporating section 13 of this Bill in our Constitution. God help us.

It is because of this nature of this Constitution 44th Amendment Bill that I have been forced to oppose almost all its clauses. If the voting had not been omnibus on the clauses after all of them had been discussed several days before, I might have voted for some of the clauses in the Bill.

But in the circumstances of omnibus voting on the clauses days after they had been discussed, I had no choice but to oppose everyone of them except the clause about amendment to VII Schedule which brings education in the Concurrent List which I had demanded in the Constituent Assembly as well.

Sir, I oppose the Bill tooth and nail and I am happy that I have done my duty fearlessly as taught by Gandhiji. Sir, I oppose the Bill.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. The hon. Minister of Law will reply at 5.30 P.M. Meantime we have to accommodate all the remaining speakers. I think there is hardly time though some very able speakers are left out. We can accommodate all if they take five or even three minutes each.

श्री भूल चंद डागा (पाली) : सभापति जी, इस बिल के पास हो जाने से न हमारे अधिकार कम हो जायेंगे और न अदालतों के अधिकार कम हो जायेंगे । होगा यह कि जो लोग अदालतों में जाते हैं उनको सहूलियत हो जायेगी । न केशवानन्द भारती जैसे केस अदालतों में जा सकेंगे और न इसी प्रकार के दूसरे केस जा सकेंगे । उनके लिए दरवाजे बन्द होंगे । अदालतों में वे लोग जा सकेंगे जिनको कि जाना चाहिए । इसलिए यह ठीक नहीं है जो शमीम साहब कहते हैं कि अदालतों की पावर करटेल होती है इस बिल से । इससे अदालतों को यही अधिकार होगा जो कि उन्हें होना चाहिए । जो काम उन्हें करना चाहिये वह काम वह करें, जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए वह काम वह न करें ।

आज से बहुत साल पहले श्री सीतलवाड़ ने कहा था--

"There is no doubt that in the course of time the court itself will steer a course which will not deny the path and progress to the nation". I see no reason for creating a myth of confrontation between the Parliament and the Judiciary."

इस संशोधन विधेयक से एक बात होगी कि कोर्ट को कोई अधिकार नहीं होगा अवैध इन संशोधनों को घोषित करने का । पार्लियामेंट सुप्रीम होगी । इस तरह से कोर्टस अब इस मामले में नहीं जा सकेंगी और न गोलकनाथ जैसे लोग अब होंगे और न केशवनन्द भारतीय जैसे लोग होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकें और इसको चुनौती दे सकें । संविधान में पार्लियामेंट जो चाहे संशोधन कर सकेगी । अब न्याय देने का काम ही कोर्टस का रह जाएगा । कोर्टस अपने क्षेत्र में रहेंगी और हम अपने क्षेत्र में रहेंगे और काम करेंगे ।

एक बात मैं कहना चाहता हूं । संविधान को चाहे जितनी बार बदला जाए लेकिन जब तक गरीबों को राहत नहीं पहुंचेगी गांधी जी का जो सपना था वह साकार नहीं हो सकेगा । उनका कहना था कि मेरा स्वराज्य व० स्वराज्य है जिसमें गरीब लोगों को सब चीजें उपलब्ध होंगी और वे सुखी होंगे । इस वास्ते जब तक हम गरीबों के लिए साधन मुहैया नहीं करेंगे उनको ऊपर नहीं उठाएंगे गांधीजी का सपना साकार नहीं हो सकेगा । शोषण को हमको मिटाना होगा । तभी जो विषमता है वह मिट सकेगी और शान्ति स्थापित हो सकेगी । जब तक विषमता बनी रहेगी अशांति भी बनी रहेगी । कोई यह न समझें कि संविधान में इन संशोधनों को करके कोई जादू की छड़ी शासन के हाथ में आ जाएगी जिससे लोगों के कष्ट मिट जाएंगे । संविधान ने एक रास्ता दिखाया है, एक तरीका बताया है जिससे लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वे निदेशक सिद्धान्तों के रास्ते में आड़े नहीं आएंगे ।

एक बात मैं पूछना चाहता हूं । 2 वां एमेंडमेंट अपने पास करवाया । वह एक क्रान्तिकारी एमेंडमेंट था । उसमें आपने व्यवस्था की थी कि आप कोई भी पूंजी ले सकते हैं और उसके लिए आपको पूरा मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है । इसके पास होने के बाद भी आज क्या कारण हैं कि पूंजीपति और भी बड़े पूंजीपति बनते चले जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब होते चले जा रहे हैं । इस तरह से तो विषमता नहीं मिट सकेगी ।

जो लोग यह कहते हैं कि अदालतों की पावर्ज को कम कर दिया गया है इसको मैं नहीं मानता हूं । पार्लियामेंट की जो पावर्ज है वे पार्लियामेंट के लिए रख दी गई है और उनमें अदालतें अब हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगी जो कि अब तक वे करती रही हैं । मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक ने एक रास्ता खोला है ताकि हम आगे बढ़ सकें तेजी के साथ बढ़ सकें । मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा

[श्री मूल चन्द डागा]

से ज्यादा पावर्ज अब पंचायतों को दें । जो पावर्ज है इनका विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए केन्द्रीयकरण नहीं होना चाहिए । और केन्द्रीयकरण इन पावर्ज का होगा तो लोगों को स्वराज्य का आनन्द नहीं मिल सकेगा ।

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) : संविधान का जो संशोधन अब हो रहा हैं मैं समझता हूं कि इसके बाद भी संविधान के संशोधन होंगे क्योंकि ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ेगी आगे संस्कृति की जो रूपरेखा होगी उनमें यह अनिवार्य हो जाएगा । आगे चल कर अगर यह समझा गया कि अब भी उनके काम करने के रास्ते बन्द हो रहे है तो उनको खोलने के लिए संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे । ऐसा अब अगर किया जा रहा हैं तो इसमें कोई बड़ा आसमान नहीं गिर रहा हैं । लेकिन जैसे एक कहावत हैं कि बुरा वकील अच्छे से अच्छे मामले को भी बुरा बना देता हैं वही यहां भी हो रहा हैं । तमाम लोगों की स्पीचेज को मैंने सुना हैं । मुझे आश्चर्य होता हैं जब यह कहा जाता है कि कनफ्रंटेशन अदालतों और पार्लियामैंट में हैं । यह कनफ्रंटेशन की बात कहां से आपने लाकर खड़ी कर दी । आपने जब संविधान बनाया था उस वक्त उसमें आपने जो पावर्ज हाई कोर्टस और सुप्रीम कोर्ट को दी थी उनके अन्दर रह कर ही उन्होंने काम किया—

एक माननीय सदस्य : जी नहीं ।

श्री राम रतन शर्मा : मैं बता रहा हूं । आप सुनिये तो सही । मेरा निवेदन है कि अगर संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टस को पावर्ज न होती, संविधान को लैजिस्लेचर ने जिस तरह से रखा हैं; उस में अगर इन्टरप्रेटेशन की पावर्ज न होती तो वे क्यों इंटरप्रेट करतीं । इंटरप्रेट करने की पावर्ज अगर आपने उनको न दी होती तो क्यों वे इटरप्रेट करतीं । आज उन पावर्ज को आपने ले लिया हैं । अब वे नहीं करेंगी । संविधान में ही आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टस को बनाया हैं । वे जिस तरह से चाहेंगी उस तरह से अपना काम करेंगी । उनका क्षेत्र अलग हैं हमारा अलग हैं । जैसा अभी डागा जी कह रहे थे और मैं सहमत हूं कि संविधान का जो संशोधन करके आप कोई फायदा नहीं कर पा रहे हैं संशोधन करके आप यह न समझें कि आपने देश का कोई बहुत बड़ा कल्याण कर दिया हैं । जब तक वास्तविक काम नहीं होता तब तक ब्यूरोक्रेसी का जो काम करने का तरीका हैं एक्सीक्यूट करने का जो तरीका है वह नहीं बदलेगा उनका काम करने का रवैया नहीं बदलेगा काम नहीं होगा और आपकी सरकार बदनाम हो जाएगी ।

पचासों प्रोग्राम जो आपने 25 सूत्री के अन्दर चालू किये है कम से कम फैमिली प्लानिंग में तो आपके सरकारी कर्मचारी लगे हुए है उन्होंने सरकार को बदनाम करने का बीड़ा उठा रखा हैं । इस बात को अगर नहीं रोका गया तो सरकार बदनाम होगी । वैसे पूरी शक्ति के साथ हम संविधान में संशोधन करने के लिये अपनी सहमति देते है लेकिन जो त्रुटियां आपके कार्यक्रम में बताई है उनको दूर करने की कोशिश की जाये, वरना हम भी आपके साथ बदनाम होंगे आप तो डूबेंगे सनम हमको भी ले डूबेंगे ।

संविधान संशोधन अपनी जगह सही हैं। उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन जो उसके पीछे मंशा है जो आपने इसमें रखी हैं समाजवाद की वह तब तक पूरी नहीं होगी जब तक गरीबी नहीं हटती । और अगर इसी प्रकार क्रम चलता गया कि गरीब और गरीब होता गया और अमीर और अमीर होता गया तो इस संविधान संशोधन से कोई फायदा होने वाला नहीं हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का सम्पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूं ।

17.12 hrs.

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*]

श्री डी० बी० नायक (कनारा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपने विधि मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं । मंत्री जी ने हमारे परम मित्र श्री शंकर दयाल सिंह को उत्तर देते हुए यह कहा कि हिन्दी जो है यह एक राष्ट्र भाषा है । ऐसा अगर उन्होंने नहीं कहा होता तो मैं यह सवाल उठाता नहीं । मगर मैंने आर्टिकल 343 जो देखा उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि

> "The Official language of the Union shall be Hindi in Devanagri script".

तो स्लिप आफ टंग अगर हुई है तो बिल्कुल ठीक है इसको ठीक कर सकते हैं । मैं यह मानता हूं कि हिन्दी हमारे देश की अधिकार भाषा है और यूनियन की भाषा है क्योंकि हर एक राज्य के लिए ऐडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए आफिशियल लैंगुएजें बना सकते हैं । यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं एक हिन्दी का प्रेमी हूं इसीलिये यह बात कह रहा हूं । इसलिये जो संशय हमारे दिल में है इसको हमारे मंत्री जी दूर करेंगे ।

श्री शंकर दयाल सिंह (बेतिया) : सभापति जी, नायक साहब की हिन्दी अंग्रेजी से ज्यादा अच्छी है इसलिये वह बराबर हिन्दी में भाषण दें तो बहुत अच्छी बात होगी । तीन मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं ।

पहली बात यह कि संविधान का जो आपने संशोधन किया है 5 क्लाजेज का तो नई संविधान की प्रति आप इसी तरह से सदस्यों को दें जिस तरह से आपने पिछले दिनों सदस्यों को दी थी । हिन्दी और अंग्रेजी संविधान की प्रति माननीय मन्त्री जी ने दी थी जो डी-लक्स प्रति थी । लेकिन अब वह पुरानी पड़ गई है । इसलिये सभी सदस्यों को आप एक-एक हिन्दी और एक-एक अंग्रेजी की प्रति भेंट करें ।

दूसरी बात यह कि संविधान के बारे में जितने भी सदस्यों ने कहा उन्होंने यह बताया कि संविधान एक मर्यादा है एक निष्ठा है और एक सम्मान का प्रतीक है । तो भारत की जितनी भाषायें आठवें शेड्यूल में है भारत की जो 16 भाषाये आठवीं सूची में हैं उन सभी में संविधान का अनुवाद होना चाहिये और उन प्रान्तों में, उन क्षेत्रों में संविधान की प्रतियों को उपलब्ध कराया जाय जिससे देश की सामान्य जनता भी समझे कि संविधान क्या है उसमें क्या परिवर्तन हुए है और उनसे क्या लाभ हमको होने हैं ।

संविधान में मूल कर्त्तव्यों का एक चैप्टर जोड़ा गया है । मेरा सुझाव है कि उन कर्त्तव्यों को दैनिक समाचारपत्रों और सामिक पत्रों तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जावे ताकि जनता को पता चल सके कि उसके मूल कर्त्तव्य क्या क्या हैं ।

पिछले दिनों आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद प्रधान मन्त्री ने देश को कुछ नारे दिये जिनका आशय यह है कि दूर दृष्टि कड़ी मेहनत ईमानदारी अनुशासन से ही देश आगे बढ़ता है । उस के बाद बसों स्कूटरों और ट्रकों आदि पर और अन्य स्थानों पर ये नारे लिख गये । देश के जन-मानस पर इसका प्रभाव पड़ा और तब से अनुशासन नाम की चीज इस देश में देखने में आ रही है । इस लिए स्कूलों कालेजों तथा पुस्तकालयों में सार्वजनिक स्थानों पर और पार्लियामेंट के बाहर इन मूल कर्त्तव्यों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए ।

प्रस्तावना प्रीएम्बल में भी बहुत अच्छा परिवर्तन किया गया है । मन्त्री महोदय ने मेरे द्वारा सुझाया गया शब्द "प्रगतिशील" स्वीकार नहीं किया । अगर वह उस को स्वीकार कर लेते तो यह परिवर्तन और बढ़िया हो जाता, क्योंकि देश में छः महीने, साल के बाद एक बार फिर आंधी और तूफान का

[श्री शंकर दयाल सिंह]

सामना करना पड़ेगा । मन्त्री महोदय ने प्रस्तावना में "समाजवादी" शब्द जोड़ दिया है और "प्रगतिशील" नहीं जोड़ा । मगर बिना प्रगतिशीलता के समाजवाद क्या है और बिना समाजवाद के प्रगतिशीलता क्या है ? फिर भी जो परिवर्तन किये गये है वे बहुत अच्छे परिवर्तन है । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से प्रीएम्बल को अच्छे और आकर्षक ढग से छपवा कर चारो ओर वितरित किया जाना चाहिए, ताकि उसका प्रचार हो और उसके प्रति निष्ठा उत्पन्न हो ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं । इस संशोधन के द्वारा संविधान में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी संस्थाओं का जिक्र जोड दिया गया है । सम्बन्धित धारा पर विचार के समय हमने उसका जोरदार विरोध किया था ।

जो लोग सचमुच राष्ट्र-विरोधी या राष्ट्र-द्रोही है जिन्होंने गैर-जनतांत्रिक तरीकों से सरकार को पलटने की कोशिश की जिन्होंने सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा दिया उनको सरकार रफा-दफा किया करती जा रही है जबकि स्वयं सरकार की ओर से कहा गया है कि चूंकि कुछ लोग अभी भी गुप्त रूप से काम कर रहे है, इसलिए चुनाव कराना सम्भव नहीं है ।

लेकिन जो लोग सचमुच में जनतन्त्र के हिमायती है समाजवाद के प्रहरी हैं और धर्म-निरपेक्षता की नीति का समर्थन करते हैं, उन को सरकार जेल में डाल रही है । यह अच्छी बात है कि गृह मन्त्री इस समय सदन में मौजूद हैं । हमने बार-बार कहा है कि इस तरह की कार्यवाहियां हो रही हैं । मेरे अपने सूबे में कैमरा में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मीटिंग करने के सम्बन्ध में सीतामढ़ी में कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बरों पर डी० आई० आर० लगा दिया गया । आज बड़े बड़े जमींदार और दूसरे लोग खेत-मजदूरों को मजदूरी नहीं देते हैं । अगर मजदूर आन्दोलन करते हैं, तो उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जाती है । उन लोगों को नक्सलवादी कह कर बड़े पैमाने पर जेल में डाला जा रहा हैं, उनको पीटा जा रहा है और उन पर मुकदमे चलाये जा रहे है ।

परिवार-नियोजन के सिलसिले में सरकारी अधिकारी ग़लत काम करते हैं लोगों पर जुल्म करते हैं और गोली चलाते हैं । 13 सितम्बर को पटना में गोली से एक आदमी मारा गया । इसी तरह मुजफ्फरनगर में गोली चली और यू० पी० में तीस जगह गोली चली । प्रधान मन्त्री और स्वास्थ्य मन्त्री ने कहा है कि परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में कोई जोरो-जुल्म नही होगा, लेकिन फिर भी जोरो-जुल्म हो रहा हैं । उनको आप राष्ट्रद्रोही नही कहते । ये असल मे राष्ट्रद्रोही हैं । राष्ट्र द्रोहिता का अर्थ यह होता है कि जो आपकी नीति समाजवाद धर्म निरपेक्षता और जनतन्त्र को मजबूत करने की है, जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, वे तो देशभक्त है लेकिन जो उसके विरोधी हैं वे देशद्रोही है । बदकिस्मती यह हैं कि आपके अधिकारियों में काफी संख्या में देशद्रोही अधिकारी जमे हुए है जो उन लोगों को पकड़ रहे है जो देशभक्त है और जो सचमुच में देशद्रोहिता का काम कर रहे है उनको नहीं पकड़ा जा रहा है । थोड़ा इस तरफ आपका ध्यान जाए ।

बोनस के सवाल पर मंहगाई आदि के सवालों पर जो आन्दोलन हो रहा है उसको दबाने की कोशिश मत कीजिये ।

SHRI SHANKERRAO SAVANT (Kolaba): I strongly support the Amending Bill. This amending Bill has evoked by far the strongest controversy in the country. Ex-judges,

lawyers, public workers, social workers, trade unionists and politicians are divided into two warring camps The judiciary has come in a great deal of criticism They themselves are to be blamed for this because in Golaknath case, you please see that the judgment was given on 27th February when results of the 1967 general elections were just coming out and the results showed that the Congress was losing in a good many States It should not be surprising that the judgment should have been influenced by the election results that had started coming in a fortnight before the judgment was delivered Shri Motilal Setalwad has called it a political judgment The judgment states that a crawling revolution is in no way better than a violent revolution It starts open confrontation with the Parliament and the Parliament has to take up this challenge of the judiciary The confrontation with the Parliament was continued in Bank Nationalisation and Privy Purses cases Therefore we had done some temporary repairs by bringing forward 24th and 25th amendments but the heavy repairs to the edifice of Parliament s supremacy are done by this Amending Bill

I must thank the Law Minister for redrafting clause 55 The earlier clause was totally out of tune with the Amending Bill and also with the original provisions of the Constitution Parliament s supremacy has now been spelt in unmistakable words

We have put Fundamental duties in the statute But they are isolated Formerly Directive Principles were isolated like this The Fundamental Duties are nowhere related either to the Fundamental Rights or the Directive Principles It was necessary to state specifically that the Fundamental Rights and Directive Principles are subject to the Fundamental Duties I hope, this will be done by the judges who will hereafter be more in tune with the spirit of the amended Constitution otherwise Parliament will have to take up the challenge to say that the Fundamental duties are supreme and the Fundamental Rights are subservient to Fundamental Duties.

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) सभापति महोदय, मैं प्रधान मंत्री को तथा विधि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हू और सब सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूं कि इन को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम नया रूप कान्स्टीट्यूशन को देने जा रहे हैं। आप को याद होगा कि 16 मई 1946 को संविधान सभा अंग्रेजो ने बनाई थी और उस का क्या रूप रंग था वह भी आप को ज्ञात हैं। आज का रूप रंग कितना भिन्न हैं कि सिर्फ लोक सभा के ही नही बल्कि राज्य सभा और लोक सभा दोनो सदनों मे इस मे कोई शक नही, हम लोग जनता के नजदीक हैं तथा उनके प्रतिनिधि है और जनता के नजदीक होने के नाते आज हमने उन लोगों की भावना को मूर्ति रूप देने का काम किया है। थोडे से देश के इटलिजेशिया चिल्ला कर यह कह रहे है कि सरकार ने विधान को बदलने मे जल्दबाजी की है। मैं गोखले साहब से कहूगा कि कृपा कर के जो संशोधन हम पास कर रहे हैं उन के अनुसार अगर आप ने कायदे जल्दी नही बनाये तो हम उस विरोध का उत्तर न दे सकेंगे क्योंकि कायदा ही आप की जल्दी को प्रस्थापित कर सकेगा क्योकि जनसाधारण को उससे लाभ मिलने लगेगा। उदाहरण स्वरूप 14 (ए) ट्रिब्यूनल बनाने का संशोधन हैं। अगर आप ट्रिब्यूनल बनाये जाने का कायदा राज्य सरकारो से जल्दी नही बनवा सके तो आप की तथा हमारी हसी होगी तथा हम निरुत्तर हो जायेंगे। ऐसे ही एमर्जेंसी क्लाज के मातहत क्लाज 357 मे देश के किसी भी हिस्से में एमर्जेंसी घोषित की जा सकती हैं। आज नही तो कल हमे एमर्जेंसी को आहिस्ता आहिस्ता हटाना हैं लेकिन उस क्षेत्र मे इस कायदे को अवश्य रखना हैं जहा के लोग अराजकता पर उतरे हुए है। इस लिए इस कायदे को भी जल्दी से जल्दी पास करवा लेना चाहिये जिससे आपत्तकालीन स्थिति ज्यादातर हिस्सो से हटाई जा सके।

[डा० कैलाश]

इसी प्रकार क्लाज 9 में नये विधान के अनुसार मजदूरों का कारखाने या उद्योग में पार्टिसिपेशन होना चाहिये । यह ही नही बल्कि मालिक के रूप में अगर मजदूरों ने अनुभव या शिक्षा ठीक प्रकार ग्रहण की तो वे मालिक भी बन सकें लेकिन इसके लिए अगर अलग अलग प्रान्तों में इस प्रकार के कायदे जल्दी नही बनाये तो विरोधी पक्ष को उत्तर नही दे सकेंगे । हमने इसलिए नया विधान बनाने की कोशिश की थी कि हम कास्टीट्यूशन को बदल कर जनता की भावना ओं को पूरा कर सके जिससे उसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय जल्दी से जल्दी मिल सके ।

SHRI RANABAHADUR SINGH (Sidhi) I support the Constitution (Forty-second Amendment) Bill, because I feel that it is as a result of the inter-action of an unprecedented number of poor people on the fragile machinery of checks and balances, as we know democracy today I believe that in passing this amendment we are seeking to build a noble arch, which may be higher than the Parthenon, or the Statue of Liberty or the Tower of Westminster But I plead, and I finish in this last sentence let us put the coping stone of this noble arch by bringing panchayat raj into the Concurrent List, and thereby starting the processes by which we would ultimately give power to those for whom we are amending this Constitution.

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) चेयरमैन साहब यह बिल पास हो रहा है । मैं समझता हू जैसा कि ला मिनिस्टर साहब ने वायदा किया था मैं उनको फिर याद दिलाना चाहता हू ताकि उनकी जेहन मे रहे कि इस देश में माइनारिटीज के साथ खास तौर से मुस्लिम माइनारिटीज के साथ जो पिछले दिनों नाइन्साफी हुई हैं और जो अब भी जारी हैं उसको दूर करने के लिए मेहरबानी करके आप कानून बनाये । आप जानते है उन० साथ पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में अभी तक जो नाइंसाफी है उसको दूर करें । मेडिकल कालेजेज में इंजीनियरिंग कालेजेज में आर्टस कालेजेज में बी० एड० में और पब्लिसेज में उनके लिए कोटा मुकर्रर किया जाये ।

इसी तरह से उर्दू जबान के साथ करीब करीब हर स्टेट में नाइन्साफी हुई हैं । यह बात सिर्फ मैं नही कहता प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा कहती हैं । मेरी दरख्वास्त हैं कि कानूनी तौर पर उर्दू को हक दिया जाये ताकि अगर कोई स्टेट उसके साथ नाइन्साफी कर रही हो तो वह न कर सके । इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हू कि जिन लोगों ने हमसे कराये और फसादात कराये उनपर सख्त से सख्त कानून और सीसा लागू किया जाये ।

एक चीज की तरफ मैं और आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हू कि यह अजीब बात हैं कि कीमते लगातार बढती चली जा रही हैं । मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग एसेंशियल कमोडिटीज को गायब करे या उनको ब्लैकेबिल ना करे या कीमते बढाकर वसूल करे उनके खिलाफ सख्त कानून का इस्तेमाल किया जाये । जैसा कि शास्त्री जी कह रहे थे उन लोगों को एंटी नेशनल एक्टिविटीज में बन्द करना चाहिए । यह बहुत जरूरी है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जाये ।

आखीर मे मै कहना चाहता हू कि मेहरबानी करके डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मजबूती के साथ कदम उठाये और उसके बीच मे कोर्टस को आने न दिया जाये सुप्रीम कोर्ट को आने न दिया जाये । डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स के लिए आप मजबूती के साथ कदम उठाये ।

[شری اسحاق سنبھالی (کشن گنج) :

جو میں صاحب - یہ بل پاس ہو رہا ہے - میں سمجھتا ہوں جیسا کہ

لا منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا ۔ میں ان کو پھر یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں رہے کہ اس دیش میں مائنورٹیز کے ساتھ خاص طور سے مسلم مائنورٹیز کے ساتھ جو پہلے دنوں نا انصافی ہوئی ہے - جو اب بھی جاری ہے - اس کو دور کرنے کے لئے مہربانی کرکے آپ قانون بنائیں- آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی تک جو نا انصافی ہے اس کو دور کریں - میڈیکل کالجوں میں ، انجینئرنگ کالجوں میں ، آرٹس کالجوں میں، بی ایڈ میں اور سروسز میں ان کے لئے کوٹا مقرر کیا جائے -

اسی طرح سے اردو زبان کے ساتھ قریب قریب ہر سٹیٹ میں نا انصافی ہوئی ہے - یہ بات صرف میں نہیں کہتا، پرائم منسٹر بھی اسے کہتی ہے- میری درخواست ہے کہ قانونی طور پر اردو کو حق دیا جائے - تاکہ اگر کوئی سٹیٹ اس کے ساتھ نا انصافی کرے تو وہ نہ کر سکے - اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے حملے کرائے اور فسادات کرائے اس پر سخت سے سخت قانون اور میسا لاگو کیا جائے -

ایک چیز کی طرف اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے کہ قیمتیں لگاتار چڑھتی چلی جا رہی ہیں - میری آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ اسمگلنگ کا مول یعنی چیزوں کو غائب کریں یا ان کو اوپن اپیل نہ کریں جیسا کہ شاستری جی کہہ رہے تھے - ان لوگوں کو اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز میں بند کرنا چاہئے - یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھایا جائے -

آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کرکے ڈائریکٹیو پرنسپلز کو امپلیمینٹیشن کے لئے مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھائیں اور اس کے بیچ کورٹس کو آنے نہ دیا جائے - سپریم کورٹس کو آنے نہ دیا جائے - ڈائریکٹیو پرنسپلز کے لئے آپ مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھائیں -]

श्री शमीम अहमद शमीम (श्रीनगर) : सभापति जी, आपको याद होगा दो दिन पहले इस दन में मैंने यह बात कही थी कि संशोधन के मुताल्लिक मेरी राय क्या है मैं उसे महफूज रखता हूं लेकिन जब तक मल्क में आपातस्थिति की घोषणा चल रही है उस हालत में नार्मल हालात न होने की वजह से इस पर बहस नहीं हो सकती है। पिछले दो दिन के अन्दर इस मुल्क के होम मिनिस्टर साहब ने और ला मिनिस्टर गोखले साहब ने मेरी बात की ताईद की थी। पूरे 15 महीने हम सुनते रहे कि इमर्जेन्सी के क्या क्या मेरिट्स होते रहे, पूरे 15 महीने हमें बताया गया कि इससे मुल्क की क्या कायापलट हो गई लेकिन आज बताया जा रहा है कि जितने मेरिट्स हो रहे हैं वह सब हाथ से फिसलते जा रहे हैं और हालात अब खराब हैं। हालात खराब हैं

[श्री शमीम अहमद शमीम]

सलिए इमर्जेन्सी जारी रहेगी। लेकिन हालात इतने खराब नहीं हैं जितनी विधान में तब्दीलिया पैदा की जा रही हैं।

हम ने यह जहर इसलिये पिया था कि आईन में जितनी तबदीलियां आप करना चाहते है, कर लीजिये, क्योंकि आप ने यह मान लिया था कि पालियामेंन्ट सुप्रीम है और इन्तखाबात के जरिये एक नई पालियामेंन्ट आयेगी, उस ने अगर मुनासिब समझा तो आपने जो तरमीमें की है, या तो उन को अप होल्ड करेगी या रिजक्ट करेगी। लेकिन अब इस पूरी बहस से एक नई दलील निकाली जा रही है—अब इलैक्शन की वैलिडिटी का ही कवश्चन किया जा रहा है और क्वश्चन करने वाले कौन है जिन का इलैक्शन 6 साल पहले हुआ था। आज गोखले साहब और ब्रह्मानन्द रेडडी साहब क्या कहते हैं इन्तखाबात इम्पोटेन्ट नही है, हालाकि हम जीत सकते हैं। मैं इन से पूछना चाहता हूं अगर पहले इन्तखाबात नही हुए होते तो आप इस एवान में नजर नही आते। यह उन इन्तखाबात का ही नतीजा हैं, यह वही सैक्शन है, जिसने मि गोखले और मि० ब्रह्मानन्द रेड्डी को हक दिया है कि वे आज कह रहे है कि इन्तखाबात इम्पोटेन्ट नही है। मैं नही जानता प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वह जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री हैं—वह प्राइम मिनिस्टर होती या नही होती, लेकिन यह बात साफ है कि अगर इस मुल्क में पालियामेंन्ट्री निजाम नही होता हर पांच साल के बाद इन्तखाबात नही होते, तो

Mr. Gokhale would not have been there to say what he is saying today.

[شری شمیم احمد شمیم (شری نگر):

سبھا پتی جی آپ کو یاد ہوگا دو دن پہلے اس سدن میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ سنشودھن کے متعلق میری رائے کیا ہے- میں اسے محفوظ رکھتا ہوں- لیکن جب تک ملک میں ایمرجنسی کی کیفیت چل رہی ہے اس حالات میں نارمل حالت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر بحث نہیں ہو سکتی ہے- پچھلے دو دنوں کے اندر اس ملک کے ہوم منسٹر صاحب نے اور لا منسٹر گوکھلے صاحب نے میری بات کی تائید کی تھی- پورے ۱۵ مہینے ہم سنتے رہے کہ ایمرجنسی کے کیا کیا گینز ہوتے ہیں- پورے ۱۵ مہینے ہمیں بتایا گیا کہ اس سے ملک کی کیا کایا پلٹ ہو گئی- لیکن آج بتایا جا رہا ہے کہ جتنے گینز ہو رہے ہیں وہ سب ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں- اور حالات اب خراب ہیں- حالات خراب ہیں اس لئے ایمرجنسی جاری رہے گی- لیکن حالات اتنے خراب نہیں ہیں- جتنی ودھان میں تبدیلیاں پیدا کی جا رہی ہیں-

ہم نے یہ زہر اس لئے پیا تھا کہ آئین میں جتنی تبدیلیاں آپ کرنا چاہتے ہیں- کر لیجئے- کیونکہ آپ نے یہ مان لیا تھا کہ پارلیمینٹ سپریم ہے اور انتخابات کے ذریعے ایک نئی پارلیمینٹ آئیگی- اس نے اگر مناسب سمجھا تو آپ نے جو ترمیم کی ہیں- یا تو ان کو آپ ہولڈ کرینگی یا رجیکٹ کرے گی- لیکن اس پوری بحث سے ایک نئی دلیل

نکالی جا رہی ہے- اب الیکشن کی ویلیڈیٹی کا ہی کوسچن کیا جا رہا ہے- اور کوسچن کرنے والے کون ہیں- جن کا الیکشن ۶ سال پہلے ہوا تھا- آج گوکھلے صاحب اور برہمانند ریڈی صاحب کیا کہتے ہیں- انتخابات امپورٹینٹ نہیں ہیں- حالانکہ ہم جیت سکتے ہیں- میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر پہلے انتخابات نہیں ہوئے ہوتے تو آپ اس ایوان میں نظر نہیں آتے- یہ ان انتخابات کا ہی نتیجہ ہے- یہ وہی سکشن ہے جس نے گوکھلے اور برہمانند ریڈی کو حق دیا ہے کہ وہ آج کہہ رہے ہیں کہ انتخابات امپورٹینٹ نہیں ہیں- میں نہیں جانتا پرائم منسٹر کے بارے میں- وہ جواہر لال نہرو کی بیٹری ہیں- وہ پرائم منسٹر ہوتیں یا نہیں ہوتیں لیکن یہ بات صاف ہے کہ اگر اس ملک میں پارلیمنٹری نظام نہیں ہوتا- ہر پانچ سال کے بعد انتخابات نہیں ہوتے تو

Mr. Gokhale would not have been there to say what he is saying today.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I am on my legs. Nothing will go on record. You are breaking the rule. Please sit down.

SHRI S. A. SHAMIM:**

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली (टिहरी गढ़वाल): सभापति महोदय, आधे घन्टे में अब यह संविधान संशोधन पास हो जायगा-समाजवाद की तरफ यह एक बहुत बड़ा कदम है और इस का श्रेय हमारी प्रधान मंत्री जी और हमारे विधि मंत्री जी को है। मैं अपने विधि मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना भाषण हिन्दी भाषा में दीजिये, यदि आप को हिन्दी भाषा में उत्तर देने में कुछ कठिनाई आती हो, तो कम से कम कुछ वाक्य अपनी भाषा में ही कह दें, जिस भाषा में आप अपनी कास्टीट्युएन्सी में बोलते हैं।

सभापति महोदय, अब मैं माननीय विधि मंत्री जी का ध्यान एक खास विषय की ओर खींचना चाहता हूं। इस संसद के सात सदस्यों ने एक प्रतिवेदन उन को प्रस्तुत किया था, जिस में निवेदन किया गया था कि काश्मीर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इत्यादी जो 18 क्षेत्र है इन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाय, क्योंकि ये क्षेत्र आजादी मिलने के समय से पिछड़े इलाके रहे हैं और आज भी पिछड़े हुए इलाके है। आज जहां हम ने "सोशलिज्म" शब्द को अपने प्रिएम्बल में जोड़ा है, वहां इस क्षेत्रीय विषमता को कायम नहीं रखा जा सकता है। विकास के लिये आप की नीयत कितनी ही अच्छी हो, लेकिन जब तक क्षेत्रीय विषमता कायम रहेगी, जब तक आप संविधान में इस के लिये प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक यह विषमता नहीं मिट सकती। इस लिये मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप उत्तर देते समय हमारे उस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में बतलायें कि आप उन इलाकों को संवैधानिक सरक्षण देने जा रहे है या नहीं। मैं आप की सूचना के लिये बतलाना चाहता हूं कि इंग्लैंड और इटली में भी ऐसे पिछड़े इलाको के विकास के लिये संवैधानिक सरक्षण दिया गया है।

सभापति महोदय, आप ने संविधान के प्रियम्बल में 'समाजवाद' शब्द जोड़ा है, यह

**Not recorded.

[श्री पूर्णचन्द्र पैन्थूली]

ले जो चुनौती आनेवाले समय में पैदा होनेवाली है, इस में मिक्स्ड इकानमी कायम नहीं रह सकती है। गरीब और अमीर के भेद को अगर आप को मिटाना होगा, तो आर्टीकिल 311 में आप को परिवर्तन करना होगा क्योंकि जिस ब्यौरोक्रेसी के माध्यम से आप इस को कार्यान्वित करना चाहते हैं वह कोलोनियल ब्रिटिश एम्पायर की देन है और वह आज भी उसी ढर्रे पर काम कर रही है जैसे पहले करती थी।

इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने उत्तर में इन दो विषयों पर प्रकाश डालेंगे जिन का मैं ने जिक्र किया है और जिन में से एक पर्वतीय क्षेत्रों को संविधान में संरक्षण देने के बारे में है।

सभापति महोदय माननीय मंत्री जी।

SHRI H. R. GOKHALE Mr. Chairman, Sir....

श्री जांबुवंत धोटे (नागपुर) मैं प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता लेकिन मैं आप को बताना चाहता हूं कि मैं ने थर्ड रीडिंग पर बोलने के लिये सुबह ही नाम दे दिया था, लेकिन मुझे बुलाया नहीं गया कम से कम मेरा नाम पुकारना तो चाहिये था।

सभापति महोदय आप सदन में नहीं थे।

श्री जांबुवंत धोटे . मेरा नाम पुकारा नहीं गया। मैं तो शरू से ही बैठा हुआ हूं।

सभापति महोदय : मैंने मंत्री जी को बुला लिया है और उन्होंने बोलना प्रारम्भ कर दिया है। अब मैं आप का नाम कर नियम को नहीं तोड़ूंगा। अगर आप खड़े हो जाते, तो मैं आप को आवश्य बुला लेता। मैं ने वहां पर आप का नाम नहीं देखा और न आप खड़े हुए। अब मैं ने मंत्री जी को बुला लिया है और वे बोलना प्रारम्भ कर चुके है, इसलिये मैं नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता।

माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H R GOKHALE) Mr Chairman, Sir, for the last seven days, beginning from the 25th of October, we have had a very useful and instructive debate in which hon Members from both the sides have participated William Shakespeare said

> A good wine needs no bush but to good wines they put good bushes and good plays prove the better by good epilogues"

7 35 hrs

[MR SPEAKER *in the Chair*]

If I give that epilogue, I think I am in good company This is no time for acrimony We are at a moment when we are going to embark upon a very useful stage a very important stage in our nation s progress And as I said in my speech when I moved the Bill for consideration, when this House will pass the Bill, that will be our finest hour Prof S L Saksena unfortunately thinks that what the country will regard as the finest hour would be the darkest hour In this Constitution Amendment Bill we have taken many steps which only history will show are very vital and major steps and are very necessary for the progress of our country and for the prosperity of our people It is no doubt true that the most important thing which we are doing in this Bill—while I recognise that there are other important things too—is that we are putting beyond doubt, if there was any, the supremacy of Parliament in unequivocal terms When I spoke about the judiciary in my earlier speech, I did not have the intention

to denigrate individual judges In fact, I am the last person to think that our judges, our judiciary does not consist of eminent and learned people, and I am not prepared to agree with some that they lack in patriotism

All that I was trying to do was to emphasize that judges have to be in tune with the movement of the times and with the felt necessities of the times If that does not happen it is not that the people can be held back If that does not happen it is the judiciary which comes into dis repute It is to prevent that thing from happening that I emphasized and quite many of us emphasized in their speeches that we wanted to tell the judges understand what the people demand keep in tune with what the people want While nobody ever disputed the right of the judges to interpret the Constitution or the other laws within the sphere which is allotted to them what we undoubtedly disputed and will dispute is the fact that in that process of interpretation they will not succumb to the temptation of importing their own political philosophy for good or for bad That is why the Prime Minister in her speech specifically referred to one Chief Justice Chief Justice Subba Rao because that was one patent example where a high judicial office was misused for political purposes

A reference was made a little while ago by one of the speakers to Shri Motilal Setalvad who served as our Attorney General for a very long time While we know that he did not go along with us on all matters he said without hesitation soon after the judgment of the Chief Justice Subba Rao that that judgment was a political judgment soon after the appointment of the Chief Justice the judges who went out of the Supreme Court left no doubt that they had always political motivations the way they plunged into political activity the moment they left their chambers in the Supreme Court and addressed meetings organised by certain opposition parties There was no doubt left that these people while they were sitting on the Bench were motivated primarily by political considerations and not by considerations of performing their duty judiciously and in accordance with the oath which they had taken to act in conformity with the Constitution Therefore I would like to remove the doubt raised by some of my friends and most of them from the opposite side when they tell me that I had been attacking the judges opposing the judges and denigrating them and I seize this opportunity to make it clear that denigrating them was the farthest thing from my mind I would have been failing in my duty if I had not said what I had said because I was only communicating to them what the whole country felt and what the entire Parliament representing the people of this country felt in the last several years

We try to make good laws Of course, the cynics in the past have said that all laws are useless for good men do not need them and bad men are made no better by them But these things were said at a time when the whole emphasis was for making laws to deal with criminals to deal with the rights of individuals And the real purpose and function of legislation which was to deal with the needs of the society was not recognised That is why all the more, one feels sorry that even in the courts when questions arise as to interpretation—in fact my very good friend Prof Hiren Mukerjee referred to it in his speech—they still refer to Blackstone and Livingston I think this world has gone far beyond Blackstone and Livingston We have in recent years, political and legal philosophers who have gone very much ahead and we pected that—if at all they needed looking to these philosophies—they would have better served themselves and the country by looking to these philosophies which gave expositions of modern society

[Shri H. R. Gokhale]

We know the circumstances in which it became necessary to pass the Amendment relating to property rights, the Twenty-fifth Amendment. We had been faced with a situation where again a very rigid, and may I say, even a backward-looking view about compensation was taken; it was thought that the only way in which compensation could be given was the market value of the property where the benefit of such acquisition was for the society as a whole and not for any individual. A very interesting story, particularly referring to the approach to property right by countries like America, was given which I came across recently in the New Zealand Law Journal. It was, of course, not a story in history, but it was a jocular enunciation of how the American approach to property was.

Once to a newly emerging country, God himself went and asked the President of that country, "Your country is almost a jungle; could I help to lay out long roads throughout your country?" The President replied, "Yes; of course; I would very much like that; but surely I will have to pay some compensation". God said, "Of course, you have to". The President asked, "What is that?" 'The compensation', said God, "is 20,000 sacrifices a year". The President said, "Get out of my sight; because I have not seen anything more barbaric or barbarous than this". God said, "I cannot think why you are so upset; I assure you that this is the market price and is gladly paid by most civilised democracies, notably the United States".

It is now high time that we forgot those outmoded ideas which have been consigned to the limbo of the past and we looked at things in a new perspective. It is with that view in mind that we have to consider, when time comes, to make changes so that in a country which is wedded to the rule of law, the changes which we seek to make would be under the law and not outside the law. It is in that spirit that we seek to change law—to be in tune with the demands of the society, with the demands of the people at large. All these things have been said ever since the Constituent Assembly discussed framing of the Constitution, when Jawaharlal Nehru said;

> "A constitution if it is out of touch with the people's life, aims and aspirations, becomes rather empty; if it falls below those aims, it drags the people down. It should be something higher to keep people's eyes and minds up to a certain high mark."

That is why when we make the constitution, particularly, we keep a certain high standard, and while everyone of us is not a fool to think that by including 'socialism' in the Preamble, we are going to usher in socialism in the fullest sense tomorrow, it is this high ideal that we are putting before ourselves and it is in the implementation of this high ideal that we have taken the vow to do all things in law and outside and more outside than in law, to see that the conditions of our country change and our people prosper.

We have for the first time given the Directive Principles rightful place of supremacy over Fundamental Rights. We have for the first time enumerated a set of 10 duties for the citizen and we have for the first time in a way, which will provide for making our judiciary function within the limits in which it was expected to function, made changes regarding the jurisdiction, the powers and the functions of the court.

There are other changes but broadly these major changes are changes in the nature of giving us a framework for the future so that within this frame-work, all of us, those belonging to the legislature, those belonging to the executive and those belonging to the judiciary should function.

In this reply while the debate has been of a high order and our minds ought to be rivetted not on petty matters or on small technicalities, it is better that we concentrate on the higher impulses, the ideals on the basis of which these changes are proposed to be made in the Constitution

Even in this debate when the various clauses were discussed I had occasion to refer to all the doubts and objections which were raised by hon Members and I do not think that this is the right time to repeat all those objections and give answers to them which have been given more than once by me and by hon Members who had participated in the debate

It was unfortunate that even in this historic task of changing the constitution some people from the Opposition Parties have chosen to turn their backs and evade responsibility and some of them have come—I am sure not all of them—but I am referring to those who have not come Some of those who have come spoke, and even in their speeches which I have heard carefully in the same vein that I have heard the speeches of my friends on this side, I was very sorry to note that there was one tone, one refrain, a tendency to run away from facts, a tendency to be blind to realities, a tendency to be cynical about what we need and what the country needs, but I must say that I was not surprised looking at what is happening in the last few days here and in the platforms outside where a congolomerate of people who have otherwise nothing in common come together on the sole common platform of opposing the constitutional amendments and the policies of the Government

Perhaps the description given by Shakespeare when he refers to strange bed-fellows is appropriate here and perhaps still more appropriate is the improvement made by George Bernard Shaw when he said not strange, but convenient bed-fellows, because, I could see nothing in common with their approach to matters of politics or economics otherwise excepting a coming together to say the same thing without giving any argument which can appeal to any rational mind as to why and on what basis the Constitutional amendments are undesirable

As against that, we have other opposition parties who have participated in the discussion I know that they have supported the major parts of the amendment while they have disagreed with others But that is a thing which we can understand. And it may be that while we have a debate, we need not and we cannot have everybody to agree with everything that we say

But, so long as we are here, in such matters when what we are doing is the right thing, we should not hesitate to do that right thing merely because it is opposed or merely because some people do not agree with what we say

Even in this discussion we have observed that as a result of certain suggestions made by hon Members some changes were made which would show that the Government had been responsive to the views expressed by hon Members, in the course of these discussions

It is just not possible to make changes in every respect But I can assure you that everyone of these suggestions made we considered by the Government and after due consideration it was thought that only some of them need be accepted and incorporated in the Bill That is the way in which the whole discussion, the whole debate, on the Constitution Amendment Bill has gone on.

[Shri H. R. Gokhale]

Mr. Mavalankar who spoke today and earlier said that there is a qualitative change made by this Constitution Amendment. Well, I am happy that there is a qualitative change. In fact, it is to make a qualitative change that we have brought this amendment. But, I can understand Mr. Mavalankar telling me in what respects it lacks in that quality which he regards as appropriate That he did not tell us. But, what is there to be shy in saying that we have brought the changes which do make a qualitative change in the Constitution? In fact, by this Constitution Amendment Bill in our Republic, we are pouring into the contents of the Constitution, into its concepts, a new force, a new approach, to all problems and in that sense we are making a very qualitative change in the Constitution, and it is a good and heartening thing.

18.00 hrs.

I do not agree with an hon. Member who spoke just now that on this Constitution Amendment Bill there is a national controversy. In fact, there is none. Of course, there may be controversy in some quarters, as controversy indeed there is bound to be, when matters like these are taken into consideration.

But it is good to see that the amendments proposed have been accepted by and large as a matter of general consensus outside and in this House; and in fact, the criticism was why you are bringing them now, you should have brought this much earlier.

Now, it is in this context that I commend that the Bill be passed. And, as I said earlier, this is not the moment when we should enter into small matters, petty matters, or small technical matters which we might have already dealt with in the earlier part of the discussion.

Sir, I commend this Bill for being passed by the House.

MR. SPEAKER: Let the lobbies be cleared. I shall now put the Motion to the vote of the House.

The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as amended, be passed".

The Lok Sabha divided:

AYES

Division No. 37] **[18.02 hrs.**

Achal Singh, Shri
Aga, Shri Syed Ahmed
Agrawal, Shri Shrikrishna
Ahirwar, Shri Nathu Ram
Alagesan, Shri O. V.
Ambesh, Shri
Anand Singh, Shri
Ankineedu, Shri Maganti
Ansari, Shri Ziaur Rahman
Appalanaidu, Shri
Arvind Netam, Shri
Austin, Dr Henry
Awdhesh Chandra Singh, Shri
Azad, Shri Bhagwat Jha
Aziz Imam, Shri
Babunath Singh, Shri
Bajpai, Shri Vidya Dhar
Balakrishnaiah, Shri T
Banamali Babu, Shri
Banera, Shri Hamendra Singh
Banerjee, Shri S. M.
Banerjee, Shrimati Mukul
Barman, Shri R. N.
Barua, Shri Bedabrata
Barupal, Shri Panna Lal
Basappa, Shri K.
Basumatari, Shri D.
Besra, Shri S. C.
Bhagat, Shri H. K. L.

Bhargava, Shri Basheshwar Nath
Bhargavi Thankappan, Shrimati
Bhatia, Shri Raghunandan Lal
Bhattacharyyia, Shri Chapalendu
Bhaura, Shri B S
Bheeshmadev, Shri M
Bhuvarahan, Shri G
Bist, Shri Narendra Singh
Brahmanandji Shri Swami
Brij Raj Singh—Kotah, Shri
Buta Singh Shri
Chakleshwar Singh, Shri
Chandra Gowda Shri D B
Chandra Sekhar Singh, Shri
Chandrakar Shri Chandulal
Chandrappan, Shri C K
Chandrashekharappa Veerabasappa, Shri T V
Chandrika Prasad, Shri
Chaturvedi, Shri Rohan Lal
Chaudhari, Shri Amarsinh
Chaudhary Shri Nitiraj Singh
Chavan, Shrimati Premalabai
Chavan, Shri Yeshwantrao
Chellachami Shri A M
Chhotey Lal Shri
Chhutten Lal Shri
Chikkalingaiah Shri K
Choudhary, Shri B E
Daga Shri M C
Dalbir Singh, Shri
Dalip Singh Shri
Darbara Singh, Shri
Das, Shri Anadi Charan
Das, Shri Dharnidhar
Dasappa, Shri Tulsidas
Daschowdhury, Shri B K
Deo, Shri P K
Deo, Shri R R. Singh
Deo, Shri S N Singh
Desai, Shri D D
Deshmukh, Shri K G
Deshpande, Shrimati Roza
Dhamankar, Shri
Dharamgaj Singh, Shri
Dhillon, Dr G S
Dhusia, Shri Anant Prasad
Dinesh Singh, Shri
Dixit, Shri G C
Dixit, Shri Jagdish Chandra
Doda Shri Hiralal
Dube Shri J P
Dumada Shri L K
Dwivedi Shri Nageshwar
Engti, Shri Biren
Gaekwad Shri Fatesinghrao
Gandhi Shrimati Indira
Ganesh Shri K R
Ganga Devi, Shrimati
Gangadeb Shri P
Gautam Shri C D
Gavit Shri T H
George Shri A C.
Ghosh Shri P K
Gill Shri Mohinder Singh
Giri Shri V Shanker
Godara Shri Mani Ram
Godfrey Shrimati M
Gogoi Shri Tarun
Gohain Shri C C
Gokhale Shri H R
Gomango Shri Giridhar
Gopal Shri K
Goswami Shri Dinesh Chandra
Gotkhinde Shri Annasaheb
Gowda Shri Pampan
Gupta Shri Indrajit
Hansda Shri Subodh
Hanumanthaiya Shri K
Hari Kishore Singh Shri
Hari Singh Shri
Hashim, Shri M M
Ishaque, Shri A K M
Jadeja Shri D P
Jaffer Sharief Shri C K
Jagjivan Ram, Shri
Jamilurrahman, Shri Md.
Janardhanan, Shri C

Jeyalakshmi, Shrimati V.
Jha, Shri Bhogendra
Jha, Shri Chiranjib
Jharkhande Rai, Shri
Jhunjhunwala, Shri Bishwanath
Jitendra Prasad, Shri
Joshi, Shri Popatlal M.
Joshi, Shrimati Subhadra
Kadam, Shri Dattajirao
Kadam, Shri J. G.
Kadannappalli, Shri Ramachandran
Kader, Shri S. A.
Kahandole, Shri Z. M.
Kailas, Dr.
Kakodkar, Shri Purushottam
Kakoti, Shri Robin
Kalingarayar, Shri Mohanraj
Kalyanasundaram, Shri M.
Kamakshaiah, Shri D.
Kamala Prasad, Shri
Kamble, Shri N. S.
Kamble, Shri T. D.
Kapur, Shri Sat Pal
Karan Singh, Dr.
Kathamuthu, Shri M.
Kaul, Shrimati Sheila
Kavde, Shri B. R.
Kedar Nath Singh, Shri
Khadilkar, Shri R. K.
Khan, Shri I. H.
Kinder Lal, Shri
Kisku, Shri A. K.
Kotoki, Shri Liladhar
Kotrashetti, Shri A. K.
Koya, Shri C. H. Mohamed
Krishna Kumari, Shrimati
Krishnan, Shri G. Y.
Krishnan, Shrimati Parvathi
Krishnappa, Shri M. V.
Kulkarni, Shri Raja
Kureel, Shri B. N.
Kushok Bakula, Shri
Lakkappa, Shri K.
Lakshminarayanan, Shri M. R.
Lambodar Baliyar, Shri
Laskar, Shri Nihar
Lutfal Haque, Shri
'Madhukar', Shri K. M.
Mahajan, Shri Vikram
Mahajan, Shri Y. S.
Maharaj Singh, Shri
Mahishi, Dr. Sarojini
Majhi, Shri Gajadhar
Majhi, Shri Kumar
Malaviya, Shri K. D.
Malhotra, Shri Inder J.
Mallanna, Shri K.
Mallikarjun, Shri
Mandal, Shri Jagdish Narain
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Manhar, Shri Bhagatram
Manjhi, Shri Bhola
Maurya, Shri B. P.
Mehta, Dr. Mahipatray
Melkote, Dr. G. S.
Mirdha, Shri Nathu Ram
Mishra, Shri Bibhuti
Mishra, Shri G. S.
Mishra, Shri Jagannath
Modi, Shri Shrikishan
Mohammad Yusuf, Shri
Mohan Swarup, Shri
Mohapatra, Shri Shyam Sunder
Mohsin, Shri F. H.
Muhammed Sheriff, Shri
Mukerjee, Shri H N.
Munsi, Shri Priya Ranjan Das
Murmu, Shri Yogesh Chandra
Murthy, Shri B S.
Muruganantham, Shri S. A.
Nahata, Shri Amrit
Naik, Shri B. V.
Nair, Shri Sreekantan
Nanda, Shri G. L.
Nayak, Shri Baksi
Nimbalkar, Shri
Oraon, Shri Kartik
Oraon, Shri Tuna

Pahadia, Shri Jagannath
Painuli, Shri Paripoornanand
Palodkar, Shri Manikrao
Panda, Shri D. K.
Pandey, Shri Damodar
Pandey, Shri Narsingh Narain
Pandey, Shri R. S.
Pandey, Shri Sarjoo
Pandey, Shri Sudhakar
Pandit, Shri S. T.
Panigrahi, Shri Chintamani
Pant, Shri K. C.
Paokai Haokip, Shri
Parashar, Prof. Narain Chand
Parikh, Shri Rasiklal
Parthasarathy, Shri P.
Paswan, Shri Ram Bhagat
Patel, Shri Arvind M.
Patel, Shri Natwarlal
Patel, Shri Prabhudas
Patil, Shri Anantrao
Patil, Shri C. A.
Patil, Shri E. V. Vikhe
Patil, Shri Krishnarao
Patil, Shri S. B.
Patil, Shri T. A.
Patnaik, Shri Banamali
Patnaik, Shri J. B.
Peje, Shri S. L.
Pradhan, Shri Dhan Shah
Pradhani, Shri K.
Purty, Shri M. S.
Qureshi, Shri Mohd Shafi
Raghu Ramaiah, Shri K.
Rai, Shri S. K.
Rai, Shrimati Sahodrabai
Raj Bahadur, Shri
Rajdeo Singh, Shri
Raju, Shri P. V. G.
Ram, Shri Tulmohan
Ram Dayal, Shri
Ram Prakash, Shri
Ram Sewak, Ch.
Ram Singh Bhai, Shri
Ram Surat Prasad, Shri
Ram Swarup, Shri
Ramji Ram, Shri
Ramshekhar Prasad Singh, Shri
Ranabahadur Singh, Shri
Rao, Shrimati B. Radhabai A.
Rao, Shri J. Rameshwar
Rao, Shri Jagannath
Rao, Dr. K. L.
Rao, Shri K. Narayana
Rao, Shri M. S. Sanjeevi
Rao, Shri M. Satyanarayan
Rao, Shri Nageswara
Rao, Shri P. Ankineedu Prasada
Rao, Shri Pattabhi Rama
Rao, Shri Rajagopala
Rao, Dr. V. K. R. Varadaraja
Rathia, Shri Umed Singh
Raut, Shri Bhola
Ravi, Shri Vayalar
Ray, Shrimati Maya
Reddy, Shri K. Kodanda Rami
Reddy, Shri K. Ramakrishna
Reddy, Shri M. Ram Gopal
Reddy, Shri P. Bayapa
Reddy, Shri P. Ganga
Reddy, Shri P. V.
Reddy, Shri Sidram
Reddy, Shri Y. Eswara
Richhariya, Dr. Govind Das
Rohatgi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Bishwanath
Rudra Pratap Singh, Dr.
Saini, Shri Mulki Raj
Salve, Shri N. K. P.
Samanta, Shri S. C.
Sambhali, Shri Ishaqua
Sanghi, Shri N. K.
Sangliana, Shri
Sankata Prasad, Dr.
Sant Bux Singh, Shri
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Satish Chandra, Shri
Satpathy, Shri Devendra

Satyanarayana, Shri B.
Savant, Shri Shankerrao
Savitri Shayam, Shrimati
Sayeed, Shri P. M.
Scindia, Shri Madhavrao
Sen, Dr. Ranen
Sethi, Shri Arjun
Shafee, Shri A.
Shafquat Jung, Shri
Shahnawaz Khan, Shri
Shilani, Shri Chandra
Shambhu Nath, Shri
Shankar Dayal Singh, Shri
Shankaranand, Shri B.
Sharma, Shri A. P.
Sharma, Dr. H. P.
Sharma, Shri Madhoram
Sharma, Shri Nawal Kishore
Sharma, Shri R. R.
Sharma, Dr. Shanker Dayal
Shashi Bhushan, Shri
Shastri, Shri Biswanarayan
Shastri, Shri Raja Ram
Shastri, Shri Ramavatar
Shastri, Shri Sheopujan
Shenoy, Shri P. R.
Shetty, Shri K. K.
Shinde, Shri Annasaheb P.
Shivappa, Shri N.
Shivnath Singh, Shri
Shukla, Shri B. R.
Siddayya, Shri S. M.
Siddheshwar Prasad, Prof.
Singh, Shri Vishwanath Pratap
Sinha, Shri Dharam Bir
Sinha, Shri Nawal Kishore
Sinha, Shri R. K.
Sohan Lal, Shri T.
Sokhi, Sardar Swaran Singh
Solanki, Shri Pravinsinh
Stephen, Shri C. M.
Subramaniam, Shri C.
Sudarsanam, Shri M.
Surendra Pal Singh, Shri
Suryanarayana, Shri K.
Swaminathan, Shri R. V.
Swamy, Shri Sidrameshwar
Swaran Singh, Shri
Tarodekar, Shri V. B.
Tayyab Hussain, Shri
Tewari, Shri Shankar
Thakre, Shri S. B.
Thakur, Shri Krishnarao
Tiwari, Shri Chandra Bhal Mani
Tiwari, Shri R. G.
Tiwary, Shri D. N.
Tombi Singh, Shri N.
Tula Ram, Shri
Tulsiram, Shri V.
Uikey, Shri M. G.
Ulaganambi, Shri R. P.
Vekaria, Shri
Venkatasubbaiah, Shri P.
Venkatswamy, Shri G.
Verma, Shri Balgovind
Verma, Shri Sukhdeo Prasad
Vidyalankar, Shri Amarnath
Vijay Pal Singh, Shri
Vikal, Shri Ram Chandra
Yadav, Shri Chandrajit
Yadav, Shri D. P.
Yadav, Shri Karan Singh
Yadav, Shri N. P.
Yadav, Shri R. P.

NOES

Dhote, Shri Jambuwant
Mavalankar, Shri P. G.
Ram Hedaoo, Shri
Saksena, Prof. S. L.

MR. SPEAKER: The result* of the division is: Ayes: 366; Noes: 4.

The motion is carried by a majority of the total membership of the House

*Sarvashri Pratap Singh Negi and Genda Singh also recorded their votes for AYES.

and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting. The Bill, as amended, is passed by the requisite majority in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution.

The motion was adopted. ..

18.06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 3, 1976/Kartika 12, 1898 (Saka).

GMGIPND—Moon—2074 L. S.—9-11-1976—